बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 214

आसान होंगे मुक्त व्यापार समझौते!

बीते कुछ वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने की समझदारी को लेकर कई तरह की शंका प्रकट की गई हैं। अब खबर है कि वाणिज्य विभाग एफटीए पर वार्ताओं को लेकर 'नए दिशानिर्देशों' पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगेगा। ऐसी बातचीत के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाओं (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी) को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ एक बैठक के बाद यह यह बात सामने आई है। माना जा सकता है कि यह इस नजरिये को दिखाता है कि पिछले कई हस्ताक्षरित एफटीए में भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है क्योंकि साझेदार देशों से होने वाले निर्यात में कई बार भारत के निर्यात से अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। एफटीए की प्रक्रिया की समीक्षा स्वागतयोग्य है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इन चर्चाओं के बाद तैयार किए जाने वाले एसओपी भारत को और अधिक संरक्षणवादी नहीं बनाएंगे।

बीते कुछ वर्षों के दौरान भारत ने कुछ रणनीतिक महत्त्व के साझेदारों मसलन यूनाइटेड किंगडम (यूके) और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ चर्चा को आगे बढ़ाया है जबकि संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक व्यापक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ अर्ली हार्वेस्ट डील हुई है। ऐसी डील एफटीए के पहले की जाती हैं जिनके तहत दो देशों के बीच शुल्क उदार बनाने के लिए उत्पादों की पहचान की जाती है। हालांकि इस अग्रगामी कदम के बीच कुछ हिचकिचाहटों को छिपाया गया। उदाहरण के लिए, यह माना गया था कि कुछ वर्ष पहले हुआ भारत-ऑस्ट्रेलिया समझौता, आरंभिक से एक व्यापक समझौते में बदल जाएगा लेकिन दोनों साझेदारों के बीच इसे आगे ले जाने के लिए कोई खास उत्साह नहीं नजर आता। यूके और ईयू के साथ भी उम्मीद के मुताबिक प्रगति नहीं हुई है। अगर नए एसओपी इस दिक्कत को दूर कर सके तो उन्हें स्वागतयोग्य सुधार माना जा सकता है। कुछ मामलों में धीमी प्रगति की एक वजह पिछली चर्चाओं की संस्थागत स्मृति की कमी भी है। ईयू के साथ ऐसा खासतौर पर हो सकता है क्योंकि उसके साथ हमारी प्रक्रिया एक दशक से रुक-रुक कर चल रही है। यह एक खास बाधा है जिससे एसओपी निजात पाने की कोशिश करेगा। यह एक आशावादी संकेत है।

यह राजनीतिक निर्णय लेने वालों के लिए भी एक अवसर है कि वे अधिकारियों को देश के बढ़ते कारोबारी संपर्कों के महत्त्व के बारे में बताएं। एसओपी में यह क्षमता है कि वह अधिकारियों को कुछ राहत प्रदान करे और बातचीत के दौरान कुछ रियायतों का अवसर दे। बहरहाल इसके साथ इस बात के व्यापक प्रयास किए जाने चाहिए कि भारतीय निर्यातकों को भी एफटीए से उतना ही लाभ हो जितना कि भारतीय उपभोक्ताओं को। उद्योग जगत को यह दिखाने की आवश्यकता है कि एफटीए की बदौलत खुले नए बाजारों का लाभ किस प्रकार उठाया जाए। गैर टैरिफ अवरोध उन व्यापारिक संबंधों में अभी भी मौजूद हो सकते हैं जहां टैरिफ कम कर दिए गए हैं। इस चिंता को हल करने के लिए ऐसी गैर टैरिफ बाधाओं का एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए। इसे द्विपक्षीय ढंग से किया जा सकता है।

नए दौर के एफटीए में पर्यावरण और श्रम नियमन संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं। वाणिज्य मंत्रालय के वार्ताकार स्वाभाविक तौर पर इन क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं जो अन्य मंत्रालयों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी सुविधा और अधिकार प्रदान करने चाहिए ताकि इन मसलों पर भी समझौतों पर पहुंचा जा सके। आखिर में, अगर संस्थागत स्मृति ही मानक है तो सरकार को बाहरी विशेषज्ञों पर भी विचार करना चाहिए। वाणिज्य मंत्रालय के पास खुद के थिंक टैंक हैं जिनका उपयोग मौजूदा वार्ताओं की मदद के लिए विशेष सेल बनाने में किया जा सकता है। भले ही विभिन्न विभागों के अधिकारी आगे बढ़ गए हों। कुल मिलाकर मंशा होनी चाहिए वैश्विक व्यापार में उभरते अवसरों का लाभ लेना। आंशिक तौर पर ऐसा बदलते वैश्विक आर्थिक और राजनैतिक माहौल के कारण भी होना चाहिए।

विनिमय दर में अनिश्चितता का अर्थव्यवस्था से ताल्लुक

कुछ लोगों की नजर में मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए बाधा है मगर हकीकत में यह आर्थिक लचीलेपन का एक महत्त्वपूर्ण तत्व है। बता रहे हैं के पी कृष्णन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल में सार्वजनिक तौर पर सीना चौड़ा कर पिछले कुछ वर्षों में मुद्रा विनिमय दरों में स्थिरता का जिक्र किया। क्या यह वाकई ऐसी उपलब्धि है जिस पर आरबीआई इतरा सकता है? कंप्यूटर क्रांति की भाषा में पूछें तो यह खुबी है या खामी? आइए, पहले तथ्यों पर विचार करते हैं।

सबसे ऊपर दर्शाए गए ग्राफ (रुपया-डॉलर की चाल) में एक सपाट जगह दिखती है जहां अमेरिकी डॉलर और रुपये की विनिमय दर जाकर लगभग ठहर जाती है यानी इसमें हलचल कम हो जाती है। सबसे नीचे दर्शाए ग्राफ में दीर्घकालिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण दर्शाया गया है। आखिरी बार 2006 में यह सपाट जगह देखी गई थी। एक लंबी अवधि तक विनिमय दर सरकारी नियंत्रण में रखने के बाद भारत ने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बड़ा कदम उठाया। अब एक बार फिर अर्थव्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण मूल्य अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण की जद में आ गया है।

वर्ष 1991-2011 के बीच की अवधि के नीति निर्धारकों ने सरकार नियंत्रित दर से बाजार निर्धारित दर की तरफ कदम क्यों बढ़ाया जो हरेक दिन बदलती रहती है? इसका पहला पहलू बाजार अर्थव्यवस्था का महज बुनियादी तर्क है। बाजार में प्रत्येक दिन आपूर्ति एवं मांग के बीच खेल चलता रहता है जिससे मूल्य निर्धारण होता रहता है। मूल्य नीतिगत निर्णयों के केंद्र में नहीं होता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण पर विचार करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बाजार में कुछ कारणवश पेंसिल की कीमत बढ़ जाती है।

अल्प अवधि में पेंसिल की कीमत बढ़ जाएंगी। बाजार में इसकी उपलब्धता यानी आपूर्ति एवं मांग में संतुलन स्थापित करने के लिए यह स्थिति बनती है। मध्यम से दीर्घ अवधि में आपूर्ति बढ़ेगी जिससे इसकी कीमत शुरुआती स्तर और बढ़ी कीमत के बीच कहीं जाकर स्थिर हो जाएगी। अनिश्चितता और मूल्य में उतार-चढ़ाव मूल्य ढांचे से जुड़ी खास बात होती है। कोई ऐसा ठोस जरिया नहीं है जिसका सहारा लेकर कोई अधिकारी वाजिब कीमत निर्धारित कर पाए। केवल बाजार यह कार्य कर सकता है। बड़े पैमाने पर पेंसिल का इस्तेमाल करने वाला, उदाहरण के लिए, कोई आर्ट स्टूडियो इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव पसंद नहीं करेगा। ऐसे स्टूडियो जोखिम कम करने के लिए नियत मूल्य का अनुबंध कर सकते हैं। इस अनुबंध के बाद उनके लिए कीमतों में उतार-चढ़ाव का जोखिम कम हो जाएगा। हां, इसके लिए उन्हें थोड़ी अधिक कीमत (प्रीमियम) का भुगतान करना होगा।

भारतीय समाजवाद की यह धारणा थी कि कीमतों में उतार-चढ़ाव अच्छी बात नहीं है, इसलिए इसे स्थिर रखने के लिए सरकार को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिकारी यह तय किया करते थे कि पेंसिल की कीमत क्या होगी। वे उपरोक्त उदाहरण में पेंसिल को 'आवश्यक वस्तु' घोषित कर देते थे और कहते थे कि कानूनन इसकी कीमतों में 'उतार-चढ़ाव' बरदाश्त नहीं की जा सकती। जो लोग पेंसिल की निर्धारित कीमत से ऊपर खरीद और बिक्री करते थे वे कानून का उल्लंघन करते थे और दंड के भागी बन जाते थे। कानून कभी-कभी इसे अपराध घोषित कर देता है (जैसा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रावधान) और ऐसे लोगों को उनके 'अपराधों' के लिए जेल में भी डाला जा सकता है।

एक सीमा तक ही अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाले लोगों की नजर में उनकी नजर में यह तरीका ठीक प्रतीत हो सकता है क्योंकि इससे अनिश्चितता कम होती है और दुनिया सभी लोगों के सहूलियत बढ़ जाती है। यह एक छद्म लाभ है क्योंकि अर्थव्यवस्था को संगठित करने का मुख्य तरीका कीमतों में उतार-चढ़ाव से जुड़ा है। दुनिया बदलेगी, आपूर्तिकर्ता औररर मांगकर्ताओं को बदलना होगा और मूल्य प्रणाली सभी समायोजनों में तालमेल बैठा लेगी। अर्थव्यवस्था की एक खास बात यह है कि इसमें कई भागीदार होते हैं। ये लोग कीमतों पर विचार करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया उजागर करते हैं। उन सभी प्रतिक्रियाओं पर संशोधित मूल्य के निर्धारण के समय विचार किया जाता है।

यह तर्क मुद्रा विनिमय दर के साथ भी उतनी ही लागू होता है। अच्छे समय में भारत में विदेश से अधिक पूंजी आती है और उस स्थिति में रुपया का मूल्य बढ़ना चाहिए। प्रतिकूल समय में भारत में कम पूंजी आती है और इस स्थिति में रुपया कमजोर होना चाहिए। रुपया कमजोर होना निर्यातकों एवं वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार में जुड़ी कंपनियों के लिए अच्छी बात है।

भारत में नीति निर्धारण कई क्षेत्रों जैसे सीमेंट, इस्पात और विनिमय दर आदि में प्रभावी नहीं रह गया है। यानी ये खंड मूल्य नियंत्रण की जद से बाहर निकल गए हैं। इसे लेकर कम से कम पांच स्पष्ट तर्क हैं कि विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होना चाहिए न कि नीति निर्धारकों द्वारा।

1. लचीली विनिमय दर स्वाभाविक रूप से झटकों को बरदाश्त कर लेती है। अच्छे समय में रुपया मजबूत होता है और प्रतिकूल समय में इसमें कमजोरी दिखती है। रुपया कमजोर होता है तो अर्थव्यवस्था दबाव में आ जाती है और रुपया चढ़ने पर ठीक इसका उल्टा होता है। यह प्रक्रिया वृहद आर्थिक हालात को स्थिर बनाए रखती है।

2. एक अधिकारी सटीक विनिमय दर कैसे निर्धारित कर सकता है? यह विश्लेषणात्मक और राजनीतिक रूप से एक कठिन प्रश्न हो सकता है। अधिकारी अब सीमेंट का मूल्य निर्धारित नहीं करते हैं। हम मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को मुद्रास्फीति लक्ष्य के आधार पर अल्प दर चुनने के लिए कह सकते हैं। सटीक विनिमय दर का चयन करने के लिए विशेषज्ञों का समूह तैयार करने का कोई औचित्य नहीं है।

3. एक नियत विनिमय दर कुछ लोगों के लिए निःशुल्क जोखिम प्रबंधन करने का जरिया होता है क्योंकि उन्हें स्वयं मुद्रा जोखिम का प्रबंधन नहीं करना पड़ता है। यह कहना काफी कठिन है कि ऐसी सरकारी सब्सिडी व्यवस्था कितनी उचित ठहराई जा सकती है।

4. नैतिक संकट का भी मसला उठता है। जब निजी क्षेत्र की इस तरक रक्षा की जाती है तो वे अधिक मुद्रा जोखिम लेंगे और ये बाद में नुकसान का कारण बनते हैं। जोखिम की आशंका वाले लोग उन नीतियों के लिए अधिक दबाव डालेंगे जो उनके हित में होंगी)।

5. स्वतंत्र मौद्रिक नीति, निश्चित विनिमय दर और पूंजी का बेरोक-टोक प्रवाह तीनों बातें एक साथ संभव नहीं हैं। भारत के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य के साथ एक मुक्त पूंजी खाता रखना और आधुनिक बॉन्ड-मुद्रा-डेरिवेटिव (बीसीडी) गठजोड़ तैयार करना जरूरी है। इन सभी के साथ विनिमय दर में बदलाव भी जरूरी है। मुद्रास्फीति लक्ष्य के साथ जुड़े विरोधाभास और नियंत्रित विनिमय दर नीति निर्धारकों द्वारा मुद्रा डेरिवेटिव कारोबार को नुकसान पहुंचाने, पूंजी निकासी पर स्रोत पर कर काटने (टीडीएस) आदि के पीछे कारण को स्पष्ट करते है।

यह तर्क 1991 से 2006 तक चल रहा था और विनिमय दर में लचीलापन और लोगों को जोखिम प्रबंधन में मदद पहुंचाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव बाजारों के विकास से यह बहस खत्म हो गई। ऐसा लगता है कि आरबीआई ने इन नीतिगत रणनीति को पलटने के लिए बड़े बदलाव किए हैं। उसने मुद्रा डेरिवेटिव बाजार के कुछ हिस्से बंद कर दिए हैं और लगभग नियत दर की तरफ वापस लौट आया है। ऐसे बड़े निर्णय सार्वजनिक सुझाव और तर्कों के आधार पर लिए जाएं तो बेहतर होगा।

जब विवेकपूर्ण तरीके से कोई आर्थिक नीति तैयार की जाती है तभी यह कारगर होती है। सफल दशकों में अर्थशास्त्र ने कुछ इसी तरह प्रभावी भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया बिना किसी ठोस आधार के शुरू नहीं की गई है बल्कि यह 20 वर्षों के शोध और भारत के उद्देश्यों की पूर्ति के विवेकपूर्ण तरीकों पर वैचारिक चर्चा के बाद प्रभावी हुई है।

(लेखक आइजक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी में मानद वरिष्ठ फेलो और पूर्व अधिकारी हैं।)

एनबीएफसी पर आरबीआई के बढ़ते एतराज

ऐसा लगता है कि भारतीय बैंकिंग नियामक के शब्दकोश में 'सब बस भौंकते हैं, काटते नहीं' मुहावरे का कोई स्थान नहीं है। महज एक हफ्ते पहले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को कड़ी चेतावनी देने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले हफ्ते एक आदेश जारी कर चार एनबीएफसी को नए ऋण को मंजूरी देने और उसका वितरण करने से रोक दिया है। इन एनबीएफसी में आशीर्वाद माइक्रोफाइनैंस लिमिटेड, आरोहण फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड, डीएमआई फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड और नावी फिनसर्व लिमिटेड शामिल हैं।

ऐसा पाया गया कि एनबीएफसी अधिक ब्याज दर वसूलने के अलावा नियामक के दिशानिर्देशों के मुताबिक परिवारों की आमदनी और ऋणकर्ताओं की मासिक किस्त चुकाने की क्षमता का आकलन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा पुराने ऋण नहीं चुका पा रहे ऋणकर्ताओं को नए ऋण देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि आरबीआई ने अपने आदेश में एनबीएफसी की विभिन्न योजनाओं की क्रॉस सेलिंग का जिक्र नहीं किया है। इन चार कंपनियों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है लेकिन आमतौर पर एनबीएफसी ऋण से इतर ऋण लेने वालों को विभिन्न उत्पाद बेचती हैं। पहले बिक्री की सूची में मोबाइल फोन, बीमा पॉलिसी, सोलर लालटेन और इन्वर्टर लाइट शामिल थे। अब ऋण दिए जाने के साथ ही प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर, टीवी और रेफ्रिजरेटर भी बेचे जाते हैं। कई मामलों में ऋण देने की पूर्व शर्त भी इन उत्पादों की बिक्री से जुड़ी होती है। संभवतः आरबीआई ने इस तरह की 'अन्य आय' को एनबीएफसी द्वारा वसूले जा रहे ब्याज दर के साथ जोड़ दिया है। चार एनबीएफसी में से डीएमआई का सबसे बड़ा लोन बुक है और यह इस वर्ष जून तक 13,160 करोड़ रुपये है और इसके बाद आशीर्वाद (11,327 करोड़ रुपये), नावी (9,110 करोड़ रुपये) और आरोहण (6,737 करोड़) का स्थान है।

जब वृद्धि की बात आती है तब डीएमआई इस सूची में 47.76 फीसदी वृद्धि के साथ शीर्ष पर, आशीर्वाद दूसरे पायदान (33.7 फीसदी) पर इसके बाद नावी (32.67 फीसदी) और आरोहण (27.95 फीसदी) का स्थान है।

आशीर्वाद का सकल फंसा कर्ज 2.99 फीसदी है और बट्टे खाते में डालने के बाद यह 7.7 प्रतिशत तक हो जाता है। इसकी तुलना में आरोहण का आंकड़ा 2.5 प्रतिशत और 4.39 प्रतिशत है। डीएमआई का कुल फंसा ऋण 2.54 प्रतिशत और नावी का 1.7 प्रतिशत है। आशीर्वाद का सबसे अधिक मार्जिन (एनआईएम) 17.29 प्रतिशत है जो फंडों की लागत और ऋण से होने वाली कमाई के बीच का अंतर है। इस लिहाज से इसके बाद नावी (16.35 प्रतिशत), आरोहण (13.32 प्रतिशत) और डीएमआई (11.46 प्रतिशत) का स्थान है।

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

आरबीआई के गवर्नर ने इस महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा में एनबीएफसी क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा, 'रिजर्व बैंक आने वाली जानकारी पर नजर रख रहा है और आवश्यक होने पर कदम उठाएगा।'

उन्होंने इस क्षेत्र को लेकर तीन महत्त्वपूर्ण विचार दिए:

■ कुछ एनबीएफसी स्थायी कारोबार की कार्यप्रणाली और जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किए बिना किसी भी कीमत पर वृद्धि को तरजीह दे रही हैं। इस तरह का अविवेकपूर्ण रवैया उनके अपने कारोबारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होगा।

■ माइक्रोफाइनैंस संस्थानों और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित कुछ कंपनियां अपनी इक्विटी पर अधिक रिटर्न पाने की कोशिश कर रही हैं जो उनके निवेशकों के चलते संचालित होती हैं। वे अधिक ब्याज दर, अधिक प्रसंस्करण शुल्क और गलत तरीके से दंडशुल्क वसूल कर पैसे कमा रही हैं। ऋण की मांग न होने के बावजूद ऋण लेने के लिए बाध्य करने के प्रभाव के कारण इन एनबीएफसी के बैलेंसशीट में बढ़ोत्तरी हो रही है।

■ कुछ एनबीएफसी के वेतन पैकेज में प्रोत्साहन से जुड़े पहलू शुद्ध रूप से लक्ष्य आधारित हैं। इस तरह के चलन से कार्यसंस्कृति और ग्राहक सेवाओं पर असर हो सकता है।

एनबीएफसी का दायरा बेहद व्यापक है। देश में कम से कम 9,325 एनबीएफसी और 94 एचएफसी हैं। आरबीआई के वर्गीकरण के मुताबिक 9 एनबीएफसी और 5 एचएफसी शीर्ष स्तर पर हैं, बाकी एचएफसी और 404 एनबीएफसी मध्यम स्तर पर और 8,912 एनबीएफसी बुनियादी स्तर पर हैं। यह सवाल हो सकता है कि क्या हमें इतने एनबीएफसी की जरूरत है? इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हमारे देश में ऋण की कमी है। विश्व बैंक के मुताबिक निजी क्षेत्र में भारत का घरेलू ऋण वर्ष 2020 में जीडीपी के 55 फीसदी तक था जो वैश्विक औसत (148 प्रतिशत) से काफी नीचे है और एशियाई देशों चीन (182 प्रतिशत), दक्षिण कोरिया (165 प्रतिशत) और वियतनाम (148 प्रतिशत) से भी काफी नीचे है। हालांकि इतने सारे एनबीएफसी की निगरानी करना आसान नहीं है।

दूसरा सवाल यह है कि आरबीआई ने एनबीएफसी को नियंत्रण में रखे के लिए भले ही सख्त कदम उठाए हैं लेकिन क्या इसे संरचनात्मक तरीका नहीं अपनाना चाहिए था? इन चारों एनबीएफसी का ऋण पोर्टफोलियो 40,334 करोड़ रुपये का है। इनकी परिसंपत्ति कहीं अधिक 50,693 करोड़ रुपये है। भले ही इन चारों का बेहतर पूंजीगत आधार (22 प्रतिशत और 52 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता अनुपात) है लेकिन बैंकिंग तंत्र का भी इनमें निवेश है।

आरबीआई कुछ समय से एनबीएफसी क्षेत्र की कार्यप्रणाली को लेकर अपना असंतोष जताता रहा है लेकिन कड़े आदेश जारी करने से पहले क्या नियामक को नोटिस नहीं देना चाहिए कि उनके खिलाफ कड़े कदम क्यों न उठाए जाएं? इससे वित्तीय क्षेत्र गलत कार्यप्रणालियों को लेकर सतर्क होता और साथ ही गलत करने वाली संस्थाओं को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है।

अब व्यापक तस्वीर पर गौर करते हैं। सामूहिक तौर पर शीर्ष स्तर के एनबीएफसी की कुल परिसंपत्ति जून में 14.25 लाख करोड़ रुपये थी जो इस क्षेत्र के कुल ऋण पोर्टफोलियो का एक-चौथाई है। पिछले एक वर्ष में जून 2023 और जून 2024 के बीच इनके ऋण में वृद्धि करीब 27 प्रतिशत तक रही है। शीर्ष स्तर के एनबीएफसी के ऋण पोर्टफोलियो में खुदरा ऋणों का योगदान कम से कम 60 प्रतिशत तक है।

मध्यम वर्ग के एनबीएफसी का कुल ऋण करीब 52 ट्रिलियन तक है और उनकी ऋण वृद्धि करीब 12 प्रतिशत तक रही है।

करीब 100 एमएफआई-एनबीएफसी हैं और इनमें से 25 का ताल्लुक मध्यम स्तर और 75 का संबंध निचले स्तर से है। इनके ऋण में वृद्धि, जून 2023 से जून 2024 के बीच करीब 23 फीसदी है।

जिन एनबीएफसी पर कार्रवाई की गई है या जिन पर कार्रवाई हो सकती है उन्हें अपनी ब्याज दरें कम करने के साथ ही बिना वक्त गंवाए अधिक फीस और दंडशुल्क घटाना चाहिए।

हमेशा से ऋण देने का बुनियादी नियम यह मूल्यांकन करने से जुड़ा है कि ऋण लेने वाले की ऋण चुकाने की क्षमता कितनी है और ऋण चुकाने की उनकी इच्छा होगी या नहीं। इस पड़ाव पर एनबीएफसी को यह भी देखने की जरूरत है कि वास्तव में ऋणकर्ताओं को पूंजी की जरूरत भी है या नहीं। आखिर ऋण देने वाली कंपनियों के बैलेंसशीट बढ़ाने के जुनून के चलते ऋणकर्ताओं को अपनी परेशानी क्यों बढ़ानी चाहिए?

आपका पक्ष

इजरायल-ईरान तनाव बनाम भारत के कारोबारी मुद्दे

इजरायल एक बार फिर ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी में है। इजरायल और ईरान का यह टकराव तेजी पकड़ने और विश्व शांति को संकट में डालने वाला हो सकता है, जिसकी जद में ईरानी परमाणु कार्यक्रम भी आ सकता है। पश्चिम एशिया में शांति के आसार नहीं हैं। इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी चिंता की वजह दोनों देशों के साथ भारत के कारोबारी संबंध हैं। दोनों देशों से 2023-2024 में भारत का करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये का व्यापार समझौता हुआ है, इनमें से ईरान के साथ करीब 21 हजार करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है। ईरान के चाबहार पोर्ट और इससे लगे चाबहार स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन में भी भारत साझेदार है। वहीं भारत- इजरायल व्यापार की बात करें तो वर्ष 2023 में इजरायल के साथ भारत ने करीब 90 हजार करोड़ रुपये का व्यापार किया है। वहीं दूसरी ओर,

लेबनान के ऐतिहासिक शहर टायरे में बुधवार को इजरायली हवाई हमले के बाद ध्वस्त इमारतों के बीच उठता धुंआ

वह समुद्री मार्ग जहां बीते दो वर्षों से ज्यादा तनाव हुआ है, उस मार्ग से भारत का भी काफी सामान आता है। ऐसे में जंग छिड़ने से भारत के कारोबारी हित प्रभावित हो सकते हैं। सिंगापुर से लेकर यूरोप तक के कई तेल टैंकर और मालवाहक जहाजों के कार्गो में भारतीय कर्मियों की अच्छी-खासी तादाद है। ऐसे में आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

आर्थिक वृद्धि दर 8 प्रतिशत की ओर भारत

भारत 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान आंकड़ों, औद्योगिक उत्पादन एवं विकास तथा तकनीक के प्रभाव से पिछले दशक में भारत की आर्थिक प्रगति तीन वर्ष के कोरोना काल के बावजूद तेजी से बढ़ी है और पिछले दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। इस कालखंड में आर्थिक वृद्धि दर 7-8 प्रतिशत के बीच रही है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अगले चार-पांच वर्षों में आर्थिक वृद्धि दर 9 प्रतिशत अपेक्षित है। इससे आगे का मार्ग बहुत लंबा है क्योंकि चीन का सकल घरेलू उत्पाद 18 अब डॉलर जबकि अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद 25 अरब डॉलर है जबकि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सकल घरेलू उत्पाद लगभग 6 अरब डॉलर ही होगा। कृषि उपज का मात्र चालीस प्रतिशत भाग ही मंडियों और बाजारों में सरकारी रिकॉर्ड, मंडी समिति के माध्यम से आता है, शेष घरेलू खपत और बिक्री असंगठित माध्यम से होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि मंडी समिति और अन्य कृषि उपज की सरकारी खरीद एवं विपणन की कार्यप्रणाली में किसानों के हितों में सुधार किया जाए। वहीं जीएसटी के 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरें बहुत अधिक हैं जिनके कारण अधिकतर माल का उत्पादन नंबर दो में होता है। यही अवरोध औद्योगिक उत्पादन को असंगठित क्षेत्र में होने के कारण कर संग्रहण कम होता है जिसका विपरीत प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ता है। अधिक तय जीएसटी दरें 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। शिक्षा में कौशल और अप्रेंटिसशिप बढ़ाने से कुशल कारीगर उपलब्ध होंगे।

विनोद जौहरी, दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को वायनाड लोक सभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

www.readwhere.com

तथ्य

बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय की 'उद्योग 5.0 और एआइ रपट' के अनुसार, 44 फीसद संगठनों ने एआइ एकीकरण के जरिए उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा 21 फीसद ने बताया कि एआइ नवोन्मेषण को आगे बढ़ाने, नए उत्पादों, सेवाओं और कारोबारी माडल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रपट के मुताबिक, खासकर वित्त, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण और विपणन जैसे क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिल रहा है। रपट में कहा गया कि लगभग 33 फीसद संगठन उत्पाद विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

सीटेट के आवेदन में की गई गलती में कल तक करें सुधार

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर (सीटेट 2024) के आवेदन पत्र में सुधार करने के लिए संशोधन विंडो खोल दी है। उम्मीदवार 25 अक्तूबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर अपने फार्म में बदलाव कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने नाम, पिता और माता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, दिव्यांग श्रेणी, चुने गए पेपर (अर्थात पेपर एक या पेपर दो किसी विशेष शहर में क्षमता की उपलब्धता के अधीन), पेपर दो के लिए विषय, चुनी गई भाषा एक और/या दो, पत्राचार का पता और संस्थान/कालेज/विश्वविद्यालय का नाम बदलने की अनुमति होगी।

'डेटा साइंस' में नौकरियों की भरमार

विशेषज्ञ की कलम से

डेटा साइंस यानी आंकड़ा विज्ञान से जुड़े रोजगार आजकल चलन में हैं। आप भी डेटा साइंस के क्षेत्र में करिअर बना सकते हैं। यह एक विकसित होता क्षेत्र है, जहां आने वाले समय में रोजगार की अपार संभावनाएं होंगी। यह सांख्यिकीय और कंप्यूटेशनल टूल, एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग सिद्धांतों का एक मिश्रण है। जिसका उद्देश्य उन आंकड़ों में छिपे प्रासंगिक संदेशों को उजागर करना है, जिनका बाद में बेहतर निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे-जैसे देश और दुनिया में डेटा का महत्त्व बढ़ रहा है, ठीक उसी रफ्तार से डेटा वैज्ञानिक, डेटा एनालिटिक्स जैसी नौकरियों के अवसर भी आ रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि आने वाले 10-15 साल तक इससे जुड़े कोर्स का स्कोप खूब रहेगा, क्योंकि यहां नौकरियों की भरमार रहने वाली है।

उच्च शिक्षा में भूमिका

कई उच्च शिक्षण संस्थानों और ई-लर्निंग प्लेटफार्मों ने डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। आइआइटी और एनआइटी ने डेटा विज्ञान में कार्यकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं। सामाजिक विज्ञान और मैनेजमेंट स्कूलों ने भी अपने पोर्टफोलियों में डेटा साइंस को जोड़ना शुरू कर दिया है।

रोजगार के अवसर

आने वाले वर्षों में डेटा साइंस के क्षेत्र में कई नौकरियों की संभावनाएं और संख्या बढ़ सकती है। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक लगभग 27 लाख पद मार्केट में होंगे, जबकि भारत में एनालिटिक्स, डेटा साइंस का आकार सात गुना बढ़ने और 2028 तक लगभग दो करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। ई-कामर्स, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सेवाओं, खेल, पत्रकारिता और सार्वजनिक नीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में डेटा साइंटिस्ट, डेटा विश्लेषक, डेटा आर्किटेक्ट, सांख्यिकीविद् या व्यवसाय विश्लेषक के रूप में रोजगार के कई अवसर हैं।

वेतन

डेटा साइंस के क्षेत्र में वेतन आपके अनुभव, पद और कंपनी के आकार पर निर्भर करता है। इस क्षेत्र में शुरुआती स्तर पर आमतौर पर 4-12 लाख रुपए सालाना वेतन मिलता है। वहीं डेटा साइंस मिड-लेवल की नौकरी में सालाना 10-20 लाख रुपए तक वेतन मिल सकता है। इसके अलावा डेटा साइंस क्षेत्र में वरिष्ठ और विशेषज्ञ स्तर पर सालाना 20-40 लाख रुपए या उससे ज्यादा भी वेतन मिल सकता है।

- आशीष झा, *करिअर परामर्शदाता*

बारहवीं के बाद प्रमुख पाठ्यक्रम

- **बीटेक-डेटा साइंस**
  यह कोर्स चार साल का है। इसमें छात्रों को डेटा से जुड़े टूल्स और तरीके सिखाए जाते हैं, जिनकी मदद से डेटा का इस्तेमाल किया जा सके।
- **बीएससी-डेटा साइंस**
  यह डिग्री कोर्स तीन साल का है। इसमें कई डोमेन हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस। इस कोर्स में कंप्यूटर और बिजनेस के साथ-साथ एआइ के बारे में भी पढ़ाया जाएगा।
- **बीसीए**
  बीसीए भी तीन साल का स्नातक कोर्स है। इसमें कंप्यूटर और मैथमेटिकल साइंस से जुड़ा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है।
- **डिप्लोमा इन डेटा साइंस**
  डेटा साइंस में डिप्लोमा दो साल तक का हो सकता है। इसमें छात्र को डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। डिप्लोमा कोर्स में डिग्री के मुकाबले खर्च कम है। कम समय में ज्यादा स्किल्स सीखने का मौका मिलता है।

जानें-सीखें

साथी पोर्टल से निशुल्क करें जेईई व नीट की तैयारी

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने छात्रों को इंजीनियरिंग (जेईई), मेडिकल (नीट) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए 'साथी पोर्टल 2024' शुरू किया है। इस पर हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन संसाधन उपलब्ध हैं। इस निशुल्क सुविधा का लाभ लेने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। 'साथी' प्लेटफार्म एक पूरी तरह से आनलाइन संसाधन है, जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए तैयार किया गया है। यह मुफ्त शैक्षिक सामग्री, वीडियो पाठ, माक टेस्ट और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों को समर्थन करता है, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए।

कैसे काम करता है

पोर्टल पर साइन अप करने के बाद, छात्र विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। उन्हें लाइव पाठ, ट्यूशन, एनसीईआरटी-आधारित पुस्तकें और वीडियो समाधान उपलब्ध होंगे। सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए, कार्यक्रम को डीटूएच चैनलों के माध्यम से भी प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा, एक चैटबाट भी है जो छात्रों को प्रश्नों में सहायता करता है और संसाधनों तक पहुंचने में मदद करता है।

पंजीकरण प्रक्रिया

एनसीईआरटी साथी पोर्टल पर अपना नाम, ईमेल पता और शैक्षणिक जानकारी भरनी होगी। इसके बाद, वे अपनी इच्छित प्रतियोगी परीक्षा का चयन कर सकते हैं, जैसे जेईई, नीट या एसएससी। पंजीकरण के बाद, छात्र लाइव सत्रों में भाग ले सकते हैं और शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच सकते हैं।

मुख्य विशेषताएं

- जेईई और अन्य इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी के लिए 45-दिवसीय 'क्रैश कोर्स'।
- गेट, कैट और यूपीएससी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सामग्री।
- आइआइटी, एनआइटी और एम्स जैसे प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन।
- क्षेत्रीय भाषाओं में वीडियो व्याख्यान उपलब्ध हैं, जिससे सभी छात्रों को लाभ होता है।

युवा शक्ति डेस्क

कोशल

दिवाली से पहले बुधवार को गुवाहाटी में मिट्टी के दीये बनाते दिव्यांग विद्यार्थी।

बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक के लिए अभी से शुरू कर दें तैयारी

परामर्श

बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ा दबाव और अपेक्षाएं भारी हो सकती हैं, लेकिन सही मानसिकता, तैयारी और रणनीतियों के साथ छात्र अपने शैक्षणिक जीवन के इस दौर को आसानी से पार कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहले छात्रों को एक विस्तृत अध्ययन योजना बनानी चाहिए, जो प्रत्येक विषय के लिए उसकी कठिनाई और उनकी क्षमता के आधार पर समय आवंटित करे। पाठ्यक्रम को पहले से ही पूरा करने से पुनराभ्यास के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। छात्रों को तैयारी के दौरान पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की मदद जरूर लेनी चाहिए। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों और सैंपल पेपर्स के माध्यम से नियमित अभ्यास से समझ में वृद्धि हो सकती है और आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा।

रटने की बजाय समझने को दें प्राथमिकता

याद करने की अपनी जगह है, लेकिन असली सफलता किसी भी विषय को सही से समझने से मिलती है। हर विषय के अंतर्निहित सिद्धांतों को गहराई से समझने की कोशिश करें, न कि उन्हें सिर्फ अपने दिमाग से रटने की। इससे पढ़ाई ज्यादा दिलचस्प होगी। निष्क्रिय शिक्षार्थी न बनें। जब जरूरत हो तो मदद लें शिक्षकों या सहपाठियों से सहायता मांगने में संकोच न करें और समर्थन के लिए अध्ययन समूहों में भाग लें। सीखने में सक्रिय रूप से भाग लेने से, यह जानकारी की समझ और अवधारण को मजबूत करता है।

जेईई मुख्य परीक्षा 2025 : पांच प्रश्नों वाली छूट खत्म

अगले साल होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मुख्य परीक्षा 2025 के संबंध में राष्ट्रीय परीक्षण एजंसी (एनटीए) ने एक बड़ा बदलाव किया है। एनटीए कोरोना काल के बीच साल 2021 से छात्रों को जेईई मेन प्रश्न पत्र के सेक्शन बी के प्रश्न हल करने को लेकर खास छूट दे रही थी लेकिन अगले साल से इस छूट को समाप्त किया जा रहा है। इस संबंध में एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है।

एनटीए की ओर से जारी नोटिस के अनुसार छात्रों को पिछले कुछ सालों से हर विषय के सेक्शन बी में प्रश्नों को प्रयास करने और उत्तर देने को लेकर छूट मिलती थी, जिसमें अभ्यर्थी 10 में से कोई भी 5 सवालों के जवाब दे सकते थे। इस छूट को अब समाप्त किया जा रहा है। यानी साल 2025 परीक्षा में जेईई प्रश्न पत्र के सेक्शन बी में ऐसा विकल्प नहीं होगा। छात्रों को दिए गए सभी प्रश्न हल करने होंगे। छात्रों को परीक्षा की तैयारी में आई चुनौतियों के चलते जेईई मेन 2021 से 2024 तक यह खास सुविधा लाई गई थी, जिसे अब हटाया जा रहा है।

एनटीए के नोटिस में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की ओर से कोविड महामारी की दिशानिर्देश पांच मई 2023 को खत्म कर दिए हैं, ऐसे में सेक्शन बी की संरचना अब पहले की तरह हो जाएगी। जेईई मेन 2025 के अंदर सेक्सन बी में हर विषय से 5 सवाल होंगे और छात्रों को सभी 5 सवालों का उत्तर देना होगा। एजंसी ने कहा कि यह इंजीनियरिंग (बीई/बीटेक, पेपर 1) और आर्किटेक्चर और प्लानिंग (बीआर्क/बीप्लानिंग, पेपर 2) दोनों पर लागू होगा।

जरूरी जानकारी

दो सत्रों में होगी परीक्षा

एनटीए नवंबर 2024 में जेईई मेन 2025 के लिए परीक्षा तिथियों की घोषणा करेगा। जेईई मेन 2025 शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दो सत्रों में आयोजित किया जाएगा। जेईई मेन 2025 पहला सत्र जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगा और दूसरा सत्र अप्रैल 2025 के मध्य में आयोजित किया जाएगा। जेईई मुख्य परीक्षा तिथि की घोषणा के साथ, एनटीए अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जेईई मुख्य पंजीकरण फार्म की तारीख भी जारी करेगा। एनटीए की तरफ से जेईई मेन परीक्षा की परीक्षा अवधि 3 घंटे होगी। हालांकि लिखने में कठिनाई वाले उम्मीदवारों को प्रति 1 घंटे में 20 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे।

क्लैट से पहले कानून की पढ़ाई में नया कोटा

विधि में प्रवेश के लिए क्लैट (कामन ला एडमिशन टेस्ट) 2025 परीक्षा दिसंबर 2024 में होने वाली है। लेकिन इससे पहले ही देश की कुछ प्रमुख राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने ला कोर्स में दाखिले के लिए कोटा सिस्टम में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। ये नया नियम एलएलबी और एलएलएम यानी ला के यूजी और पीजी दोनों में लागू होगा। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अलग से आरक्षण की नीति जोड़ी गई है। इसके अलावा राज्य कोटा भी लागू किया गया है। महाराष्ट्र के तीन एनएलयू में यूजी और पीजी ला पाठ्यक्रमों में सोशली और इकोनामिकली बैकवर्ड क्लास (एसईबीसी) के लिए आरक्षण जोड़ा गया है। ये एनएलयू मुंबई, एनएलयू औरंगाबाद और एनएलयू नागपुर में लागू होगा। असम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में राज्य के ईडब्लूएस और असम में तैनात रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी के बच्चों के लिए आरक्षण जोड़ा गया है। फिर चाहे रक्षा विभाग के कर्मचारी भारत के किसी भी राज्य से क्यों न हों, अगर उनकी तैनाती असम के किसी भी हिस्से में है, तो उनके बच्चे को एनएलयू असम में ला में प्रवेश में कोटा का फायदा मिलेगा। इस बार की क्लैट परीक्षा में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित डा राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को भी जोड़ा गया है।

सूचनापट्ट

जामिया

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने पर्यावरण स्वास्थ्य, जोखिम और सुरक्षा प्रबंधन में एक नया एमटेक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पेशेवरों को पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी खतरों और कार्यस्थल की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का गहराई से अध्ययन करने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। यह विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए उपयोगी है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पर्यावरण नीतियों, नई तकनीकों, और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रबंधन प्रणालियों का प्रशिक्षण भी मिलेगा। इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए, अभ्यर्थियों के पास यूजीसी या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यावरण अध्ययन/विज्ञान में एमएससी या किसी भी शाखा में बीटेक/बीई/बी प्लानिंग की डिग्री होनी चाहिए, और उन्हें न्यूनतम 55 फीसद अंक प्राप्त करने चाहिए। आवेदकों को जेएमआइ की वेबसाइट पर जाकर एक अलग आवेदन पत्र भरना होगा। प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक परीक्षा पर आधारित होगा, जिसका पाठ्यक्रम जेएमआइ की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अंतिम तिथि : 27 अक्तूबर, 2024

स्वयं

राष्ट्रीय परीक्षण एजंसी (एनटीए) ने स्टडी वेब्स आफ एक्टिव-लर्निंग फार यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयं) जनवरी 2025 सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। संबंधित उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार, जनवरी सेमेस्टर की परीक्षा 17, 18, 24 और 25 मई, 2025 को आयोजित की जाएगी। इस बीच, स्वयं जुलाई 2024 सेमेस्टर के लिए पंजीकरण आनलाइन प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं। सुधार विंडो 1 से 3 नवंबर, 2024 तक खुलेगी। परीक्षा 7, 8, 14 और 15 दिसंबर को दो पालियों में आयोजित की जाएगी - सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक।

अंतिम तिथि : 31 अक्तूबर, 2024

आइआइटी दिल्ली

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली में सेंटर फार बायोमेडिकल इंजीनियरिंग (सीबीएमई) ने हेल्थकेयर टेक्नोलाजी में मास्टर आफ साइंस (एमएस) रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया है। चिकित्सा और संबद्ध क्लीनिकल प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया यह कार्यक्रम जनवरी 2025 में शुरू होगा। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एमएस रिसर्च कार्यक्रम परियोजना-आधारित शिक्षा पर जोर देता है, जिससे छात्रों को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। यह कार्यक्रम पारंपरिक स्नातक डिग्री और चिकित्सा क्षेत्र में स्वतंत्र शोधकर्ता बनने के लिए आवश्यक अधिक व्यापक मास्टर और डाक्टरेट डिग्री के बीच की खाई को पाटने के लिए बहुत जरूरी इंटरमीडिएट डिग्री और प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

अंतिम तिथि : 25 अक्तूबर, 2024

इग्नू

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा जुलाई सत्र में प्रवेश के लिए इग्नू रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि एक बार फिर से विस्तारित कर दी गई है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी एडमिट कार्ड के लिए आनलाइन माध्यम से इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फार्म भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस पेज पर दिए लिंक से भी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी जिस भी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए पात्रता की जांच अवश्य कर लें। पात्र अभ्यर्थी जिस भी माध्यम में (डिस्टेंस लर्निंग या आनलाइन प्रोग्राम) प्रवेश लेना चाहें उसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। इग्नू में प्रवेश के लिए एससी/एसटी वर्ग से संबंधित उम्मीदवार शुल्क छूट के लिए दावा कर सकते हैं, बशर्ते कि वे एक इग्नू कार्यक्रम के लिए आवेदन करें। जो उम्मीदवार दूसरे या तीसरे वर्ष के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं, वे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक पुनः पंजीकरण फार्म भरकर इग्नू प्रवेश 2024 जुलाई सत्र में भाग ले सकते हैं।

अंतिम तिथि : 31 अक्तूबर, 2024

www.readwhere.com

कल्पमेधा

सत्य से मूढ़ का कोई संबंध नहीं होता, अपने मत से संबंध होता है। ज्ञानी, जो सत्य है, उसको अपना मत बनाता है। मूढ़, जो उनका मत है, उसको सत्य सिद्ध करता है।

- ओशो

सकारात्मक रुख

ब्रिक्स सम्मेलन में एक बार फिर भारत और चीन के रिश्तों में गरमाहट लौटती दिखी है। पिछले पांच वर्षों से दोनों देशों के बीच तल्खी बनी हुई थी। हालांकि इस बीच कुछ मौकों पर हमारे प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकातें जरूर हुईं, मगर द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई थी। ब्रिक्स सम्मेलन में अलग से दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता की और परस्पर सहयोग और सम्मान का संकल्प दोहराया। इस वार्ता से एक दिन पहले दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में अपनी सेनाओं को पीछे लौटाने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पुरानी स्थिति बहाल रखने का फैसला किया था। चीन ने दौलतबेग ओल्डी और डेमचोक क्षेत्र में अपना अतिक्रमण हटाने पर सहमति दे दी। अब दोनों देशों की सेनाएं अपने हिस्से के इलाकों में गश्त कर सकेंगी। चीन ने यह भी कहा है कि वह सीमा विवाद सुलझाने में भारत का सहयोग करेगा। अब प्रधानमंत्री की शी जिनपिंग के साथ बातचीत के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि चीन का रुख लचीला हो गया है और वह भारत के साथ दोस्ती बनाए रखना चाहता है। हालांकि यह कोई नाटकीय घटना नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से ही बननी शुरू हो गई थी, जब दोनों देशों के विदेशमंत्रियों ने अलग से बातचीत की थी।

सच्चाई यह भी है कि चीन बेशक अपनी विस्तारवादी रणनीति के तहत भारत को घेरने का प्रयास करता रहा हो, पर आज की वैश्विक स्थितियों में वह इसके साथ लंबे समय तक तनावपूर्ण रिश्ते बना कर नहीं चल सकता। चीन को मुख्य चुनौती अमेरिका से है। इसलिए अगर चीन को इस चुनौती से पार पाना है, तो उसे भारत के साथ रिश्ते मधुर बना कर रखने ही होंगे। ब्रिक्स का गठन ही इस मकसद से हुआ था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबदबे को कमजोर किया जा सके। फिर, अमेरिका और यूरोप ने जिस तरह यूक्रेन को रूस के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की, उससे रूस के सामने भी चुनौतियां बढ़ गई थीं। उसने चीन के साथ नजदीकी बढ़ा ली। मगर गलवान सैन्य संघर्ष के बाद चीन और भारत के बीच तल्खी कायम रहने से इस समीकरण में बाधा आ रही थी। इसलिए रूस भी चाहता था कि भारत और चीन अपने मतभेद जल्दी सुलझा लें। फिर, भारत के बिना ब्रिक्स देशों के संगठन में मजबूती कभी नहीं आ सकती। अच्छी बात है कि चीन ने इस तकाजे को समझा और भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया।

भारत की अहमियत चीन के लिए भी बड़ी है। भारत अब भी उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। फिर, जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और तकनीकी क्षेत्रों में लगातार भारत न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि दवा उत्पादन, सेमीकंडकटर आदि के मामलों में दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए एक बड़े सहयोगी के रूप में दिखने लगा है, ऐसे में चीन उसकी अनदेखी नहीं कर सकता। वैश्विक दक्षिण के तमाम देशों को भारत पर भरोसा है। इसलिए भी चीन और रूस उसे अलग करके नहीं रख सकते। अच्छी बात है कि चीन ने अपना रुख बदल लिया है, मगर उससे यह अपेक्षा फिर भी बनी रहेगी कि भारत के हिस्से वाले क्षेत्रों, उसके पड़ोसी देशों और हिंद महासागर में अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत चलाई जा रही, भारत के लिए चिंता पैदा करने वाली, गतिविधियों पर भी विराम लगाए।

पर्यावरण की फिक्र

मानसून की विदाई के साथ धान की कटाई शुरू हो गई है। मगर विडंबना है कि हर सख्ती के बावजूद खेत-खलिहानों में इस वर्ष भी पराली जलाई जा रही है। इससे जाहिर है कि नियम-कायदों की परवाह किसी को नहीं है। यह छिपी बात नहीं है कि पराली जलाने से प्रति वर्ष दिल्ली और आसपास प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंच जाता है। नागरिकों का दम घुटने लगता है। अस्पतालों में उपचार कराने की नौबत आ जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कवायद शुरू की, तब जाकर पंजाब और हरियाणा की सरकारें सक्रिय हुईं। पंजाब पुलिस ने आनन-फानन में एक महीने में ही आठ सौ चौहत्तर प्राथमिकियां दर्ज कीं। वहीं कैथल जिले में पराली जलाने पर अठारह किसानों को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के कृषि विभाग ने पहली बार चौबीस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। बावजूद इसके, पराली जलाने के मामले घट नहीं रहे। दिल्ली के आसमान पर धुएं की परत जमने लगी है। ऐसे में सर्वोच्च अदालत ने केंद्र के साथ पंजाब और हरियाणा को याद दिलाया है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है।

बड़ा सवाल है कि नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में होने के बावजूद पर्यावरण कानून का पालन करने से सरकारों को कौन रोक रहा है? इसे शक्तिहीन बनाने के लिए अदालत ने बुधवार को केंद्र की भी खिंचाई की। स्पष्ट है कि पराली जलने से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की बड़ी वजह जमीनी स्तर पर कार्रवाई न होना है। राज्य सरकारें और स्थानीय जिला प्रशासन पर्यावरण संरक्षण कानून को सख्ती से लागू करते, तो यह नौबत नहीं आती। यही वजह है कि शीर्ष अदालत ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को तलब कर बार-बार आंकड़े बदलने पर सवाल उठाया और कहा कि हर कोई इस मामले को हलके में ले रहा है। इससे गलत संदेश गया है। यह हैरानी की बात है कि शीर्ष न्यायालय की फटकार और बार-बार चिंता जताए जाने पर भी गंभीरता से व्यापक कार्रवाई न होना, यह साबित करता है कि राज्य सरकारें नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं हैं।

अपनों से अपनों का टूटता भरोसा

बिखरते पारिवारिक संबंधों में ही नहीं, विखंडित होते सामाजिक परिवेश में भी इस आर्थिक भंवर जाल का दुष्प्रभाव स्पष्ट दिखता है। हाल के बरसों में गांवों से लेकर महानगरों तक चल-अचल संपत्ति हड़पने की शिकायतें करीबी परिजनों के खिलाफ की गई हैं।

मोनिका शर्मा

हाल ही में राजस्थान के नागौर जिले में जमीन-जायदाद हड़पने के लिए बुजुर्ग माता-पिता को इतना परेशान किया गया कि तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस वृद्ध दंपति को न केवल बेटे-बहू, बल्कि बेटियां भी प्रताड़ित करती थीं। अपने ही बच्चों का अमानवीय बर्ताव लंबे समय से लगातार झेलते आ रहे असहाय मां-बाप ने पानी के टैंक में कूद कर जान दे दी। बेटों और बेटियों के दुर्व्यवहार से मिली पीड़ा कितनी भयावह रही होगी कि पुलिस को घर की दीवार पर चिपकाया हुआ उनका लिखा नोट मिला, जिसे उन्होंने मरने से पहले लिखा था। उसमें उन्होंने पारिवारिक कलह, स्वार्थ की अति और संपत्ति को लेकर विवाद का जिक्र किया था।

व्यथित करने वाली परिस्थितियों में अपनी जान देने वाले सत्तर और अड़सठ वर्षीय बुजुर्ग मां-बाप ने दो पृष्ठ के पत्र में बेटों, बहुओं, पोते-पोतियों और दोनों बेटियों के साथ कुछ रिश्तेदारों को भी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। कैसी विडंबना है कि धन के आधिपत्य से जुड़ी अनबन में अब बेटे ही नहीं, बेटियों और घर के बच्चों की भागीदारी का डरावना पहलू भी शामिल है। वहीं जमीन-जायदाद से जुड़ी दूसरी घटना नागौर के वाकये से ठीक विपरीत परिस्थितियों को सामने रखती है। जयपुर के इस मामले में पति के साथ हांगकांग में रहने वाली युवती ने अपने पिता, भाई और भाभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसका आरोप है कि उसके पिता, भाई और भाभी ने उसके सोने के आभूषण और जमीन छीन ली है। पीड़ित युवती कैंसर की मरीज है और नौ महीने पहले इलाज के लिए हांगकांग से भारत आई थी। इलाज कराने के दौरान उसे अपनों द्वारा की गई ठगी का पता चला। पीड़िता का कहना है कि पिता ने सहूलियत के नाम पर आभूषण और दो प्लाट के कागजात उसके बैंक से निकाल कर घर में रखे और फिर देने से इनकार कर दिया। कैंसर के इलाज के लिए कई दोस्तों और परिजनों से उधार लिए रुपए उसने और उसके पति ने गहने बेच कर चुकाने की सोची, पर इस बीच आभूषण और जमीन के दस्तावेज पिता और भाई ने हड़प लिए।

कैसी विडंबना है कि जानलेवा व्याधि से जूझती बेटी से लेकर जीवन संवारने वाले माता-पिता तक, धन-दौलत से जुड़े स्वार्थ में शामिल हो रहे हैं। हालांकि अधिकतर मामलों में बुजुर्ग ही प्रताड़ना का शिकार होते हैं, पर बदलती सोच और सामाजिक ढांचे में अब नई उलझनें भी दिख रही हैं। गृहक्लेश के ऐसे मामले कहीं अपनी जान देने, तो कहीं अपनों का जीवन छीनने के हालात तक ले जा रहे हैं। कई घरों में वर्षों की कानूनी लड़ाई में करीबी पर ही आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं। बिखरते पारिवारिक संबंधों में ही नहीं, विखंडित होते सामाजिक परिवेश में भी इस आर्थिक भंवर जाल का दुष्प्रभाव स्पष्ट दिखता है। हाल के बरसों में गांवों से लेकर महानगरों तक चल-अचल संपत्ति हड़पने, धोखे से कब्जा करने या चुरा लेने की शिकायतें करीबी परिजनों के खिलाफ की गई हैं। इनमें अपने ही बच्चों और अभिभावकों से लेकर दूसरे परिजनों के बीच चल-अचल संपत्ति के लिए लड़ने-

झगड़ने की घटनाएं आम हैं। यहां तक कि कुछ व्यावसायिक घरानों में भी ऐसे मामले देखने में आए हैं।

मौजूदा दौर में धन जीवन के आर्थिक पहलू से ही नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी जुड़ गया है। पैसे को सम्मान और दबदबे से

> **आक्रोश, अहंकार और स्वार्थ के मेल से उपजी सोच से पूरा पारिवारिक ढांचा डगमगा रहा है। बुजुर्गों और उम्रदराज लोगों का परिवार की मौजूदा पीढ़ी के प्रति विश्वास खत्म हो रहा है। हालांकि इस तरह की घटनाओं में वरिष्ठजनों के शोषण और प्रताड़ना के मामले अधिक हैं, पर रीत रहे भरोसे की बानगी हर उम्र के लोगों में दिखती है। जबकि पारिवारिक संबंधों में एक-दूसरे पर आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, हर पहलू से जुड़ी निर्भरता होनी चाहिए। जरूरी है कि धन-दौलत से जुड़े मामलों को लेकर भी आपसी संवाद और सहजता का मार्ग चुना जाए। स्थितियां इतनी तो न उलझें कि अपनों की जान लेने या अपनी जान देने की पीड़ादायी परिस्थिति बन जाए।**

जोड़ कर देखा जाने लगा है। सहज सुलभ जीवनशैली पाने के लिए ही नहीं, समाज और परिवार में रुतबा बनाने के लिए भी धन जुटाने की कोई सीमा नहीं रही। नतीजा, कहीं पर्याप्त धन का होना शोषण का कारण बनता है, तो कहीं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में जीवन जटिल स्थितियों का सामना करता है। दोनों ही स्थितियों का परिणाम आपराधिक घटना या आत्महत्या के रूप में भी सामने आता है। राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो द्वारा हर साल जारी किए जाने वाले आंकड़े भी बताते हैं कि देशभर में होने वाले आपसी विवाद ही नहीं, हत्या तक से जुड़े बहुत से मामले संपत्ति या भूमि विवाद से संबंधित होते हैं। ऐसे मामलों में अधिकतर परिजन ही आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते हैं। कुछ साल पहले रिसर्च थिंक टैंक 'दक्ष' के 'एक्सेस टू जस्टिस' सर्वे में भी सामने आया था कि भारत में सभी दीवानी मामलों में 66.2 फीसद मामले भूमि या संपत्ति विवादों से संबंधित थे।

ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं कि धन-संपत्ति की लालसा में अपने ही अपनों के अधिकार छीनने की नकारात्मक और स्वार्थी सोच रखने लगे हैं। चिंताजनक है कि अकेले उत्तर प्रदेश में भूमि और संपत्ति विवाद हत्याओं का प्रमुख कारण रहा है। 2017 से लेकर 2021 के बीच हत्या के उन्नीस हजार छह सौ चौवालीस मामले दर्ज हुए। अधिकतर मामलों में अपनों की आपसी उलझनें ही जिंदगी छीनने का कारण बन रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि धन-संपत्ति से जुड़ी रंजिश की घटनाएं चिंताजनक रूप बढ़ भी रही हैं।

असल में, संपत्ति से जुड़ी अनबन का एक पक्ष यह भी है कि सगे-संबंधियों में बरसों बरस यह मनमुटाव चलता रहता है। 'सेंटर फार पालिसी रिसर्च' के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किए गए सभी मामलों में से 25 फीसद भूमि विवाद से जुड़े हैं। निचली अदालतों में ऐसे मामले वर्षों तक चलते रहते हैं। एक ओर कानूनी पेचीदगियां, तो दूसरी ओर अपनों के ही आरोप-प्रत्यारोप। इन स्थितियों में लंबी न्यायिक प्रक्रिया भी निराशा पैदा करती है। इन्हीं हालात में कई बार लोग या तो किसी का जीवन छीनने का अपराध कर बैठते हैं या अपने जीवन से हार जाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2022 में देश में हुई सभी आत्महत्याओं में से 54.9 फीसद के पीछे पारिवारिक समस्याएं रही हैं। इन पारिवारिक समस्याओं में विवाह संबंधी समस्याएं शामिल नहीं हैं। पारिवारिक विवाद हत्याओं की भी तीसरी बड़ी वजह है। जमीन या संपत्ति विवाद को लेकर दो हजार तीन सौ छब्बीस, पैसों के विवाद को लेकर स्यारह सौ चौवालीस और स्वार्थ साधने के मकसद से अठारह सौ चौरासी हत्याएं हुईं।

आक्रोश, अहंकार और स्वार्थ के मेल से उपजी सोच से पूरा पारिवारिक ढांचा डगमगा रहा है। बुजुर्गों और उम्रदराज लोगों का परिवार की मौजूदा पीढ़ी के प्रति विश्वास खत्म हो रहा है। हालांकि इस तरह की घटनाओं में वरिष्ठजनों के शोषण और प्रताड़ना के मामले अधिक हैं, पर रीत रहे भरोसे की बानगी हर उम्र के लोगों में दिखती है। जबकि पारिवारिक संबंधों में एक-दूसरे पर आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, हर पहलू से जुड़ी निर्भरता होनी चाहिए। जरूरी है कि धन-दौलत से जुड़े मामलों को लेकर भी आपसी संवाद और सहजता का मार्ग चुना जाए। स्थितियां इतनी तो न उलझें कि अपनों की जान लेने या अपनी जान देने की पीड़ादायी परिस्थिति बन जाए। आपधापी भरे आज के जीवन में कम से कम अपनों से तो जुड़ाव बना रहे।

कृतज्ञता की गहराई

अशोक कुमार

मानव जीवन की आचार संहिता के अन्य सूत्रों में कृतज्ञता का स्थान अति विशिष्ट रहा है। हमारे पूर्वजों द्वारा इस आचरण को कभी अपनी दैनिक गतिविधियों का सहज और सरल हिस्सा के साथ स्वभाव माना जाता था। किसी के दुख या उसकी समस्या में संलग्न होने की सूचना मिलते ही वे अपने कार्य को विराम देकर उनके पास पहुंच जाया करते थे और यथाशक्ति वे सहायता के सभी स्रोतों से लैस रहते थे। सामाजिक जीवन में यह क्रिया स्वतःस्फूर्त होती थी। कभी-कभी किसी पड़ोसी से अनबन की स्थिति में भी अगर वे संकट में हैं, तो व्यक्ति सब कुछ विस्मृत कर उसे कष्ट से उबारने में चेष्टारत हो जाते थे। पीड़ित व्यक्ति ठीक हो जाने पर उक्त मददगार के घर जाकर प्रदत्त सेवा के प्रति आभार या कृतज्ञता ज्ञापन करने में जरा भी कंजूसी नहीं करते थे। ऐसे मनीषाय से पड़ोसी के बीच लंबे समय से जारी संबंधों के खटास में सक्रियता और सामान्यता का संचार हो जाता था, बल्कि संकट से मुक्त व्यक्ति मदद करने वाले अपने उस पड़ोसी की किसी प्रतिकूलता में सबसे पहले सहयोगार्थ हाजिर हो जाते थे।

जीवन के वर्तमान परिवर्तन के दौर में किसी को मदद करना अब कम हो गया है, क्योंकि आत्मकेंद्रित मनोदशा के हम सब शिकार हैं। जब हम कष्ट में पड़े किसी व्यक्ति का हाथ नहीं थामते तो ऐसी स्थिति में हम भी एकांत भाव में यथास्थितिवाद से गुजरने को बाध्य होते हैं। गुजरे जमाने में कृतज्ञता एक पारिवारिक संस्कार की अक्षय निधि होती थी, जिससे व्यक्ति के मानस पटल पर विनम्रता की रेखाएं सदा केंद्रित रहती थीं। कुछ लोग संकट काल में काम आने वाले व्यक्तियों के चिर ऋणी होते थे और इसमें लेशमात्र भी आडंबर नहीं होता था। कुछ बुजुर्गों की मान्यता थी कि किसी को मदद करने की कहीं चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी प्रवृत्तियों का जन्म मानव सभ्यता के प्रारंभ से होना यह बताता है कि किसी शिक्षण संस्थान के अभाव में भी हमारी जीवन पद्धति कितनी प्रभावी और सहयोगात्मक थी। कृतज्ञ प्राणी एक सामान्य शिष्टाचार की श्रेणी धारण करते हुए अपने शिष्ट वचनों से सहायता करने वाले का आभार प्रकट करते थे। इस शिष्टाचार के माध्यम से वे अपने व्यक्तित्व का श्रेष्ठ और उज्ज्वल प्रदर्शन करते थे और यह गुण उन्हें सम्मानित नागरिकों की पंक्ति में खड़ा कर देता था। सच कहा जाए तो कृतज्ञता एक ऐसी पुण्यकारी अवयव है, जो अनुग्रहकर्ता के प्रति अनुग्रहित होने का भाव ज्ञापन भी है, जहां उसके कृत्य अभिनंदनीय और वंदनीय हो जाते हैं।

वर्तमान भौतिक सुख की प्राथमिकता के बावजूद समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना किसी लोभ और यत्न के दूसरे को मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब हम स्नेह या प्रेम से किसी की सहायता करते हैं तो हमारे भीतर का मन कुछ हल्का होकर अहंकार के अंश को मौन कर देता है। इस विपुल ब्रह्मांड की अक्षय निधि सूर्य, वायु, पर्वत, वन, चंद्रमा, नदियां, वर्षा आदि बिना मांगे एक भाव से समस्त मानव प्राणी को नित्य उपकृत करते रहते हैं, जिसका आभार और कृतज्ञता हम विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। हम अपने प्रति कभी भी और किसी भी रूप में की गई सहायता के लिए आभार प्रकट करते हुए जब कहते हैं कि 'हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं, जिसके बदले हमें जब भी कभी अवसर आएगा, अवश्य सेवा करेंगे।'

दरअसल, यह भाव मानवता की सर्वोत्कृष्ट विशेषता है, जो हमें आभास दिलाती है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष किसी रूप में कभी भी अगर किसी व्यक्ति ने कोई मदद की है, तो उसके लिए अगर कुछ न कर सके तो हृदय से आभार अवश्य निवेदित किया जाए। वहीं कृतघ्नता इसके विपरीत एक नकारात्मक प्रवृत्ति है, जो आज समाज में अधिक देखी जा रही है और इंसान को उसके औसत कर्तव्य पथ से विमुख कर रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संकट में किसी न किसी रूप में अपने दांव-पेच के सहारे दूसरे से मदद लेते हैं, लेकिन उन्हें आभार प्रकट करने से वे विलग हो जाते हैं। ऐसी मनःस्थिति वाले मदद पाए लोगों से उनकी आवश्यकता की घड़ी में बड़ी निष्ठुरता से नजर भी फेर लिया करते हैं, जिन्हें लोग एहसान-फरामोश कहने में नहीं हिचकते।

> **दुनिया मेरे आगे**
>
> **सहयोग जैसे दिव्य और भव्य गुण के बल पर समाज और इंसान में एक सहज संबंध विकसित होकर भावना और संवेदना का जीवंत वातावरण निर्मित कर पाता है। कृतज्ञता सचमुच में मानवीय आचार संहिता के अनुष्ठान का एक पावन और अनवरत यज्ञ है।**

विचारणीय यह भी है कि समाज में अच्छे-बुरे लोगों का समूह सृष्टि के शुरू से ही है। सहयोग जैसे दिव्य और भव्य गुण के बल पर समाज और इंसान में एक सहज संबंध विकसित होकर भावना और संवेदना का जीवंत वातावरण निर्मित कर पाता है। कृतज्ञता सचमुच में मानवीय आचार संहिता के अनुष्ठान का एक पावन और अनवरत यज्ञ है। इससे विलग व्यक्ति को समाज से सहयोग और सहायता की कामना करना सूखे में जल तलाशने जैसा है। कई सामाजिक दर्शनों का आख्यान है कि किसी के प्रति किए गए उपकार अमूल्य हैं, लेकिन उपकृत व्यक्ति सिर्फ कृतज्ञता प्रकट कर भी उक्त उपकार का मोल कुछ हद तक चुका देता है। एक सेविका की सहायता के बिना हम जीवन नहीं पा सकते थे, जिसने हमें माता के गर्भ से इस संसार में अवतरण कराया। इसी प्रकार, वह व्यक्ति जो हमें नित्य वाहन द्वारा घर से दफ्तर आना-जाना कराते हैं, दोनों के प्रति भी एक तरह से मौन कृतज्ञता का भाव संचार तो होता ही है। स्वीकार किया जाना चाहिए कि पूर्वजों द्वारा स्थापित मानवीय सद्गुणों के अनेक रूपों में कृतज्ञता हमारे आचरण का वह आभूषण है जिसके सौंदर्य की सुगंध से हम असीम आनंद की शीतलता में अवगाहन करते हैं। किसी के सहयोग के बदले उसे धन्यवाद अर्पण में जीवन को एक नूतन दिशा में यात्रा का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह गुण बिना किसी क्षति के हमारी मनोदशा को तृप्त होने का अवसर प्रदान करता है।

फर्जी धमकियां

पिछले कुछ दिनों से विमानों और हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि ये सभी फर्जी निकलीं। मगर इससे न केवल देश का माहौल खराब हो रहा है, बल्कि कई विमानों को आपात स्थिति में उतारना पड़ रहा है। कई के मार्ग बदलने पड़े हैं। कई विमानों की सघन जांच से यात्रियों का समय बर्बाद हो रहा है। इसके अलावा कई असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। यह यात्रियों, विमानों और हवाई अड्डों की सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है। इसलिए इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जा सकती। स्वाभाविक रूप से सुरक्षा एजंसी द्वारा इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिर भी बीते दिनों नागर विमानन मंत्री ने कहा है कि सरकार इस तरह की धमकी देने वालों के नाम, 'उड़ान निषिद्ध' सूची में डालने पर विचार कर रही है। विमानन मंत्री का यह बयान बहुत देर से आया और अपर्याप्त महसूस होता है। विमानन मंत्रालय को तो किसी प्रकार की धमकी मिलते ही सक्रिय हो जाना चाहिए और त्वरित कार्रवाई कर फर्जी संदेश देने वालों के हौसले पस्त कर देना चाहिए। फर्जी संदेश देने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए।

- इशरत अली कादरी, भोपाल

हरित दिवाली

दिवाली खुशियों का पर्व है। इस पर्व में लोग खुशियों के साथ-साथ एक-दूसरे को मिठाइयां भी बांटते हैं और उनके अच्छे और स्वस्थ जीवन की मंगलकामना करते हैं। इस अवसर पर घरों में दीपक जलाया जाता है, ताकि यह अंधकार को मिटा कर रोशनी ला सके। मगर आज के परिप्रेक्ष्य में लोग इस मंगल पर्व को अमंगल बनाने लगे हैं। लोग पटाखे जलाने लगते हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण दूषित होता है, बल्कि कई लोग इन पटाखों और गोलों की गूंज से बहरे हो जाते हैं। कुछ लोगों के हाथ भी जल जाते हैं। कई बार दुकानों में इन पटाखों की वजह से आग भी लग जाती है। इन सभी दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमें पटाखों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ताकि पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। इसलिए पर्यावरणविद और चिकित्सक प्रतिवर्ष लोगों से हरित दीपावली मनाने की अपील करते रहे हैं। इस बार सभी नागरिकों को हरित दीपावली मनाने का संकल्प करना चाहिए।

- रविकांत कुमार, आइआइएमसी, जम्मू

शहरी प्रदूषण

छोटे शहरों के आसपास और उनमें बढ़ी औद्योगिक इकाई भी नहीं हैं, जो प्रदूषण उत्पन्न करें। इसके बावजूद छोटे शहरों में अत्यधिक प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। सामान्य लोग इस मामले में असहाय हैं। नीति नियामकों और सरकार से जुड़े तमाम अधिकरणों को संज्ञान लेना चाहिए और शुद्ध हवा में शहरवासी जीवन यापन करें, इसके लिए समाधान तलाशें। वायु गुणवत्ता सूचकांक का मापन शहर के साथ-साथ उनके आसपास वाले इलाके में भी हो और इस पर नियंत्रण कैसे लगे, इस पर मंथन होना चाहिए। सामान्य नागरिकों के लिए यह बात कहीं अधिक चिंतनीय है कि भागलपुर शहर प्रदूषण की चपेट में है। रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं बल्कि स्वस्थ वातावरण भी लोगों का अधिकार है। छोटे-छोटे शहरों में अगर ऐसी स्थिति रही, तो फिर स्वच्छ वातावरण कहां रहेगा। विकास के पहले ही विनाश की रूपरेखा खींची जा रही है।

- मिथिलेश कुमार, भागलपुर

कूटनीतिक कामयाबी

भारत की कूटनीति रंग ला रही है। अब चीन-भारत के बीच सीमा पर गश्त करने और आपसी मित्रता बढ़ाने पर बात हुई है। भरोसा होने पर और आगे कदम बढ़ाए जाने की संभावना है। उधर, हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान के संपर्क में हैं। अन्य पड़ोसी देशों के साथ ही दुनिया के देशों से हमारे राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक संबंध बढ़ रहे हैं। भारत हमेशा विश्व शांति की राह पर चलता रहा है और सबको शांति का संदेश देता रहा है। जैसा कि हाल ही में हमारे देश ने रूस-यूक्रेन युद्ध विराम की बात करते हुए आपस में वार्ता के जरिए समस्या का समाधान खोजने की सलाह दी थी। इसके सकारात्मक परिणाम निकलने की संभावना है। इसका प्रभाव युद्धरत देशों पर भी पड़ सकता है और वहां भी शांति की उम्मीद बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र को इस दिशा में सकारात्मक पहल करनी चाहिए।

- शकुंतला महेश नेनावा, गिरधर नगर, इंदौर

64,871 बूथों का डिजिटाइजेशन किया था भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में, जो देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने बूथ कमेटी और मतदाताओं का पूरा विवरण आनलाइन किया था।

ड. अनिता राठौर
वरिष्ठ स्तंभकार

भारत-चीन एलएसी समझौता

समझौते का स्वागत हो सजगता भी रहे कायम

रूस में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के आरंभ होने से एक दिन पहले भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) पर पेट्रोलिंग व्यवस्था संबंधी समझौता हो गया है। इससे न केवल डिसइंगेजमेंट (सैनिकों का मोर्चे से बैरकों में लौटना) होगा, बल्कि वर्ष 2020 के सैन्य टकराव से जो मुद्दे उठे थे, उनका भी समाधान हो जा सकता है। दोनों देशों के बीच स्थिति को सामान्य करने के संदर्भ में यह एक बहुत बड़ा कदम है। वस्तुत: पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में पिछले 54 माह से जो सैन्य गतिरोध बना हुआ था, वह समाप्त हो जा सकता है, फिर भी चीन के प्रति सजग तो रहना ही होगा

चीन की ओर से संकेत अच्छे मिले हैं, परंतु एलएसी के निकट सैन्य निगरानी में कमी नहीं की जानी चाहिए। फाइल

मंगलवार यानी 22 अक्टूबर से रूस के कजान में शुरू हुए 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग व्यवस्था संबंधी जो समझौता हुआ था, वह उम्मीदों के मुताबिक सही दिशा में बढ़ रहा है। अगले एक हफ्ते के भीतर भारत और चीन दोनों की सेनाएं 2020 में हुए गलवन घाटी टकराव से पहले की स्थिति में चली जाएंगी। चूंकि चीन इतिहास में कई बार समझौता करके भी पीछे लौटने की हरकत करता रहा है, इस वजह से भारत इस बार पूरी तरह से सतर्क था और तब तक पुरानी पेट्रोलिंग व्यवस्था की अपनी मांग को लेकर अडिग रहेगा, जब तक चीन इसे व्यावहारिक तौर पर शुरू नहीं कर देता। वैसे चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इस समझौते की पुष्टि करते हुए कहा है कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर चीन और भारत की कूटनीतिक एवं सैन्य स्तर पर करीबी बातचीत जारी है। उम्मीद की जा रही है कि लद्दाख क्षेत्र में सैन्य टकराव की आशंकाएं समाप्त हो जाएंगी।

दरअसल यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहे हैं, उनके कारण शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद विश्व एक बार फिर से दो खेमों में विभाजित होता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका और उसके यूरोपिय साथी हैं, जो यूक्रेन व इजरायल के समर्थन में खड़े हैं और दूसरी ओर रूस, चीन एवं ईरान का त्रिकोण है, जो पश्चिम का विरोध कर रहा है। भारत इन दोनों खेमों के बीच फिलहाल सेतु के रूप में है, लेकिन दोनों ही खेमे उसे अपने अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि भारत का चीन से सीधा सीमा विवाद चल रहा था, इसलिए उसके लिए किसी एक खेमे का सदस्य बनना संभव नहीं था। चीन ने सीमा विवाद को हल करके भारत को प्रलोभन अवश्य दिया है, लेकिन सवाल यह है कि चीन पर कितना भरोसा किया जा सकता है?

फिलहाल भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्रिक्स पश्चिम-विरोधी समूह बनकर न रह जाए। क्वाड, आकस, रूस-चीन 'नो-लिमिट्स पार्टनरशिप', यूक्रेन युद्ध और ईरान का ब्रिक्स सदस्य बनने के बाद यह दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है कि ब्रिक्स को पश्चिम के विरोध में खड़ा किया जाए। हालांकि ब्रिक्स के गठन का आधार ही पश्चिम-प्रभावित विश्व व्यवस्था को चुनौती देना था, लेकिन विस्तृत ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी बनने से बचना चाहिए। भारत के पास विशिष्ट अवसर है कि वह अपनी 'सेतु' वाली स्थिति का प्रयोग ब्रिक्स के भविष्य को दिशा देने के लिए करे।

वैसे भी भारत ने स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में संकोच नहीं किया है, जैसा कि यूक्रेन-रूस युद्ध में रूस पर पश्चिम की पाबंदी के बावजूद वह रूस से सस्ता तेल लेता रहा और इस तरह दुनिया को बता दिया कि वह किसी एक खेमे का सदस्य नहीं है। नई दिल्ली के लिए जरूरी है कि वह चीन के साथ एलएसी समझौते को द्विपक्षीय मामला ही रखे, उसे अंतरराष्ट्रीय खेमेबाजी की राजनीति का हिस्सा नहीं बनने दे। इस समझौते के संदर्भ में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि इस 'सकारात्मक' समझौते से दोनों पक्ष 2020 की स्थिति में वापस पहुंच गए हैं और डिसइंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी हो गई है। उनके अनुसार अब भारतीय सैनिक उसी तरह से पेट्रोलिंग कर सकेंगे, जैसा वह 2020 के गतिरोध से पहले करते थे।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत व चीन के बीच संबंध निरंतर पिघलती बर्फ की पतली परत पर टिके हुए थे, पूर्वी लद्दाख में 2020 के घातक टकराव के बाद से दोनों पक्ष जबरदस्त सैन्य तैयारी में जुटे हुए थे, जैसे किसी भी पल जंग का बिगुल बज जाएगा। गतिरोध वाले क्षेत्रों में बफर जोन के बावजूद दोनों देशों ने अधिक फौज की तैनाती से अपनी अपनी किलेबंदी भी की हुई थी, जो चिंता का विषय थी।

हालांकि भारत अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चीन से संपर्क में रहा है, लेकिन 2020 से द्विपक्षीय बातें केवल डिसइंगेजमेंट तक ही सीमित रही हैं। अब जो यह कदम आगे बढ़ा है, उस तक पहुंचने के लिए पिछले 53 माह में 20 चक्र से भी अधिक सैन्य वार्ताएं हुई हैं और इनके अतिरिक्त विदेश मामलों के अधिकारियों के बीच भी मल्टी-लेवल की अनेक बैठकें हुई हैं, खासकर पिछले दो-तीन माह में तो बैठकों का सिलसिला निरंतर चला है। सवाल यह कि आखिरकार यह गतिरोध टूटा कैसे? यह सही है कि बीजिंग आक्रामक जिद्दी प्रतिद्वंदी है, लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि समझौता करने के लिए वह अपनी घरेलू चुनौतियों से प्रभावित हुआ है, विरोधस्वरूप धीमी होती अर्थव्यवस्था और अत्यधिक सैन्यीकृत सीमा को कायम रखने के खर्च से बीजिंग की निगाह इस बात पर भी लगी हुई थी कि नई दिल्ली के वाशिंगटन से स्ट्रेटेजिक व सैन्य संबंध गहरे होते जा रहे हैं और रक्षा व्यापार भी धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है।

बीजिंग के दिमाग में यह भी है कि इस्लामाबाद भी वाशिंगटन की तरफ बढ़ता जा रहा है। दरअसल, पाकिस्तान ने चीन को कुंठित कर दिया है, चीन के प्रिय सीपीईसी प्रोजेक्ट को गति न देकर और चीनी वर्कर्स व इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित न करके, जो दोनों ही अतिवादी तत्वों का निशाना हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर बताया गया, विश्व दो खेमों में विभाजित होता जा रहा है, पश्चिम को चुनौती देने के लिए रूसी खेमे को भारत की जरूरत है, जिसके लिए आवश्यक था कि भारत व चीन के बीच सीमा विवाद का हल निकले और इन दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हों। इधर नई दिल्ली भी बीजिंग से समझौता करके वाशिंगटन को संदेश देना चाहता था कि वह पनून और निज्जर (कनाडा के जरिये) के बेबुनियाद केस उछालकर उसे 'पार-ग्रेटेड' न ले।

संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर उठते सवाल

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी
चेयर प्रोफेसर, केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा, पंजाब

विश्व आज परिवर्तन के दौर में है। इस दौर में संयुक्त राष्ट्र ने भविष्य की खोज के लिए एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया। इस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार हिबाकुशा को मिला, जिसकी मंशा है कि संपूर्ण विश्व परमाणु शस्त्र विहीन बन जाए और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिले। विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार उत्पादक देश अमेरिका, रूस और चीन इस संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। वीटो पावर इनके पास है। विश्व में अपनी बेहतर छवि बनाने का प्रयास संयुक्त राष्ट्र ने अब तक किया है। विश्व शांति एवं मानवाधिकारों के साथ सतत विकास के लक्ष्य हों या जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने की कवायद, इन सब पर संयुक्त राष्ट्र इन्हीं देशों के चंदे से अपने हर वक्तव्य के साथ खड़ा होता है।

पिछली सदी के अंतिम दशक में इंफाक में जो कोहराम मचा, वह किसी से छुपा नहीं है। आज यूक्रेन और रूस के हालात हैं या गाजा संकट हो, बेबस संयुक्त राष्ट्र केवल एक अपील एजेंसी बन गया है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र को लेकर उभरी नकारात्मक छवि को ठीक करने का उपाय संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस के पास नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय है। इस समय मानवाधिकारों के हनन, शरणार्थियों की समस्या और अनागरिक होने का संकट भी है। भूख, स्वास्थ्य और गरीबी से जूझती तीसरी दुनिया के लोग अपनी लाचारगी लिए घूम रहे हैं। अफगानिस्तान और म्यांमार में महिलाओं एवं शरणार्थियों के संकट, बांग्लादेश में तख्तापलट व असंतोष संयुक्त राष्ट्र के लिए भी हैं, क्योंकि उसने जो एमडीजी से एसडीजी-2030 की जो यात्रा तय करने का सोचा था, वह अब लक्ष्य से बहुत दूर जा चुकी है।

संयुक्त राष्ट्र अब यह सोच रहा है कि चंदे देने से ना-नुकुर करने वाले देश अपना वित्तीय पोषण करने से यदि हाथ पीछे कर लेंगे तो उसके साथ जुड़े मानव संसाधन का क्या होगा? इस समय संयुक्त राष्ट्र के सामने यह एक चुनौती है कि जलवायु परिवर्तन के लिए व्यापक सहयोग हो और सतत विकास लक्ष्य को हासिल किया जाए, लेकिन बहुत से देश सतत विकास लक्ष्य-2030 के लिए कोई व्यवस्थित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हैं। वैसे आज बहुत ही सुनियोजित ढंग से विश्व में पृथ्वी की चिंता हो रही है और वहीं दूसरी ओर युद्ध भी हो रहे हैं, हथियार निर्यात किए जा रहे हैं, परंतु संयुक्त राष्ट्र कुछ करने की स्थिति में नहीं है। कई देशों की जब सुरक्षा परिषद में विस्तार के लिए पहल हुई तो कुछ छोटे देशों ने सहयोग करने को कहा, लेकिन भारत के पक्ष में स्वयं चीन ने कई बार वीट करने से मना कर दिया। संयुक्त राष्ट्र विस्तार की पहल भी नाकाम दिख रही है। आज जब विश्व में कई तरह की समस्याएं हैं, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार आवश्यक हो गया है। यदि ऐसा हो जाए तो कई मामलों पर एकाधिकार वाली स्थिति को रोका जा सकता है।

आज समस्या यह है कि 24 अक्टूबर, 1945 को जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तो उस समय की प्रतिबद्धताएं अब बहुत पीछे छूट गई हैं। वह समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नए पुनरुत्थान के लिए समर्पित होकर शांति व विकास की यात्रा के लिए था। विकास की गतिशीलता को व्यापक पैमाने पर ले जाने की प्रतिबद्धताएं निजी हितों में भी देखी जा रही हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र से निराश होती भारत और विश्व की आबादी इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि हमारे लिए कब ऐसा पल आएगा जब संयुक्त राष्ट्र अपनी निष्ठा के साथ विश्व में शांति और सम्मान दिलाने में कामयाब हो सकेगा। एक बात यह तय है कि यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार नहीं किया गया तो वह अपने लक्ष्य को हासिल करने से कोसों दूर रह जाएगा।

खरी-खरी

कुर्सी पर वफादारी की खड़ाऊं

रेखा शाह आरबी

सियासत और वफादारी ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। अगर सियासत में वफादारी निभाई जाए तो वह खतरे में पड़ जाती है। और सियासत निभाई जाए तो वफादारी खतरे में पड़ जाती है। इनका जन्म ही गठबंधन होता है जबरदस्ती का ही होता है। इसके अनेक उदाहरण राजनीति में भरे हैं। वैसे कुछ लोगों के नसीब में जब राहु केतु और शनि की एक साथ युति होती है, तो मजबूरी में ही सही, सियासत में भी वफादारी दिखनी पड़ जाती है। यह सब कुछ कुर्सी के लिए होता है। और कुर्सी न किसी की सगी होती है, न कभी सगी होगी। जब मौका मिला, जिसको मौका मिला, उसी की हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक नेता को सबसे ज्यादा और सबसे पहले अपनी कुर्सी की चिंता होती है। उसके बाद देश दुनिया और अपने कार्यकर्ताओं की चिंता होती है। लेकिन कभी-कभी बाजी ऐसी पलटती है कि नेता को अपनी कुर्सी भी दूसरे को देनी पड़ती है। अब वह किस मन से देता है यह मन कोई नहीं समझ सकता। और जब ऐसी स्थिति में कोई नेता आता है तो वह अपने सबसे विश्वस्त व्यक्ति को ही अपनी कुर्सी अमानत के तौर पर दे देता है। उसका विश्वस्त व्यक्ति भी उस कुर्सी को अमानत समझकर उस पर स्वयं न बैठकर अपने मलिक के खड़ाऊं को रखकर राज-काज चलाता है।

परंतु देख गया है कि कुर्सी तो स्वयं ही बेवफा प्रेमिका की भांति है तो वह वफादारी कैसे निभा सकती है। जब कुर्सी पर खड़ाऊं बैठी होती है तो कभी लुढ़क कर इधर गिरती है, कभी लुढ़क कर उधर गिरती है। बहुत मुश्किल से कुर्सी पर वह अपना स्थूलन बना पाती है। खड़ाऊं से ज्यादा लुढ़कने का चांस उसको देखभाल करने वाले की होती है। जैसे ही मौका मिलता है पहली फुर्सत में खड़ाऊं को नौ दो ग्यारह कर देता है और स्वयं उस पर काबिज हो जाता है। इसमें न तो खड़ाऊं का कोई दोष होता है, न ही खड़ाऊं रखने वाले का दोष होता है। कुर्सी है ही ऐसी चीज कि किसी को टिकने नहीं देती है। सबको वफादारी को पलीता लगा देती है।

पोस्ट

नेता राजनीति के लिए कह देते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, लेकिन आखिर उन बच्चों को खिलाएगा कौन?
मनु गौर@mgtaxab

बोतल फूटे या अंगुली टूटे। चोट बैक का साथ न छूटे। देश की राजनीति में जो नेता रचनात्मक योगदान नहीं दे पाते, वे मीडिया की हेडलाइंस में आने के लिए कितना फूहड़ काम करते दिखते हैं। राजनीति में बढ़ती इस दरिद्रता पर तरस आता है।
नवनीत मिश्रा@navneetmishra99

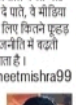

अप्रैल 2023 में जारी दिल्ली सरकार के दस्तावेज कहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए अलग-अलग विभागों की तरफ से 2017-18 और 2020-21 के बीच कुल 6,856.9 करोड़ रुपये खर्च किए गए। फिर भी दिल्ली तेरी यमुना मैली हो गई!
रुबिका लियाकत@RubikaLiyaquat

जामिया मिलिया में हिंदू छात्रों का दीवाली मनाना लोगों को अखर गया और फलस्तीन के समर्थन में नारे लगाते हुए जलते हुए दीपकों को जूतों से तौड़ दिया गया। याद रहे कि इस यूनिवर्सिटी की तनख्वाह से लेकर ग्रांट तक और बिजली से लेकर पानी तक हमारे टैक्स के पैसे से दिया जाता है।
अनुपम मिश्रा@scribe9104

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को वहाल किए जाने की मांग सही है?

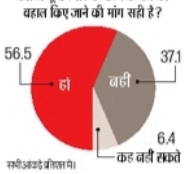

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या भारत को चीन के साथ अपने संबंध सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए?

घरिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

'अनुभव' देने में गई गुजर पीढ़ियां चार,
फिर भी उनकी पार्टी रही हार पर हार।
रही हार पर हार वहन जी अबहैं आई,
जब भाई की फौज पार सी ना कर पाई।
रही लड़ती आस सदा प्रत्याशी नव-नव,
लौ जाकर वायनाड जरा लड़ने का अनुभव!
- ओमप्रकाश तिवारी

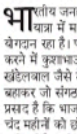

धनंजय प्रताप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

राजनीति में भाजपा का नवाचार

भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान रहा है। पार्टी का कैडर खड़ा करने में कुशाभाऊ ठाकरे या प्यारेलाल खंडेलवाल जैसे नेताओं ने पसीना बहाकर जो संगठन खड़ा किया, उसी का प्रसाद है कि भाजपा 2003 के बाद से चंद महीनों को छोड़कर लगातार सत्ता में बनी हुई है। नई सदी के पांच विधानसभा चुनाव में भाजपा ने चार में जीत दर्ज की। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटें भाजपा की झोली में आई हैं। यह रिकार्ड तो भाजपा का चुनावी राजनीति का है, लेकिन यदि पार्टी को संगठनात्मक पकड़ और क्षमता की बात करें तो भी मध्य प्रदेश ने भाजपा को कई ऐसे नवाचार दिए, जो देशभर में लागू किए गए हैं। पन्ना प्रमुख के नवाचार में मध्य प्रदेश की ही देन है।

वर्ष 1993 में मुस्लिम बहुल सीट भोपाल उत्तर में पहली बार पन्ना प्रमुख बनाए गए थे। उस समय रमेश शर्मा गुड्डू भैया भाजपा के प्रत्याशी थे, तब इसी नवाचार की बदौलत पहली बार मुस्लिम बहुल सीट से कोई हिंदू प्रत्याशी चुनाव जीता था। इसके बाद जब भोपाल दक्षिण से उमाशंकर गुप्ता वर्ष 2013 में भाजपा प्रत्याशी थे, राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल इस बैठक में शामिल होने भोपाल आए। गुप्ता ने बैठक व्यवस्था भी पन्ना प्रमुख के हिसाब से की थी। रामलाल पन्ना प्रमुख के इस नवाचार को देखकर आश्चर्यचकित थे, उन्होंने कहा कि हम जो करना चाहते थे, वह मध्य प्रदेश ने आरंभ कर दिया। फिर यह व्यवस्था पूरे देश में लागू कर दी गई।

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां भाजपा ने 64,871 बूथों का डिजिटाइजेशन किया था। यानी बूथ कमेटी और मतदाताओं का पूरा ब्यौरा आनलाइन किया गया था। प्रदेश संगठन की इस उपलब्धि को देखकर ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जून 2023 में 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को चुना। इस कार्यक्रम में देशभर के बूथ कार्यकर्ता आए थे और ऐसे एक लाख कार्यकर्ताओं ने बूथ में रहकर उसकी कार्यपद्धति सीखी व अपने राज्यों में जाकर इसे लागू किया। कैडर आधारित पार्टी होने का भाजपा की यही मजबूती उसे चुनाव में सफलता दिलाती है। अब इस वर्ष मध्य प्रदेश भाजपा ने एक नवाचार किया है, वह है- आइ एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स। वस्तुत: यह प्रधानमंत्री मोदी का विजन था कि एक लाख गैर राजनीतिक प्रोफेशनल्स को राजनीति में लाया जाए, ताकि वे 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभा सकें।

इंदौर में सदस्यता अभियान के लिए आयोजित सम्मेलन में शामिल प्रोफेशनल्स। भाजपा

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने सदस्यता अभियान के तहत पांच अक्टूबर को भोपाल के रविंद्र भवन में इस अभियान का श्रीगणेश किया। इसमें डेढ़ सौ प्रोफेशनल्स को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। इसके बाद उज्जैन, जबलपुर और इंदौर जैसे बड़े शहरों में भी बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स को भाजपा से जोड़ा गया। भाजपा की दिल्ली में सदस्यता की बैठक में जब इस 'आइ एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स' के बारे में विष्णु दत्त शर्मा ने बताया तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने केवल प्रशंसा ही नहीं की, बल्कि देश के अन्य राज्यों में इसे लागू करने का निर्देश भी दिया। 'आइ एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स' अभियान राजनीति में शुचिता लाने का एक प्रयास है।

इस प्रयास की पृष्ठभूमि में जाएं तो पता चलेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ-वैचारिक संगठन प्रज्ञा प्रवाह की भोपाल में एक बड़ी बैठक हुई थी। इसमें सरसंघचालक डा. मोहन भागवत भी उपस्थित थे। यहां तय किया गया था कि राजनीति में शुचिता लाने के लिए गैर राजनीतिक लोगों को भागीदारी पार्टी में बढ़ाई जाना चाहिए। बैठक के कुछ समय बाद नगरीय निकाय के चुनाव हुए तो भाजपा ने इंदौर में पुष्यमित्र भार्गव और जबलपुर में डा. जामदार को महापौर का टिकट दिया। भाजपा राजनीतिक शुचिता के लिए अब राजनीति में सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी में है।

मध्य प्रदेश में मिशन-2028 की तैयारी में जुटी पार्टी इस बार अपने टिकट बांटने के फार्मूले में बदलाव करेगी। पार्टी टिकट चयन में सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शामिल न कर प्रोफेशनल्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच से भी बेहतर छवि वाले लोगों को प्रत्याशी बनाएगी। पार्टी की तैयारी 10 से 15 प्रतिशत टिकट समाज के बीच काम करने वाले अच्छे लोगों को देने की है। भाजपा ने 'आइ एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स' के जरिए इस पर काम करना आरंभ भी कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का मानना है कि इससे आने वाले समय में राजनीति में भ्रष्टाचार, अहंकार और जनता से दूरी बनाकर रहने वाले नेताओं से मुक्ति भी मिलेगी और समाज के लोगों की भागीदारी भी राजनीति में बढ़ेगी। समाज में जो अच्छा काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भाजपा ने राजनीतिक क्षेत्र में एक बढ़िया प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया है। 'आइ एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स' से आने वाले समय में राजनीतिक शुचिता लाना है, यह लक्ष्य अब मध्य प्रदेश भाजपा का है।

मंथन

मुस्लिम ओबीसी आरक्षण की समीक्षा

देश के अनेक राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है कि लगभग संपूर्ण मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में शामिल कर दिया गया है, जिससे उन्हें आरक्षण की सुविधा मिल रही है। ऐसे में मुस्लिम ओबीसी आरक्षण की समीक्षा आवश्यक है

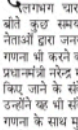

मनीष त्रिपाठी
वरिष्ठ पत्रकार

देश में जनगणना का कार्य पिछले लगभग चार वर्षों से लंबित है। बीते कुछ समय से विपक्ष के कई नेताओं द्वारा जनगणना के साथ जातीय गणना भी करने की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में ऐसा किए जाने के संकेत दिए हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि जातीय गणना के साथ मुस्लिम जातियों की भी जातीय गणना की जा सकती है। केंद्र सरकार यदि इस पर अमल करती है तो वर्ष 2025 में पहली बार सामान्य जातीय गणना के अनुसार मुस्लिम समुदाय के जातियों की भी गणना होगी।

वैसे इस मामले में एक विडंबना यह है कि जातीय गणना का सीधा संबंध विपक्षी पार्टियों आरक्षण की मांग से जोड़ती आ रही हैं। आरक्षण का मुद्दा भारत में समय समय पर उठता रहता है। आरक्षण खतरे में है, इसे मुद्दा बनाने के लिए कांग्रेस सहित विपक्ष ने तमाम नैरेटिव गढ़े हैं। ऐसे में यह भी समझा जाना चाहिए कि ओबीसी आरक्षण कोटे में भारत की कई राज्य सरकारें सेंधमारी कर रहे हैं। कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जहां राज्य सरकारें संपूर्ण मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में शामिल करने की कोशिश कर रही हैं। यद्यपि कुछ प्रदेश सरकारों को ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को शमिल करने में सफलता भी मिल रही है। कुछ में कोटे के चलते मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने में कामयाबी नहीं मिली है।

तुष्टीकरण : कुछ दिनों पहले बंगाल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे का जिक्र किया जिसमें सरकार द्वारा 78 ओबीसी जातियों में से 77 ओबीसी जातियां मुस्लिम बताई गई हैं। जाहिर है, यहां ममता सरकार के फैसले से मुस्लिम जनसंख्या ओबीसी आरक्षण का हक मारती नजर आ रही हैं। वैसे फिलहाल कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। सत्ता पक्ष के अनुसार ओबीसी वोट के लिए ओबीसी गणना करने की मांग विपक्ष की कोरी राजनीति है, जबकि सच्चाई यह है कि विपक्ष द्वारा ओबीसी के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ओबीसी आरक्षण का उपयोग मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। वैज्ञानिक तरीके से समाजिक पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी जातियों की पहचान कर संविधान में उन्हें आरक्षण का अधिकार दिया गया है, लेकिन बंगाल में मुस्लिम जातियों को ओबीसी की सूची में उसी दिन शामिल कर लिय गया जिस दिन उनका आवेदन आया था। यानी उनके पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक सर्वे नहीं किया गया।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ओबीसी आरक्षण तुष्टीकरण की राजनीति के लिए है? दोहरेपन की बात यह है कि एससी, एसटी और ओबीसी की बात करने वाले आइएनडीआइए में शामिल कांग्रेस की तेलंगाना सरकार, कर्नाटक सरकार और ममता बनर्जी की सरकार मुस्लिम आरक्षण को ही बढ़ाने के लिए ओबीसी समाज के असली हक को ही मार रही हैं। इन राज्यों में हिंदू ओबीसी के अधिकारों को छीनकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण किया जा रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले भी बंगाल सरकार द्वारा 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत करने को रद कर दिया था व 2010 के बाद बंगाल में जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर ममता सरकार से जवाब मांगा है कि उसने किस आधार पर मुस्लिम जातियों को यह कोटा दिया है।

अन्य कई राज्यों की स्थिति : वहीं देश के कई राज्य ऐसे हैं, जहां मुस्लिमों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। केरल में ओबीसी को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। इसके अंदर ही कुछ कोटा मुस्लिमों के लिए भी है। यहां मुसलमानों को नौकरियों में आठ प्रतिशत और उच्च शिक्षा में 10 प्रतिशत का कोटा मिलता है। तमिलनाडु में भी मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है। यहां पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 3.5 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कोटे में मुसलमानों की 95 प्रतिशत जातियां शामिल हैं। इसी तरह बिहार में मुसलमानों की कुछ जातियों को 'अति पिछड़ा वर्ग' में शामिल किया गया है। अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों और उपजातियों को 18 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। बिहार में हुए जातिगत सर्वे में 73 प्रतिशत मुसलमानों को 'पिछड़ा वर्ग' माना गया था। देश भर में आरक्षण के मामले को तूल पकड़ते हुए देख राजस्थान सरकार ने भी राज्य में दिए जा रहे मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। वहीं हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को जो आरक्षण मिल रहा है, उस पर यहां की सरकार मौन साधे हुए है।

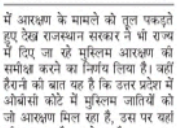

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुस्लिम ओबीसी जातियों को आरक्षण पर उठाए हैं सवाल। फाइल

ऐसे में देश को इतिहास के वर्ष 1909 के उस कटु अध्याय को नहीं भूलना चाहिए, जिसमें मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत विधान परिषदों, विधानसभाओं में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की शुरुआत की गई थी, जिसने अलगववाद को जन्म देकर भारत विभाजन की नींव रखी थी।

****

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 24 अक्टूबर • 2024
www.rashtriyasahara.com

बचकानी हरकत

वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय बैठक में तीखी बहस हुई। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने गुस्से में कांच की बोतल तोड़ कर फेंकी जो समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पॉल को लगी जिससे वह चुटहिल होने से बाल-बाल बचे। पॉल ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। वह सारी सीमाओं को लांघ गए थे। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पॉल चार बार लोक सभा सांसद, पांच बार विधानसभा और विधान परिषद में रहे हैं। उनका कहना है कि चालीस वर्ष के संसदीय कॉरिअर में वे कई कमेटियों के सदस्य भी रहे हैं। हमेंमें मतभेद भी रहे परंतु ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं कर सकते। बनर्जी पर गाली-गलौच के भी आरोप हैं। बोतल तोड़ने के दौरान क्रोधित बनर्जी को भी अंगूठे और तर्जनी में चोट आई। कमेटी ने

फौरन ही उन्हें एक दिन की बैठक से निलंबित करने का फैसला किया। तीन बार सांसद चुने गए कल्याण बनर्जी को पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। गोया संसद में सरकार और सुधार का रवैया वैश्विक संघर्ष और चुनौतियों के बावजूद भारत के लिए नये अवसरों का आधार है। गौरतलब है कि विगत 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रूस-यूक्रेन और इस्राइल-ईरान युद्ध की अनिश्चितता के बीच भी दुनिया का भारत पर असाधारण आर्थिक विश्वास बना हुआ है। मोदी ने कहा कि दुनिया की नजरों में यह युग भारत का युग है। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

दुनिया में भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन के मामले में पहले क्रम पर है। इंटरनेट उपभोक्ताओं के मामले में दूसरे क्रम पर है, स्टार्टअप के मामले में तीसरे क्रम पर है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे क्रम पर है। इतना ही नहीं, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और मूडीज जैसी वैश्विक एजेंसियां भी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत को दुनिया की सबसे विश्वसनीय और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ-साथ निवेश के पसंदीदा देश के रूप में देख रही हैं। बशर्ते इस समय पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध के विस्तारित होने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास और तेज विकास के मद्देनजर देसी उद्यमियों के साथ वैश्विक उद्यमियों के लिए भी बढ़ते अवसरों का परिदृश्य उभर कर दिखाई दे रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि हाल में दुनिया की ख्यातिप्राप्त वित्तीय सेवा फर्म मॉर्गन स्टेनली ने कहा है कि सितम्बर, 2024 के दौरान भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए खुद को निवेश की पसंदीदा जगह बना लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में एशियाई विकास

बैंक (एडीबी) ने अपनी नई रिपोर्ट-2024 में कहा है कि भारत आर्थिक विकास, विदेशी निवेश और नई तकनीकों के उपयोग की ऊंची संभावनाओं वाला देश है। अमेरिका चेंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में अमेरिका की कंपनियों की वैश्विक निवेश पसंदगी में भारत का दूसरा स्थान है। इस समय चीन अमेरिकी निवेशकों की प्राथमिकता खोता जा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका और चीन में बढ़ते तनाव के माहौल में इस समय चीन में कार्यरत 12 लाख करोड़ रुपये निवेश वाली 50 अमेरिकी कंपनियां अपना कारोबार चीन से समेटने की तैयारी में हैं। इन कंपनियों में से 15 कंपनियां भारत में निवेश की तैयारी कर रही हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विगत 23 सितम्बर को प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क में एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर काम करने वाली 15 प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बहुआयामी क्षेत्रों में दुनिया के लिए अपार आर्थिक मौके हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि अब भारत को आर्थिक दुनिया के उभरते सितारे के रूप में देखा जा रहा है, जो भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय साख को दर्शाता है। वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मंचों पर भारत को विशेष अहमियत भारत की आर्थिक स्थिति से भी मिल रही है। अमेरिका और रूस, दोनों महाशक्तियों के साथ भारत की मित्रता के नये अध्याय दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा एवं भारतीय बाजार में मौके बढ़ा रहे हैं।

निस्संदेह भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कृषि विकास और बढ़ती ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश-दुनिया के कारोबारियों और निवेशकों के लिए मौकों का नया द्वार खोल रहे हैं। देश में खाद्यान्न उत्पादन ऊंचाई बना रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक अब देश की खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ वैश्विक खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने के लिए भारत रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है। अब भारत दुनिया के खाद्य कटोरे के रूप में रेखांकित हो रहा है। भारत दुनिया के 150 से अधिक देशों को खाद्य पदार्थों के निर्यातक देश के रूप में दुनिया में रेखांकित हो रहा है। भारत दुनिया का आठवां बड़ा कृषि निर्यातक देश बन गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय शेयर बाजार ऊंचाई पर है, और दुनिया के लिए भारतीय शेयर बाजार में मौके बढ़ रहे हैं।

वर्ष 2024 की शुरुआत से भारत में आईपीओ का बाजार गुलजार है। भारत में म्युचुअल फंड (एमएफ) में निवेश छलांगें लगा कर बढ़ रहे हैं। अगस्त, 2024 तक डीमैट खातों की संख्या 17.10 करोड़ के पार हो गई है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि विदेश व्यापार में भारत की नई संभावनाएं दुनिया के लिए नये मौके के रूप में हैं। 'चीन प्लस वन' रणनीति के तहत भारत दुनिया के सक्षम और भरोसेमंद देश के रूप में वैश्विक आपूर्ति शृंखला में नई भूमिका निभा रहा है।

हम उम्मीद करें कि इस समय पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध के विस्तारित होने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट के दौर के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी बहुआयामी विशेषताओं के कारण मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। साथ ही, आर्थिक विकास के रणनीतिक प्रयासों से भारत में विकास का अध्याय आगे बढ़ता जाएगा। साथ ही, रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। इससे देश 2027 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 में विकसित भारत बनने की डगर पर आगे बढ़ेगा।

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

भारतीय अर्थव्यवस्था

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

दुनिया में भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन के मामले में पहले क्रम पर है। इंटरनेट उपभोक्ताओं के मामले में दूसरे, स्टार्टअप के मामले में तीसरे और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे क्रम पर हैं। विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और मूडीज जैसी वैश्विक एजेंसियां भी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत को दुनिया की सबसे विश्वसनीय और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ-साथ निवेश के पसंदीदा देश के रूप में देख रही हैं

चीन को पछाड़ने की राह पर

ब्रिक्स का संदेश

इस सप्ताह भारत के लिहाज से सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय घटना रूस (कजान) में आयोजित 16वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर हुई थी। बाद में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया। अमेरिका और पश्चिमी देशों के घटते वैश्विक प्रभाव के कारण विभिन्न महाद्वीपों के अनेक देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। इन देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया तो यह संगठन अमेरिका के प्रभाव वाले जी-7 से भी मजबूत हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका और पश्चिमी देशों का सशंकित होना स्वाभाविक है। उनकी आशंका को देखकर प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ा है कि ब्रिक्स पश्चिम विरोधी नहीं, बल्कि गैर-पश्चिम संगठन है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स विभाजनकारी नहीं, जनहितकारी है।

राष्ट्रपति पुतिन ने फरवरी 2024 में अमेरिका के जाने-माने न्यूज एंकर टकर कार्लसन को दिए अपने साक्षात्कार में ब्रिक्स देशों की बढ़ती ताकत का जिक्र किया था तथा अपनी अध्यक्षता के दौरान इसकी भूमिका की भी चर्चा की थी। पुतिन ने ब्रिक्स के एजेंडे को व्यापक रूप देने का प्रस्ताव दिया है। इसमें ब्रिक्स देशों के बीच अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी कम करने के लिए नई मुद्रा का प्रचलन करना बहुत जटिल और दुरूह प्रक्रिया है। इसी बात को ध्यान में रखकर स्थानीय मुद्रा यानी विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं में लेन-देन की व्यवस्था लागू करना शामिल है। लेकिन कुछ अर्थों में यह मुद्दा भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह रूस से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात कर रहा है। रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के कारण लेन-देन की समस्या पैदा हो रही है। यही संभावना है कि बुधवार को कजान में जारी घोषणापत्र में कोई ठोस भुगतान प्रणाली कायम करने की घोषणा हो जाएगी। अगर बाद में सदस्य देशों के बीच कोई सहमति बन पाती है, तो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पश्चिमी देशों को मजबूत चुनौती मिल सकती है। रूस में हो रही ब्रिक्स शिखर वार्ता नई विश्व व्यवस्था का शिलान्यास साबित हो सकती है। अब ब्रिक्स नेताओं को चट्टान जैसी संकल्पशक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए।

कटाक्ष/ सहीराम

हासिल रहा क्या?

इधर लॉरेंस, उधर लॉरेंस। लॉरेंस पंजाब में है, हरियाणा में है। मुंबई में है और अहमदाबाद जेल में तो है ही। बल्कि लॉरेंस तो विदेश में भी है। कनाडा, इंग्लैंड में हो सकता है। न्यूयार्क, वाशिंगटन में भी हो सकता है। लॉरेंस सर्वव्यापी है। देश में है, विदेश में है। जेल में भी है और बाहर भी है। राजनीति में है, मीडिया में है। अंडरवर्ल्ड में तो है ही। जरूर बॉलीवुड में भी होगा। बल्कि किसी दिन हॉलीवुड में भी हो सकता है। वह सर्वव्यापी है। सुरक्षा के लिए खतरा भी है और खुद सुरक्षा भी है। वह गृह नीति में है। बल्कि अब तो विदेश नीति में भी है। कहां नहीं है। सर्वव्यापी है। उसके सात सौ शूटर हैं। एक पूरी विग्रेड, पूरी बटालियन, पूरी फौज है। वह एक टुच्चे से बदमाश, करन्वर्ड गुंडे से रॉबिनहुड बनने की दिशा में बढ़ चला है। सलमान को धमकी देने के बाद, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उसे जिस तरह से दाऊद इब्राहिम के मुकाबले खड़ा किया जा रहा है, लगता है कि एक दिन अवश्य ही हिन्दू हृदय सम्राट बनेगा। उस दिशा में उसने कदम बढ़ा दिए हैं। धर्म का रक्षक बनेगा।

बस गनीमत यही है कि सर्वव्यापी होकर भी अभी भगवान नहीं बना है। बन जाएगा। एक दिन भगवान भी बन जाएगा। अभी सिर्फ रॉबिनहुड ही बना है। अगली मंजिल हिन्दू हृदय सम्राट बनने की है। फिर हो सकता है एक दिन भगवान भी बन जाए। जब डेरों और मठों के बाबे भगवान बन सकते हैं तो उसके पास तो सात सौ शूटर हैं। वे भगवान बनने में हर अड़चन दूर कर सकते हैं। जानकारों ने अभी उसके शूटरों की ही संख्या खंगाई है। यह संख्या इस वर्ष की है। अगले साल यह दोगुनी, चार गुनी हो सकती है क्योंकि ज्यों-ज्यों बेरोजगारी बढ़ेगी त्यों-त्यों उसके शूटर बढ़ेंगे। बहरहाल, जानकारों ने यह नहीं बताया कि उसके फोलोवर कितने हैं। फेसबुक, ट्विटर आदि पर अगर वह सक्रिय है तो उसके फोलोवर किस गति से बढ़ रहे हैं, यह बताया जाना चाहिए। लेकिन यह जरूर पता चल रहा है कि गृह नीति से अब वह विदेश नीति तक पंहुच गया है। अभी भारत-कनाडा के विगड़े रिश्तों में ही उसका नाम आ रहा है। आगे हो सकता है उसका और क्षेत्रों में भी नाम आए। कोई पूछे कि घर में घुस कर मारने की विदेश नीति का हासिल क्या रहा तो जवाब होना चाहिए-हासिल रहा जी लॉरेंस बिश्नोई। नहीं क्या?

निंदा

डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी

एक बार भगवान बुद्ध ने शिष्यों के एक कथा सुनाई, 'एक गांव में एक वृद्ध श्रद्धालु महिला थी। उसका नियम था कि जब भी

गांव में साधु-महात्मा आते तो वह उन्हें भोजन कराती। एक बार भंडारे के लिए उसके घर के बड़े खुले आंगन में खाना बनाया जा रहा था। तभी आसमान में उड़ती हुई एक चील आंगन के ऊपर से होकर गुजरी। उसने अपने पैर से मरा हुआ सांप पकड़ रखा था। सांप के मुंह से जहर टपक रहा था। जहर की बूंदें खाने में गिर गईं। उस भोजन को खाने वाले अनेक तीर्थवासी संन्यासी मर गए। इस घटना को लेकर गांव के लोग उस वृद्धा को जिम्मेदार ठहराने लगे-'बुढ़िया ने साधुओं को जहर देकर मार डाला!' जब भी भिक्षुओं का कोई संघ गांव में आवास-भोजन की मांग करता तो गांव वाले कहते, 'इस गांव में एक बुढ़िया रहती है, वहां जाओ। सीधा मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा।' फिर वही किस्सा सुनाते और वृद्धा को दोषी और हत्यारी कहते।' बुद्धा के वर्षों के अच्छे कर्म और सेवा पर एक दुर्घटना ने पानी फेर दिया जिसमें उसका कोई दोष नहीं था। जनता प्रायः सच और झूठ के मूल में जाना नहीं चाहती। इस परिस्थिति में निंदकों की लॉटरी लग जाती है। वे युक्तिपूर्वक उस बुरहें पर चर्चा करते हुए अच्छहें को भी बुराई में तब्दील करने का हुनर रखते हैं। ऐसे निंदक तत्त्व हर किसी के पवित्र जीवन में से भी गलती ढूंढकर या मक्खन उस पर कीचड़ उछालते रहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को यही समझाते हैं-'अर्जुन! तुम्हारे अतुलनीय प्रभाव के कारण अब तक लोग तुम्हारा आदर करते आए हैं। किंतु यदि इस युद्ध से तुम विरत हो जाते हो तो वे तुम्हें भय से भगोड़ा और युद्ध से विमुख समझेंगे।' महंत स्वामी महाराज समझाते हैं कि उस समय अर्जुन की उपलब्धि, यश, प्रतिष्ठा, विजय, सम्मान आदि आसमान छू रहे थे। इसीलिए यदि उसने एक बार भी (युद्ध न करने की) छोटी-सी भी भूल की (भले ही भूल कर) तो लोगों द्वारा वर्षों तक इतनी निंदा की जाएगी कि...अर्जुन को मृत्यु उससे भी अधिक प्रिय लगेगी। जी हां, निंदा का गान और अवगुण का बखान करना बहुत आसान है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इससे समाज का कितना नुकसान होता है?

रीडर्स मेल

मिलावटी खानपान का बढ़ता जोर

त्योहारों के मौसम में खाद्य पदार्थों में मिलावट का कारोबार खास तौर पर मिठाइयों में ज्यादा जोर पकड़ता है। समाज में बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जो अपने थोड़े से फायदे के लिए खाने-पीने की चीजों में मिलावट करके दूसरों की जान तक जोखिम में डाल देते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि एक तो आमजन सरकार द्वारा लगाए गए उपभोक्ता संरक्षण के कानूनों के प्रति जागरूक नहीं है, दूसरा, सरकार और प्रशासन मिलावट रोकने के लिए गंभीरता नहीं दिखाते और तीसरा, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कारण ही खाद्य पदार्थों की जांच समय-समय पर नहीं होती। सरकार और प्रशासन को भी आमजन को सेहत की सुरक्षा के लिए गंभीरता दिखानी चाहिए, बाजार में बिकने वाली चीजों की समय-समय पर जांच करनी चाहिए। कहना उचित होगा कि विज्ञापनों के भ्रम में आकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना सरासर गलत है। आज मीडिया समय-समय पर मिलावटी या बनावटी खाने-पीने की चीजों से सेहत पर होने वाले नुकसान का खुलासा करता रहता है, इस पर सबको अमल करना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

खेल आयोजकों का मोहभंग

क्या सचमुच बढ़ती महंगाई एवं जीवन यापन की लागत में लगातार हो रही वृद्धि ने क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं उसके आयोजकों का मोहभंग करना शुरू कर दिया है? सबसे पहले ऐसी घटना घटी थी 52 साल पहले जब 1972 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स खेलों को आयोजित करने से अमेरिका के डेनवेर कोलारादो शहर ने मना कर दिया था। उसके बाद जुलाई, 2023 में विक्टोरिया (ऑस्ट्रेलिया) ने घोषणा की कि वह अप्रत्याशित लागत वृद्धि के कारण 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी नहीं करेगा। 23 जुलाई, 2026 से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता में कई महत्त्वपूर्ण एवं लोकप्रिय खेलों को हटा दिया गया है। हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, डाइविंग, रग्बी सेवन्स, बीच वॉलीबॉल, माउंटेन बाइकिंग, स्क्वैश और रिदमिक जिमनास्टिक जैसे कई प्रमुख खेलों को हटा दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि आधा से अधिक पदकों की संख्या अब कम हो जाएगी। आधे से अधिक प्रतियोगी भी इन आयोजनों से दूर हो जाएंगे। क्या अब इन छोटे आयोजनों को दर्शक मिल पाएंगे? क्या आगे चल कर खेल प्रतियोगिताओं के अंत की शुरुआत हो चुकी है?

जंगबहादुर सिंह, जमशेदपुर

क्या हिम्मत दिखाएंगे राहुल

सक्रिय राजनीति में 2004 में 'आँल इज वेल' के चश्मे के साथ पदार्पण करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा हरियाणा की हार की समीक्षा बैठक में की गई टिप्पणी 'नेताओं ने अपने हितों को पार्टी से बड़ा समझा', उनकी 2024 में राजनीतिक परिपक्वता का प्रमाण है। पर क्या यह पहली बार हुआ है? वस्तुतः राज्य-दर-राज्य कांग्रेस अपने क्षत्रपों की कटपुतली बन गई है। रही-सही कसर ईडी गठबंधन के पारिवारिक क्षत्रप पूरी कर दे रहे हैं। अब जबकि राहुल गांधी यह समझ भी चुके हैं, देखना होगा कि वह कांग्रेस-ईडी गठबंधन के क्षत्रपों के इस चक्रव्यूह को तोड़ पाने का साहस जुटा पाते हैं या नहीं?

मनोज श्रीवास्तव, सुल्तानपुर, उप्र
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

अनमोल वचन

छोटा आरंभ करो, शीघ्र आरंभ करो
-रघुवंश महाकाव्यम्

एक्यूपंचर को हेल्थ थेरेपी के रूप में मान्यता

- एक्यूपंचर को अब स्वतंत्र रूप से हेल्थ थेरेपी के रूप में मान लिया गया है। इस बाबत जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसका नियमन करेगा
- अब देश में इसकी पढ़ाई होगी, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, कोर्स होगा और इस थेरेपी के स्पेशलिस्ट तैयार होंगे
- हर प्रकार के दर्द-चाहे माइग्रेन हो या सर्वाइकल-में यह कारगर है। विभिन्न स्तर पर खिलाड़ियों को चोट आदि में उपयोग में लाई जा रही इस थेरेपी से बिना सर्जरी भी खिलाड़ी ठीक हो रहे हैं

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

अमेरिकी मोदी मीडिया पुतिन को आइसोलेटेड कह रहा है जबकि ब्रिक्स में दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले देश जुड़े हैं। भारत, चीन, ईरान, यूएई, ब्राजील जैसे देश ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी वहां हैं। असल में अमेरिका और यूरोप के सामने खतरा है दुनिया में आइसोलेट होने का।

अशोक कुमार पाण्डेय, पत्रकार एवं लेखक
@Ashok_Kashmir

सुस्त-पक्षपाती होता संयुक्त राष्ट्र संघ

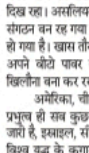

यूएन दिवस

डॉ. घनश्याम बादल

दुनिया भर में संघर्षों और तनावों के बीच संवादहीनता खत्म करने और विश्व शांति के उद्देश्य के साथ 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। मगर आज की परिस्थितियों में यह उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा। असलियत तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ वेजान संगठन बन रह गया है। उस पर महज चंद देशों का कब्जा हो गया है। खास तौर पर सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों ने अपने वीटो पावर की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ को खिलौना बना कर रख दिया है।

अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस का प्रभुत्व ही सब कुछ हो गया है। यूक्रेन-रूस का घमासान जारी है, इस्राइल, सीरिया, ईरान, फिलिस्तीन दुनिया भर को विश्व युद्ध के कगार पर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसे देश अपने हथियार बेचने के पत्ते चल रहे हैं यानी फिर से दुनिया के सामने करीब-करीब 1939 से 45 वाले हालात ही हैं। भारत, पाकिस्तान और चीन के विवादों में भी उसकी भूमिका अपंग सरीखा जैसी रही है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत ही क्या है? भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सही ही कहा था पिछले दिनों कि आखिर, भारत कब तक संयुक्त राष्ट्र संघ में बाजिब हिस्सेदारी के लिए प्रतीक्षा करे। आज भारत एशिया ही नहीं, दुनिया के प्रभावशाली देशों में शुमार है, उसकी जनसंख्या कमजोरी नहीं, ताकत बन चुकी है। अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। स्थाई सुरक्षा परिषद की सदस्यता पर उसका दावा सही और समय के अनुकूल है पर संयुक्त राष्ट्र संघ पर हावी देश उसके हक को दबाए बैठे हैं। तब भारत क्यों न संयुक्त राष्ट्र संघ से अलग कुछ सोचे? पर भारत ने ऐसा सोचा और किया तब तो संयुक्त राष्ट्र संघ मुर्दा संगठन ही बन कर रह जाएगा। बेहतर हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ भारत की भूमिका बढ़ाने के बारे में तत्परता से सोचे। सोचे ही नहीं अपितु उस पर अमल भी करे।

संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष वर्तमान ज्वलंत प्रश्नों के साथ उसके स्थापना दिवस पर उसके इतिहास, दायित्वों, कार्यों और उपलब्धियों तथा सफलताओं-विफलताओं पर भी नजर डालना समीचीन होगा आज। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिल कर संयुक्त राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय संघर्ष

की स्थिति में विवादों और युद्ध की समाप्ति के लिए हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से और भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध की तरह के युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के रूप में शक्तिशाली देशों अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन को शामिल किया। कागमा में संयुक्त राष्ट्र संघ में 194 देश सदस्य हैं, और आम सभा, सुरक्षा परिषद, यूनिसेफ, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसके मुख्य अंग हैं। राष्ट्र संघ के विफल होने पर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार उभरा और 24 अक्टूबर, 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त बैठक राष्ट्र सम्मेलन हुई और 40 उपस्थित देशों ने संयुक्त राष्ट्रीय संविधान पर हस्ताक्षर किए और 24 अक्टूबर, 1945 को 50 देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क बना। दूसरी अहम संस्थाएं जेनेवा, कोपनहेगन आदि में हैं।

जिस समय संयुक्त राष्ट्र बना था, उस समय सभी राष्ट्र एक दूसरे के घोर विरोधी थे। दो देश आपस में तभी जुड़ते थे, जब उनका हित होता था। हित पूर्ति होते ही अलग होकर एक दूसरे से लड़ने लगते थे। इसी कारण दो भीषण विश्व युद्ध हुए। उस समय के पांच मजबूत देशों को वीटो पावर दिया गया ताकि वे सभी से सहयोग कर सकें। अगर किसी एक ने वीटो पावर का प्रयोग कर दिया तो वह आम राय नहीं मानी जाती और संयुक्त राष्ट्र वह कार्य नहीं कर पाता है। मगर इस ताकत का अनेक बार वेजा इस्तेमाल हुआ है। भारत को सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य न बनने देने के लिए चीन अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता रहा है। चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई सेना या बल नहीं है, तो उसे किसी भी कार्रवाई के लिए सदस्यों देशों पर ही निर्भर करना पड़ता है और इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ में ताकतवर देश मनमानी करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है-एक भी बच्चा भूखा-अनपढ़ न रहे, सभी को उचित भोजन-शिक्षा मिले। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी भारी खर्च कर रहा है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए समय-समय पर यूनिसेफ कार्यक्रम कराता है ताकि उन्हें उचित प्रोत्साहन मिले और वे मन लगा कर अपने कार्यों को पूरा कर सकें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में उत्साह और नवाचार का माहौल तैयार किया है पर सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का मामला अभी भी अधर में है। इस दिशा में भारत को आगे आकर काम करना होगा ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संतुलन स्थापित हो सके।

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कज़ादी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सहयोग लाज, नरमेरा हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
: समूह संपादक - डॉ. जिजय राय : स्थानीय संपादक - राकेश सिंह*
मुख्यालय - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, मुख्यालय - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

चिंतन

भारत-चीन नियंत्रण रेखा पर तनाव कम होने की उम्मीद

आजकल दुनिया भर में भारत-चीन के रिश्तों को लेकर चर्चाएं हैं। बीते दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा चीन के साथ मौजूदा स्थिति पर बयान देने के बाद से ही विश्व बिरादरी में इसे लेकर कई तरह-तरह की चर्चाएं थी। अब ब्रिक्स सम्मेलन में 5 साल बाद भारत-चीन की द्विपक्षीय बातचीत ने इन चर्चाओं को बल दे दिया है। इन चर्चाओं ने जेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से भी पकड़ा। पीएम ने कहा कि हम युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं और जिस तरह हमने मिलकर कोविड जैसी चुनौती को परास्त किया, उसी तरह हम भावी पीढ़ी के सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध भविष्य के लिए नए अवसर पैदा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। इसी संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूस के कजान शहर में बातचीत शुरू हो गई है। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बाइलेटरल मीटिंग हो रही है। 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने पर सहमति बनी है। असल में क्रस समेत दुनिया के अनेक देश चाहते हैं कि भारत और चीन मिलकर चलें। दोनों देशों का ब्रिक्स में बड़ा योगदान है। सम्मेलन में रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका समेत 28 देशों के राष्ट्र प्रमुख पहुंचे हैं। इस साल सर्मिट की अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन कर रहे हैं। वैसे भी यूरोपियन यूनियन को पछाड़कर ब्रिक्स दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर आर्थिक संगठन बन चुका है। ग्लोबल जीडीपी में यूरोपियन यूनियन के देशों की कुल हिस्सेदारी 14 प्रतिशत है, वहीं ब्रिक्स देशों का हिस्सा 27 फीसदी है। ब्रिक्स का अपना अलग बैंक भी है, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर चीन के शंघाई में है। यह सदस्य देशों को सरकारी या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन उपलब्ध करवाता है। 'राइजिंग इकोनॉमी' के कॉन्सेप्ट पर बने इस ग्रुप में पिछले साल तक 5 देश ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। इस साल यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया औपचारिक सदस्य बन जाएंगे। पिछले साल 34 और इस साल 40 देशों ने संगठन से जुड़ने की इच्छा जताई है। इसी सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया उथल-पुथल भरे बदलाव से गुजर रही है। हमें शांतिपूर्ण ब्रिक्स बनाने की जरूरत है। गाजा और लेबनान में हमें सीजफायर पर जोर देना होगा। हमें आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही ग्लोबल साउथ का देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना होगा। चीन, ब्रिक्स देशों के साथ ग्रीन इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी और ग्रीन मिनरल के लिए सहयोग बढ़ाना चाहता है। साफ है कि चीन भी भारत से संबंध बेहतर करना चाहता है, लेकिन चीन की विस्तारवादी नीतियां इसके आड़े आ रही हैं। अगर वो दोस्ती का हाथ भी बढ़ाता है तो भारत को हमेशा चौकना रहना होगा। चीन कर्ज देने और गुलाम बनाने की नीति पर चलता है। पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव चीन के बड़े कर्जदार हैं। चीन रूस के साथ इसलिए है कि वह गलत ऐतिहासिक तथ्यों व अपने सैन्य शक्ति के बल पर ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। लिथुआनिया में ताइवान का दूतावास खोलने की अनुमति मिलने से चीन परेशान है। विश्व के देशों की मुखरता से भी चीन परेशान है। इसीलिए वो भारत से दोस्ती करने के प्रयासों में लगा है। भारत को भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, लेकिन सतर्क भी रहना होगा क्योंकि हम पहले भी धोखा खा चुके हैं।

दो टूक
विकेश कुमार बडोला

कनाडा की धृष्टता का हो दृढ़ प्रतिकार

खालिस्तान की मांग करने वाले हरदीप सिंह निज्जर और अन्य की हत्या के लिए भारत पर बिन साक्ष्य के दोषारोपण करने के बाद कनाडाई शासक ट्रुडो इतने अदूरदर्शी, अपरिपक्व और जी-7 समूह के शक्तिशाली देशों के उकसाने से स्वार्थी हो चुके हैं कि खालिस्तानियों की अवैध धारणाओं व गतिविधियों को संरक्षण देकर भारत विरोधी प्रचार-प्रसार में बुरी तरह संलिप्त हैं। जो अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए भारत की प्रशंसा और समर्थन में विरोधी देशों का विरोध भी झेल लेता है, वह भारत एवं भारतीय महाद्वीप में अपने अनुचित कल्पनागत हितों में बाधक समुचित व सार्वभौमिक कल्याण के लिए भारतीय नीतियों का अप्रत्यक्ष प्रतिकार करने में कनाडा को माध्यम बना रहा है।

कनाडा अस्थिर है। इस देश का शासन हानिकारक अस्थिरताओं से घिर गया है। प्रमुख शासक जस्टिन ट्रूडो का अविवेकपूर्ण आचरण भारत के लिए असहनीय बन चुका है। जस्टिन इतने वर्षों की राजनीतिक गतिविधियों के बाद भी मूर्खतापूर्ण वक्तव्य दे रहे हैं और अनुचित निर्णय ले रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर को भी कनाडा शासन के अशिष्ट आचरण पर वक्तव्य देना पड़ा है कि वह अवैध युक्तियों द्वारा भारतीय सेना की जानकारी एकत्र करते हैं। जयशंकर के अनुसार, कनाडा अपने राजदूतों के माध्यम से भारतीय सेना व पुलिस के संबंध में सूचनायें एवं जानकारियां एकत्र करता है, किंतु कनाडा स्थित भारतीय राजदूत भारत के हित एवं सुरक्षा हेतु बाधक समस्याओं के उपाय ढूंढने का प्रयास करते हैं तो कनाडा को समस्या होने लगती है। खालिस्तान की मांग करने वाले हरदीप सिंह निज्जर और अन्य की हत्या के लिए कनाडा स्थित भारतीय राजदूतों पर बिन साक्ष्य के दोषारोपण करने के बाद कनाडाई शासक ट्रूडो भारतीयों की दृष्टि में गिर चुके हैं।

वे इतने अदूरदर्शी, अपरिपक्व और जी-7 समूह के शक्तिशाली देशों के उकसाने से भारत के विरोध में इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि खालिस्तानियों की अवैध धारणाओं व गतिविधियों को संरक्षण देकर भारत विरोधी प्रचार-प्रसार में बुरी तरह संलिप्त हैं। जो अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए भारत की प्रशंसा और समर्थन में विरोधी देशों का विरोध भी झेल लेता है, वह भारत एवं भारतीय महाद्वीप में अपने अनुचित कल्पनागत हितों में बाधक समुचित व सार्वभौमिक कल्याण के लिए भारतीय नीतियों का अप्रत्यक्ष प्रतिकार करने में कनाडा को माध्यम बना रहा है। यह बात संभवतः कनाडा के प्रधान मंत्री को ज्ञात नहीं है अथवा वे कनाडा में संभावित चुनाव में अपनी राजनीतिक स्थिति को राष्ट्रहितों दिखाने के प्रयास में अमेरिकी षड्यंत्र को अपने लिए अस्त्र मानकर उसका भारत के विरुद्ध व्यापक रूप में उपयोग कर रहे हैं। एक स्थिति यह है भारत के विरोध को प्रतिदिन व्यापक करते हुए तीव्र करते जाने की।

खालिस्तानियों का संरक्षण करके भारत के विरोध में अनेक निर्णय लेने का जस्टिन का उद्देश्य आगामी कनाडाई चुनाव में केवल खालिस्तान समर्थक अप्रवासियों का वोट बैंक साधना ही नहीं है, अपितु कनाडा में अवैध धन-संसाधनों के प्रसारण और माफियागत कार्यों को खालिस्तानी आतंकवादियों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना भी है। अनेक अन्य स्थितियां भी हैं, जिनमें कनाडा व जस्टिन ट्रूडो को शक्तिशाली राष्ट्रों के पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनाकर भारत के विरुद्ध नचवाया जा रहा है। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में भारत और कनाडा के संबंध सबसे निम्न स्तर पर पहुंच चुके हैं। दोनों राष्ट्रों के संबंध हानिकारक सीमा तक विद्रूप व विकृत हो चुके हैं। कनाडा के ऐसे दुराचरण पर भारत ने कनाडा के राजदूतों को तुरंत अपना सामान बांधकर भारत छोड़ने और कनाडा स्थित अपने दूतों को वापस बुलाने का आधिकारिक आदेश क्या जारी किया कि कनाडा को लगा कि कहीं उसकी स्थिति इस प्रकरण में अपमान्य न हो जाए, तो उसने भी

भारत की दोतरफा कार्रवाई के बाद भारतीय राजदूतों को कनाडा से निष्कारित करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया। कनाडा, भारत को नीचा दिखाने के हर संभव प्रयास कर रहा है। आये दिन वह अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और मंचों के सहयोग से भारत विरोधी षड्यंत्र कर रहा है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक शासन दुनिया के मानचित्र पर हमेशा से ही कष्टकंटक बोने के लिए कुख्यात रहा है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सांसदों और उनके संबंधियों के अस्त्र-शस्त्र के अनेक कल-कारखाने हैं। ये कारखाने केवल अमेरिका में ही नहीं हैं। जी-7 समूह के सभी देशों में ये कारखाने किसी न किसी ऐसे स्वामित्वधारक और प्रवर्तक के हैं, जो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसदों के संबंधी हैं। हालांकि अस्त्र-शस्त्रों के कारखाने तो रिपब्लिकन सांसदों के भी हैं, किंतु उनकी अस्त्र-शस्त्र विक्रय नीतियों में अवैध गतिविधियों के लिए अवैध माध्यम से अस्त्रों-शस्त्रों के विक्रय का कार्यव्यवहार या तो शून्य है अथवा अत्यंत सीमित है।

अवैध अस्त्र-शस्त्र ही नहीं, ऐसे कारोबारी तो प्रकृति को नष्ट करने वाली अनेक ऐसी वस्तुओं, उत्पादों व सेवाओं का कारोबार भी करते रहे हैं, जिन्हें कई देशों के विरोध के बाद भी वहां खपाने व बेचने के खटकर्म किए जाते रहे हैं। चूंकि भारत में गत बारह-चौदह वर्षों से ऐसी वस्तुओं, उत्पादों व सेवाओं के आयात पर राष्ट्रीय प्रतिबंध है और अस्त्र-शस्त्रों के विनिर्माण में भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है, तो अमेरिका सहित जी-7 राष्ट्रों के स्थापित कारोबारियों के लिए यह स्थिति हानिकारक है। होगरी-अमेरिकी मुद्रा सटोरिया जॉर्ज सोरोस भी भारत में मुद्रा सट्टा के अपने हित नहीं साध पा रहा है। सोरोस के समान ही अन्य व्यवसायी हैं, जो भारत के स्थिर व प्रगतिशील शासन को अस्थिर करके यहां अपने अनुचित व्यावसायिक हित साधना चाहते हैं। गत दो दशकों से वे खुलकर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो हानिग्रस्त होते रहे हैं। इसीलिए भारत में राज्यों के विधानसभा चुनावों या लोकसभा चुनाव से पहले आंदोलन के रूप में षड्यंत्र किया जाता है। ऐसे व्यवसायी भारत के भ्रष्ट, चरित्रहीन, देशविरोधी, लालची और स्वार्थी विपक्षी नेताओं, बुद्धिजीवियों, मीडियाकर्मियों तथा संस्थागत पदों पर आरूढ़ पदाधिकारियों के साथ मिलकर स्थिर केंद्रीय शासन को डिगाने-डगमगाने के कुत्सित प्रयास करते रहे हैं। दिल्ली में विगत दिनों, माहों एवं वर्षों में केंद्रीय शासन व शासनजन्य नीतियों के विरोध में जितने व जो भी आंदोलन हुए हैं, अधिक या सभी षड्यंत्र की उपज ही थे। पंजाब व दिल्ली में हुए ऐसे आंदोलनों में कनाडा के माध्यम से जॉर्ज सोरोस जैसे कारोबारियों के हथियार बने थे खालिस्तानी आतंकी। भेष इन्होंने किसानों का बनाया था, किंतु थे ये खालिस्तानी। इन्होंने लाल किले में उपद्रव किया। दिल्ली स्थित विभिन्न राजमार्गों, एक्सप्रेस हाईवे में जाम किया। सिंघु बार्डर पर कई दिनों तक धरना दिया। खालिस्तानियों के माध्यम से भारतीय शासन को अस्थिर करने में असफल रहने वाले सोरोस जैसे व्यक्तियों ने अंततः अमेरिकी नीतियों व संसाधनों की मदद से बांग्लादेश में उथल-पुथल करके भारत को चोट पहुंचाने का प्रयास किया, किंतु यह उपाय भी विफल ही सिद्ध हुआ। अभी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय पूंजीपतियों, देशों व अन्य माफियाओं के उकसावे में भारत के विरुद्ध विषवमन करने में व्यस्त है। ऐसे में भारत को चाहिए कि वह कनाडा के माध्यम से अपने विरुद्ध होने वाले प्रत्येक षड्यंत्र की तह तक पहुंचे और भारतीय गौरव, संप्रभुता, अखंडता एवं सम्मान के रक्षार्थ कनाडा पर हरसंभव बंध-प्रतिबंध लगाना जारी रखे और साथ ही गुप्त षड्यंत्रकारियों को भी परास्त करने के अभियान संचालित करे।

(लेखक उत्तराखंड स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

साइबर अपराध

सतीश सिंह

'डिजिटल हाउस अरेस्ट' से दहशत में आमजन

डिजिटल हाउस अरेस्ट साइबर अपराध का नया स्वरूप है, जिससे आमजन दहशतजदा हैं, क्योंकि आये दिन कोई न कोई साइबर ठगी का शिकार बन रहा है और 'डिजिटल हाउस अरेस्ट' की खबरें अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। ऐसी ठगी में पढ़े-लिखे लोग ज्यादा शिकार बन रहे हैं और इनमें बुजुर्गों की संख्या अधिक है। विगत वर्षों में साइबर अपराधों में काफी विविधता आई है। 'तू डाल-डाल, मैं पात-पात' की तर्ज पर अपराधी अब नये-नये तरीकों से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इस क्रम में नई मोडस ऑपरेंडी है 'डिजिटल हाउस अरेस्ट'। इस तकनीक की मदद से ऑनलाइन फ्रॉड में काफी तेजी आई है। उदाहरण के तौर पर, अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में एक 65 साल की बुजुर्ग महिला को 5 दिनों तक डिजिटली घर में कैद करके फर्जी पूछताछ की गई और 46 लाख रुपये ठगे गए। इसी तर्ज पर अगस्त महीने में लखनऊ की एक महिला न्यूरो डॉक्टर को 6 दिनों तक डिजिटली गिरफ्तार करके ठगों ने 2.8 करोड़ रुपये ठग लिए। दोनों मामले में ठग खुद को सीबीआई अधिकारी बता रहे थे और बुजुर्ग महिला एवं महिला डॉक्टर को हवाला कारोबार में उनकी संलिप्तता बताकर इन दोनों ठगी को अंजाम दिया। इस तरह की ठगी में ठग पुलिस, सीबीआई, ईडी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ,नॉरकोटिक्स आदि का अधिकारी बनकर ऑडियो या वीडियो कॉल करके टार्गेट को इतना डराते हैं कि वह अपनी जिंदगी भर की जमापूंजी ठग के खाते में ट्रांसफर कर देता है। 'डिजिटल हाउस अरेस्ट' को मूर्त रूप देने के लिए ठग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई के जरिये वे टार्गेट के सगे-संबंधियों की आवाज की नकल करके या फिर उसकी हूबहू वीडियो बनाकर टार्गेट को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि वे गंभीर संकट में हैं। चूंकि साइबर अपराधों को रोकने के लिए अभी भी पुख्ता कानून और प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव है, इसलिए ऐसी ठगी को रोकना भारत में हाल-फिलहाल में असंभव लग रहा है। देश में प्रशिक्षित साइबर पुलिस की भारी कमी है, जिसका फायदा साइबर ठगों को मिल रहा है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत दुनिया में 10वें स्थान पर है। आजकल किशोर बच्चियों को ऑनलाइन चैटिंग एप के जरिये ब्लैकमेल करके या उनकी अश्लील तस्वीरों को पॉर्न मार्केट में बेचकर और उनके पैरेंट्स को ब्लैकमेल करके ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग,कुरियर, रिश्तेदार, दोस्त की गिरफ्तारी आदि की धमकी, अश्लील वीडियो आदि नए-नए तरीकों की मदद से ठगी करने के वारदातों में तेजी आई है। स्नैप चैट, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी अब ठगी के साधन बन गए हैं। मित्र या रिश्तेदार को फर्जी प्रोफाइल बनाकर ऐसी ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। ब्राउजर एक्सटेंशन के डाउनलोडिंग के जरिये भी साइबर अपराध किए जा रहे हैं। यह काम वायरस के जरिये किया जाता है। क्रोम, मोजिला आदि ब्राउजर के जरिए किए गए ऑनलाइन लेनदेन ब्राउजर के सर्वर में सेव हो जाते हैं, जिन्हें सेटिंग में जाकर डिलीट करने की जरूरत होती है, लेकिन अज्ञानतावश लोग ऐसा नहीं करते हैं, जिसका फायदा साइबर ठग उठाते हैं। हैकर्स एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिये भी ऑफर वाले मैसेज भेजते हैं, जिसमें मैलवेयर युक्त हाइपर लिंक दिया हुआ होता है। मोबाइल एप से लोन लेना सूदखोर या महाजन या साहूकार से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऐसे ठगों की व्यापकता देश-काल से परे है, क्योंकि अधिकांश मोबाइल चाइना मेड हैं और उनका सर्वर भारत से बाहर होता है। ब्राउजिंग सेशन के दौरान संदेहास्पद पॉप अप से सतर्क रहें। वेबसाइट्स या मोबाइल या पब्लिक लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कार्ड की जानकारी साझा नहीं करें। अंजान नंबर या ईमेल आईडी से आये अटैचमेंट को तुरंत डिलीट कर दें और ऑनलाइन लॉटरी, कैसिनो, गेमिंग, शॉपिंग या फ्री डाउनलोड वाले मैसेज की उपेक्षा करें तो फिशिंग मेल या एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिये फॉरवर्ड होने वाले संदेहास्पद हाइपर लिंक के जाल से बचा जा सकता है।कभी मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं आयें। धमकी मिलने पर पुलिस की मदद लेने से नहीं हिचकें। हमेशा जागरूक रहें। फोन, कंप्यूटर, टैबलेट के सॉफ्टवेयर को समयानुसार अपडेट करें,मजबूत पासवर्ड, अंजान लिंक को ओपेन करने से बचें, निजी जानकारी को सुरक्षित रखें, सार्वजनिक वाई-फाई के इस्तेमाल में सावधानी बरतें, एंटीवायरस का इस्तेमाल करें और नियमित रूप से उसे अपडेट करें आदि। सबसे महत्वपूर्ण है लालच से परहेज करें। मामले में सावधानी ही बचाव है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मनुष्य इंद्रिय विषयों में तीव्र आनंद अनुभव करता है

संकलित
दर्शन

भक्ति विभिन्न रूपों में प्रकाशित होती है। पहला है श्रद्धा। लोग मंदिरों और पवित्र स्थानों के प्रति श्रद्धा इसलिए प्रकट करते हैं, क्योंकि वहां भगवान की पूजा होती है, ऐसे स्थानों में उनकी सत्ता अधिक अनुभूति होती है। प्रत्येक देश में लोग धर्मचार्यों के प्रति श्रद्धा इसलिए प्रकट करते हैं, क्योंकि ये आचार्य उन्हीं भगवान की महिमा का उपदेश देते हैं। इस श्रद्धा का मूल है प्रेम। हम जिससे प्रेम नहीं करते, उसके प्रति कभी श्रद्धालु नहीं हो सकते। इसके बाद है प्रीति अर्थात ईश्वर चिंतन में आनंद। मनुष्य इंद्रिय विषयों में तीव्र आनंद अनुभव करता है। इंद्रियों को अच्छी लगने वाली चीजों के लिए वह भटकता फिरता है और बड़ा से बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। भक्त को चाहिए कि वह भगवान के प्रति इसी प्रकार का तीव्र प्रेम रखे। इसके उपरांत आता है विरह। विरह प्रेमास्पद के अभाव में उत्पन्न होने वाला तीव्र दुख। यह दुख संसार के समस्त दुखों में सबसे मधुर है। जब मनुष्य भगवान को न पा सकने के कारण, संसार में एकमात्र जानने योग वस्तु को न जान सकने के कारण तीव्र वेदना अनुभव करने लगता है और अत्यंत व्याकुल हो पागल-सा हो जाता है, उस दशा को विरह कहते हैं। मन की ऐसी दशा में प्रेमास्पद को छोड़ उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुधा यह विरह सांसारिक प्रणय में देखा जाता है। जब पराभक्ति हृदय पर अपना प्रभाव जमा लेती है तो अन्य अप्रिय विषयों को उपस्थित हमें खटकने लगती है, यहां तक कि प्रेमास्पद भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर बातचीत तक कहना हमारे लिए अरुचिकर हो जाता है।

महिला के शुभ कदम

संकलित
प्रेरणा

एक आदमी ने दुकानदार से पूछाः केले और सेवफल क्या भाव लगाए है? दुकानदारः केले 20 रु. दर्जन और सेव 100 रु. किलो। उसी समय एक गरीब सी औरत दुकान में आई और बोली मुझे एक किलो सेव और एक दर्जन केले चाहिए, क्या भाव है? भैया दुकानदारः केले 5 रु दर्जन और सेब 25 रु किलो। औरत ने कहाः जल्दी से दे दीजिए। दुकान में पहले से मौजूद ग्राहक ने खा जाने वाली निगाहों से घूरकर दुकानदार को देखा, इससे पहले कि वो कुछ कहता, दुकानदार ने ग्राहक को इशारा करते हुए थोड़ा सा इंतजार करने को कहा। औरत खुशी खुशी खरीदारी करके दुकान से निकलते हुए बड़बड़ाई हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे फलों को खाकर बहुत खुश होंगे। औरत के जाने के बाद, दुकानदार ने पहले से मौजूद ग्राहक की तरफ देखते हुए कहाः ईश्वर गवाह है, भाई साहब मैंने आपको कोई धोखा देने की कोशिश नहीं की। यह विधवा महिला है, जो चार अनाथ बच्चों की मां है। किसी से भी किसी तरह की मदद लेने को तैयार नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की है और हर बार नाकामी मिली है। तब मुझे यही तरीकाब सूझा है कि जब कभी वे आए तो, मैं उसे कम से कम दाम लगाकर चीजे देदूँ। मैं यह चाहता हूँ कि उसका भरम बना रहे और उसे लगे कि वह किसी की मोहताज नहीं है। इस तरह भगवान के बन्दो की पूजा कर लेता हूँ। थोड़ा रूक कर दुकानदार बोलाः यह औरत हफ्ते में एक बार आती है। भगवान गवाह है, जिस दिन यह आ जाती है उस दिन मेरी बिक्री बढ़ जाती है और उस दिन परमात्मा मुझपर मेहरबान हो जाता है।

अंतर्मन

आज की पाती

विश्वास के लायक नहीं है चीन

खबरों के मुताबिक भारत और चीन के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है कि दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपने-अपने सैनिकों को पीछे करेंगे और यहां पेट्रोलिंग करेंगे। चीन इस पर कितना कायम रहेगा, यह तो आने वाला समय ही बतएगा। लेकिन चीन हर समझौते, जो इससे पहले हुए हैं, उन पर अमल करता तो वो रह सकर नियंत्रण रेखा पर अपने नापाक इरादों को अंजाम नहीं देता। दूसरी बीज भारत को चीन के इस समझौते पर चीन के प्रति इतना नरम भी नहीं हो जाना चाहिए कि उसके लिए देश में व्यापार को और सुलभ बना दिया जाए। चीन का यो हाल है कि गंगा गए तो गंगाराम यमुना गए तो यमुना दास। वह मेरे मुंह पर मेरा और तेरे मुंह पर तेरा है। वह अकसर अपने वादों से मुकरता रहा है। उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए सचेत रहने की जरूरत है। - शैलेश सिंह ठाकुर, रायगढ़

ट्रेंड

पुतिन के साथ अच्छी मुलाकात

रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। भारत और रूस के बीच संबंध बहुत गहरे हैं। हमारी बातचीत इस बात पर केंद्रित थी कि विभिन्न क्षेत्रों में हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को और अधिक मजबूती कैसे दी जाए।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सरदार पटेल की भूमिका अमिट

कश्मीर से लद्दाख तक भारत को एकजुट करने में सरदार पटेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका अमिट है। उनके सामर्थ्यवीर योगदान का सम्मान करने के लिए उनकी 150वीं जयंती 2024 से 2026 तक दो साल के राष्ट्रव्यापी उत्सव के साथ मनाएंगे।

-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

नीति निर्माण में स्थिरता

स्थिरता नीति निर्माण का एक अभिन्न अंग बन गई है। स्थिर तकनीक, विश्वस्त विनिर्माण, अबाधित और ऊर्जा में कटौती दिखाकर बायोमैन्युफैक्चरिंग को पालने की कुंजी है।

-किरण मजूमदार-शॉ, उद्यमी

'हमारे राम' का संगीत रिलीज

टी सीरीज का रामनवमी से कुछ संगतकारियों के आनंद और उत्साह में वृद्धि का वाहक है। टी सीरीज जैसे सशक्त, लोकप्रिय संस्थान द्वारा रामायण पर प्रस्तुत किए जाने वाले महाकाव्य 'हमारे राम' का संगीत रिलीज करने पर हार्दिक धन्यवाद।

-आशुतोष राणा, अभिनेता

करंट अफेयर

रियाद का 'बुलेवार्ड वर्ल्ड' बना विश्व का प्रमुख मनोरंजन क्षेत्र

सऊदी अरब की राजधानी रियाद के बीचों बीच स्थित प्रमुख मनोरंजन क्षेत्र 'बुलेवार्ड वर्ल्ड' विभिन्न सभ्यताओं से रूबरू कराता है, जहां आगंतुक इन स्मारकों की प्रतिकृतियों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसमें भारत समेत दुनिया भर के 20 से अधिक विभिन्न स्थल, लगभग 300 रेस्तरां और कैफे तथा लगभग 900 दुकानें हैं। इस साल 72 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में 'रियाद सीजन' का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दौदह मनोरंजन स्थल बनाए गए हैं। इन क्षेत्रों में एक पारंपरिक बाजार है जिसमें स्थानीय संस्कृति से लेकर शिल्प तक का प्रदर्शन किया जाता है और यहां प्रत्येक देश की झलक मिलती है। गोंडोला सवारी के अलावा, आप वाटर टैक्सी, एम्फीथाटर और फ्लोटिंग डोनट्स, केबल कार या फिर पैदल चलकर भी इस स्थल का भ्रमण कर सकते हैं। यहां हर दिन विभिन्न देशों के नाट्य प्रस्तुतियां भी होती हैं। ये गतिविधियां सऊदी अरब के लोकप्रिय शीतकालीन महोत्सव 'रियाद सीजन' का हिस्सा हैं, जो 12 अक्टूबर से शुरू हुआ है और मार्च तक जारी रहने की उम्मीद है। इस महोत्सव की शुरुआत जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी (जीईए) के निदेशक मंडल के अध्यक्ष तुर्की बिन अब्दुल्लाहोसेन अल-शेख ने की।

ऑफ बीट

पृथ्वी की कक्षा में 4300 टन अंतरिक्ष कचरा

एक बड़ा संचार उपग्रह अपनी कक्षा में टूट गया है, जिससे यूरोप, मध्य अफ्रीका, मध्य पूर्व, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के उपयोगकर्ता प्रभावित हुए हैं, वहीं हमारे ग्रह के पड़ोस में अंतरिक्ष कचरे के खतरे में भी इजाफा हुआ है। इंटेलसैट 33ई उपग्रह भूमध्य रेखा के चारों ओर भूस्थिर कक्षा में हिंद महासागर से लगभग 35,000 किलामीटर ऊपर एक बिंदु से ब्रॉडबैंड संचार प्रदान करता था। बीस अक्टूबर को प्रारंभिक खबरों में कहा गया था कि इंटेलसैट 33ई की अचानक बिजली गुल हो गई है। कुछ घंटे बाद, यूएस स्पेस फोर्सेस-स्पेस ने पुष्टि की कि उपग्रह कम से कम 20 टुकड़ों में टूट गया है। तो क्या हुआ? और क्या यह आने वाली घटनाओं का संकेत है क्योंकि अधिक से अधिक उपग्रह कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं? एक अंतरिक्ष रहस्य इंटेलसैट 33ई के टूटने के कारणों के बारे में कोई पुष्ट खबर नहीं है। हालांकि, यह अपनी तरह की पहली घटना नहीं है। अतीत में हमने उपग्रहों को नष्ट होते, आकस्मिक टकराव और बढ़ी हुई सौर गतिविधि के कारण उपग्रहों को नष्ट होते देखा है। हम यह जानते हैं कि इंटेलसैट 33ई में दिक्कतें उत्पन्न होने का इतिहास रहा है। बोइंग द्वारा डिजाइन और निर्मित, उपग्रह को अगस्त 2016 में प्रक्षेपित किया गया था।

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण

उत्तरदायित्व की भावना का अभाव प्रगति को रोकता है

चीन से संबंध सुधार

रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के संबंध सामान्य होने की संभावना बढ़ अवश्य गई है, लेकिन इसमें समय लगेगा, क्योंकि बीते चार वर्षों में चीन ने अपनी हरकतों से भारत का भरोसा खोने का काम किया है। भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच करीब पांच वर्षों के बाद विस्तार से वार्ता इसीलिए हो सकी, क्योंकि चीन देपसांग एवं डेमचोक से अपनी सेनाएं पीछे हटाने और सीमा पर निगरानी की पहली वाली स्थिति बहाल करने पर सहमत हुआ। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए इस पर जोर दिया कि सीमा पर शांति रहनी चाहिए और आपसी विश्वास एवं सहयोग को बढ़ावा देने के साथ एक-दूसरे की संवेदनशीलता का सम्मान किया जाना चाहिए। यह कहना आवश्यक था, क्योंकि चीन यह तो चाहता है कि भारत उसके हितों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरते, लेकिन खुद उसकी ओर से भारत की संवेदनशीलता की परवाह नहीं की जाती। इसका प्रमाण यह है कि वह कभी कश्मीर तो कभी अरुणाचल प्रदेश को लेकर मनगढ़ंत दावे करता रहता है। इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि चीन किस तरह पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। इस क्रम में वह पाकिस्तान के उन आतंकियों का संयुक्त राष्ट्र में बचाव तक करता है, जो भारत के लिए खतरा हैं। ऐसे में भारत का उसके प्रति संशंकित रहना स्वाभाविक ही है।

यह ठीक है कि रूस में भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि भी शीघ्र मिलेंगे। इस मेल-मुलाकात में विश्वास बहाली के उपायों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ऐसा पहले भी हो चुका है। अब चीन को यह आभास कराया जाना चाहिए कि उसने पहले गलवन और फिर अन्य स्थानों पर नियंत्रण रेखा में यथास्थिति बदलने के जो प्रयत्न किए, उससे ही दोनों देशों के संबंधों को पटरी से उतारने का काम किया। इसके लिए चीन अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकता। भारत को चीन से संबंध सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ने के पहले इसकी पड़ताल करनी चाहिए कि कहीं वह फिर से वैसी हरकत तो नहीं करेगा, जैसी डोकलाम, गलवन, देपसांग आदि में की। यह ध्यान रहे कि अतीत में चीन ने अपने अतिक्रमणकारी रवैये को तभी छोड़ा है, जब भारत ने यह जताने में संकोच नहीं किया कि वह बहुपक्षीय सहयोग के ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों को अपेक्षित महत्व देने से इन्कार कर सकता है। इस बार चीन इसलिए भी झुका, क्योंकि उसे यह आभास हुआ कि भारत का असहयोग उसके आर्थिक हितों पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। निःसंदेह संबंध सामान्य होने से चीन के आर्थिक हित सधेंगे, लेकिन भारत को अपने आर्थिक हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।

पुलिस के कलंक

यह चिंता की बात है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरे देश में सराहना हो रही है, लेकिन निचले स्तर पर भ्रष्टाचार में कमी नहीं आ पा रही है। कानपुर में दो दारोगाओं का कृत्य तो हैरान करने वाला है और चोरों पर मोर पड़ जाने की कहावत को चरितार्थ करता है। इन दरोगाओं ने सरांफ की मदद से 25 लाख रुपये के जेवरात तो चोरों से हड़पे ही, चोर से एक लाख रुपये अलग से वसूले। ऐसे ही एक दूसरे मामले में दारोगा ने मोमबत्ती के एक व्यापारी से 50 हजार रुपये वसूल लिए। अब अधिकारियों ने दो दरोगाओं को गिरफ्तार और थाना प्रभारी समेत सात पुलिसकर्मियों का निलंबन कर महकमे की छवि बचाने की कोशिश की है, लेकिन गंभीर सवाल यह है कि जिन्हें अपराध रोकने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित किया जाता है, वह स्वयं ही अपराधियों जैसा आचरण क्यों करने लगते हैं? कानपुर के ये दोनों प्रकरण तो उदाहरण के तौर पर हैं। इस तरह के न जाने कितने मामले हर जिले में सामने आते रहे हैं। थानों में तैनात पुलिसकर्मियों में भ्रष्टाचार एक ऐसा नासूर है जिसका इलाज करने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन रोग बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि पुलिस महकमे में तैनात हर कर्मी भ्रष्ट है, लेकिन कुछ मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। विशेष तौर पर थानों की कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। अधिकारियों ने कुछ माह पहले बलिया के नरही थाने में हर माह डेढ़ करोड़ रुपये की वसूली का राजफाश किया था। आगरा में अभियान चलाकर दो दिन के भीतर 12 दरोगा, छह मुंशी सहित 56 दागी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। देखा जा रहा है कि प्रदेश के हर जिले में इस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि थानों में तैनात पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

राजनीतिक लड़ाई का मोहरा बनते कारोबारी

गौरव वल्लभ

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नवाचार और उद्यमशीलता सम्मान करने वाली संस्कृति को बढ़ावा देना अनिवार्य है

भारत अभूतपूर्व औद्योगिक कायापलट के दौर से गुजर रहा है। परिवर्तन की यह बयार देश के आर्थिक विकास और सामाजिक लोकाचार को परिभाषित करेगी। करीब 24.7 लाख उद्यमियों के इस विशाल परिवार ने वित्त वर्ष 2023 में 8.8 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर के विस्मयकारी लेनदेन के स्तर को छुआ। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में संघर्ष करने वाले बड़े व्यवसायों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्यमों तक व्यवसाय पारंपरिक प्रतिमानों को फिर से परिभाषित कर रहे हैं और आर्थिक समावेशिता को बढ़ावा दे रहे हैं। उद्यम की यह लहर केवल एक सांख्यिकीय घटना नहीं, बल्कि नवाचार और महत्वाकांक्षा की अदम्य भावना का प्रतिबिंब है, जो भारतीय समाज के हर तबके में व्याप्त है। फिर भी विडंबना यह है कि जैसे-जैसे ये उद्यमी देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वे हमलों का सामना कर रहे हैं। रचनात्मक आलोचना प्रतिस्पर्धा एवं नवाचार को बढ़ावा देते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यह विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। उद्यमियों को अपने मानकों को बढ़ाने और मूल्य प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। आलोचनात्मक मूल्यांकन से प्रेरित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बेहतर उत्पादों, सेवाओं और अंततः अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर ले जा सकती है। हालांकि आलोचना जब स्वस्थ और भली मंशा से न की जाए तो वह केवल नकारात्मकता को बढ़ाती है। हमारे सार्वजनिक विमर्श में कुछ तबकों द्वारा अक्सर ऐसा किया जाने लगा है। वेल्थ क्रिएटर्स यानी संपदा सृजन करने वालों को अनावश्यक रूप से निशाने पर लिया जा रहा है। उद्यमियों को अपनी राजनीतिक लड़ाई का मोहरा बनाया जा रहा है।

नवाचार और कड़ी मेहनत के माध्यम से अर्जित सफलता का जश्न मनाने के लिए सामाजिक आख्यान को बदलने की आवश्यकता इस समय कहीं अधिक महसूस हो रही है। आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए उद्यमशीलता के प्रयासों का समर्थन करने वाली संस्कृति को अपनाना महत्वपूर्ण है। हमारे पाठ्यक्रम में व्यापक उद्यमिता शिक्षा की अनुपस्थिति के कारण कई लोग व्यवसायिक उपक्रमों की चुनौतियों और योगदानों को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। एक उद्यमी तमाम मुश्किल पड़ावों को पार कर सफलता के गंतव्य तक पहुंचता है। युवा उद्यमियों का ही उदाहरण लें तो कभी-कभी योग्यता के आधार पर मूल्यांकन करने के बजाय उनकी उम्र के कारण उन्हें खारिज कर दिया जाता है। इसी तरह, धार्मिक और

अवधेश राजपूत

सांस्कृतिक पूर्वाग्रह विशिष्ट पृष्ठभूमि के चलते भी उद्यमियों को भेदभाव झेलना पड़ सकता है। जबकि लैंगिक पूर्वाग्रह महिला उद्यमियों के लिए एक बाधा बनी हुई है, जिन्हें अपने लिए मुकाम बनाने में और परिश्रम करना पड़ता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कारोबारी हस्तांतरण को भाई-भतीजावाद के आरोप झेलने पड़ते हैं, जबकि ऐसा करते हुए विरासत व संचित ज्ञान के महत्व की अनदेखी कर दिया जाता है।

अनुचित आलोचना के प्रभाव बहुत गहरे और दूरगामी होते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर ही देखें तो इससे कारोबारी प्रवर्तकों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनामी झेलनी पड़ती है। यह उनके कर्मचारियों तक फैलता है, जिससे उनका मनोबल गिरता है और उत्पादकता घटती है। नवाचार को हतोत्साहित करना एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। जब जोखिम लेने वालों को सामाजिक रूप से दंडित किया जाता है तो यह रचनात्मकता और प्रगति को रोकता है। नकारात्मकता से भरे माहौल में निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है। घरेलू और विदेशी दोनों तरह की पूंजी स्थिर और अनुकूल परिस्थितियों को प्राथमिकता देती है। अनुचित आलोचना अस्थिरता को बढ़ाकर निवेशक बिरादरी का भरोसा तोड़ती है, जो आर्थिक विकास की गति को कुंद करता है। प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करने से अधिक टिकाऊ और समावेशी विकास हो सकता है। आर्थिक विकास को गति देने में उद्यमशीलता की अपरिहार्य भूमिका को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने पारंपरिक समाजवादी-उन्मुख नीतियों से धीरे-धीरे अधिक बाजार-हितैषी रणनीतियों की ओर रुख किया है। यह महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन व्यवसायों के फलने-फूलने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उद्यमियों को सशक्त बनाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक गहराई से जोड़ने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। जैसे स्टार्टअप इंडिया योजना कर रियायतों, नियमों को सरल बनाने और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर एक अनुकूल तंत्र के निर्माण में सहायक बनी है। इसी तरह मुद्रा योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति अपनी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार असाधारण योगदान को मान्यता और सम्मान देकर और नवाचार एवं उत्कृष्टता की राष्ट्रव्यापी संस्कृति को बढ़ावा देकर इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। इन प्रयासों के बावजूद उद्यमियों को अनुचित आलोचना से बचाने के लिए सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता है। इसके साथ ही जवाबदेही भी बनाए रखनी है।

उद्यमियों को नैतिक प्रथाओं, पारदर्शिता और सामाजिक प्रभाव के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। स्वयं ही, वे आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए मान्यता एवं सम्मान के हकदार हैं। खुले संवाद को प्रोत्साहित करना, वित्तीय साक्षरता बढ़ाना और उद्यमिता शिक्षा को अकादमिक पाठ्यक्रम में शामिल करना समूह के स्तर पर बनी खाई को पाटने में मददगार हो सकते हैं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नवाचार का जश्न मनाने वाली और उद्यमशीलता का सम्मान करने वाली संस्कृति को बढ़ावा देना अनिवार्य है। सरकार, मीडिया, शैक्षणिक संस्थानों और समाज का सामूहिक प्रयास ऐसा माहौल बनाने के लिए आवश्यक है, जहां आलोचना प्रगति में बाधा बनने के बजाय सुधार के साधन के रूप में काम करे।

(लेखक एक्सलएआरआइ, जमशेदपुर में वित्त के प्रोफेसर एवं भाजपा नेता हैं)

response@jagran.com

अलग माहौल वाले विधानसभा चुनाव

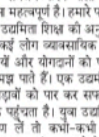

अवधेश कुमार

महाराष्ट्र और झारखंड में सीटों के बंटवारे पर जो खींचतान हुई, उससे आइएनडीआइए की एकता की पोल ही खुली

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है, जिसकी कल्पना हाल के लोकसभा चुनाव के बाद नहीं की जा रही थी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस सहित उसके घटक दलों के स्वर में उत्साह और आत्मविश्वास की गूंज थी। ऐसा लगता था कि उन्होंने लड़ाई में जबरदस्त जीत हासिल की और भाजपा पराभव की ओर है। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के नतीजों ने माहौल बदल दिया। यदि महाराष्ट्र और झारखंड में आइएनडीआइए में सीट बंटवारे को लेकर जो कुछ हुआ, उसे को आधार बनाएं तो पता चल जाएगा कि स्थिति कितनी बदली हुई है। एक ओर भाजपा ने आत्मविश्वास और परिपक्वता से सहयोगी दलों के साथ सीटों का तालमेल किया और दोनों राज्यों में आपसी विरोध नहीं दिखा। दूसरी ओर महाराष्ट्र और झारखंड में आइएनडीआइए के बीच सीटों को लेकर जिस तरह की खींचतान तथा सार्वजनिक बयानबाजी हुई, उससे तथाकथित एकजुटता की वास्तविकता सामने आई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेता एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ही नहीं करते रहे, अपने हिस्सा से प्रत्याशी उतारने की घोषणा भी करते रहे।

यह कहना ठीक नहीं होगा कि भाजपा नेतृत्व वाले राजग में सीटों को लेकर समस्याएं नहीं। मूल बात है कि आप इसे हैंडल कैसे करते हैं। महायुति में देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे में से किसी ने सीटों के बंटवारे को लेकर असंतोष प्रकट नहीं किया। भाजपा ने महाराष्ट्र में आरंभिक 99 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जहां दूसरे का दावा नहीं था। झारखंड में भी उसने शांति से सीटों का बंटवारा कर लिया और स्वयं 68 सीटों पर लड़ते हुए आजसू को 10, जदयू को दो एवं लोजपा को एक सीट दी। लोजपा का प्रदेश में जनाधार नहीं है और जद-यू भी ऐसी स्थिति में नहीं कि साथ न लेने पर भाजपा को क्षति पहुंचा दे। बावजूद इसके गठबंधन में एका बनाए रखने के लिए भाजपा ने ऐसा किया। दोनों गठबंधनों के बीच का यह गुणात्मक चरित्र चुनाव परिणाम पर प्रभाव नहीं डालेगा, यह मानना व्यावहारिक नहीं। महाराष्ट्र का अंकगणित देखें तो 2019 के विधानसभा चुनाव परिणामों का अब इसलिए महत्व नहीं, क्योंकि शिवसेना और राकांपा

महाविकास अघाड़ी में नहीं दिख रहा एका। प्रेट्र

दोनों टूट चुकी हैं। यद्यपि भाजपा और कांग्रेस में टूट नहीं हुई है, लेकिन सारी दलों से इन्हें तब प्राप्त मतों का अनुमान लगाना संभव नहीं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में 48 में से राजग को केवल 18 तथा महाविकास अघाड़ी को 30 सीटें प्राप्त हुईं।

झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी के साथ परिवार बंट गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन और सीता सोरेन भाजपा के साथ हैं। झामुमो की लोकप्रियता नीचे है। हरियाणा में जीतते-जीतते हारना और जम्मू-कश्मीर में बुरे प्रदर्शन के कारण कांग्रेस के अंदर निराशा है। इसके साथ आइएनडीआइए घटकों के बीच संदेश गया है कि कांग्रेस की हैसियत अपनी बदौलत सफलता पाने की नहीं है। जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की प्रवृत्तियां बदलती दिखाई दी हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के लिए दलितों के बीच विस्तृत पैठ बनाना कठिन रहा है, क्योंकि यह प्रदेश दलित आंदोलन का केंद्र है, जिसके निशाने पर हिंदुत्व और भाजपा रही है। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार संविधान और आरक्षण खत्म कर देगी, ऐसा प्रचार दलितों और पिछड़ों के एक वर्ग तक पहुंचा। उसने आइएनडीआइए के पक्ष में मत दिया, लेकिन हरियाणा के दलितों के बड़े वर्ग ने भाजपा के पक्ष में जाकर जता दिया कि वह इस गलत प्रचार के झांसे में नहीं आने वाला। हरियाणा सरकार गठित होने के बाद नायब सिंह सैनी सरकार ने अनुसूचित जाति आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू कर दिया, जिसका लाभ दलितों के अंदर वंचित वर्ग को मिलेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के समय देख गया कि भाजपा उम्मीदवारों और संगठनों में तो तालमेल था, लेकिन राज्य सरकार को लेकर संगठन परिवार के अंदर असंतोष और नराजगी थी। इसके बाद भी राहुल गांधी ने जिस तरह हिंदुत्व पर कटाक्ष किए और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का उपहास उड़ाया, उसकी प्रतिक्रिया हुई।

वास्तव में लोकसभा चुनाव में जहां भी भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा, वहां यह भाव व्याप्त हो रहा है कि यद्यपि भाजपा संगठन और सरकारों ने हमारी अनेक अपेक्षाएं पूरी नहीं की, किंतु देश के समक्ष खतरे को देखते हुए उसके विरोधियों के साथ जाना आत्मघाती होगा। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के बीच हिजबुल्ला सरगना के मारे जाने के बाद देश के कुछ हिस्सों में किए गए आक्रामक प्रदर्शनों से डर पैदा हुआ। फिर जगह-जगह सिर तन से जुदा के नारे ने इसे और बढ़ाया। कई जगह दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर हमले और हिंसा देखने को मिली। झारखंड में घुसपैठ, कट्टरपंथ, मतांतरण, लव जिहाद की घटनाओं ने लोगों के मन पर असर डाला है। हरियाणा की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दे किसान आंदोलन, अग्निवीर, संविधान, आरक्षण और दलितों, पिछड़ों तथा अल्पसंख्यकों पर खतरे की बात से मतदाता सहमत नहीं। राहुल गांधी के रणनीतिकार यह मानने को तैयार नहीं कि हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में मतदाताओं ने उनके तर्कों और मुद्दों को ठुकरा दिया है, इसलिए वे उसे नैरेटिव पर काम कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम को तंत्र, चुनाव आयोग और ईवीएम को आरोपित करना बताता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस अपनी नीतियों पर पुनर्विचार विचार करने को तैयार नहीं।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

स्वबुद्धि और आत्मबल

मानव जीवन जटिलताओं से परिपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति, बुद्धि और वृत्तियां विलक्षण होती हैं। इसीलिए यह अनिवार्य है कि मनुष्य अपने जीवन में अपने पथ का चयन स्वयं करे, क्योंकि आत्मपरिचय की गहनता किसी अन्य द्वारा संपूर्णतः समझना संभव नहीं है। जब हम परायों के परामर्श और अनुभूतियों पर निर्भर होते हैं, तो हम आत्मविस्मृति के पाश में बंध जाते हैं। समाज और परिवेश की अपेक्षाओं से प्रभावित होकर लिया गया कोई भी निर्णय हमारी आंतरिक चेतना और प्रकृति के अनुरूप नहीं होता। ऐसे पथ, जो केवल बाह्य प्रेरणाओं पर आधारित हो, मनोवांछित सुख और सौंदर्य नहीं प्रदान कर सकता। व्यक्ति को अपनी स्वबुद्धि और आत्मबल के आधार पर अपने लक्ष्य और दिशा का निर्धारण करना चाहिए।

स्वपथ का चयन आत्मशक्ति और स्वावलंबन को उत्प्रेरित करता है। जब हम स्वयं अपने निर्णयों का भार वहन करते हैं, तो हमारा आत्मबल और धैर्य विकसित होता है। इस प्रक्रिया में त्रुटियां भी स्वाभाविक हैं, परंतु उन्हीं त्रुटियों से हमें जीवन की वास्तविक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक विफलता हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करती है। स्वनिर्णय का पथ हमें आत्मविकास की ओर अग्रसर करता है। किसी भी पथ का चयन करते समय अपने अंतर्मन की वाणी और विवेक की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। यद्यपि समाज व परिवार से प्राप्त परामर्श मूल्यवान हो सकते हैं, किंतु अंतिम निर्णय व्यक्ति की अपनी प्रकृति और अनुभवों के आधार पर ही होना चाहिए। आत्मनिर्णय से उत्पन्न स्वाधीनता व्यक्ति के जीवन को गरिमा और संप्रभुता प्रदान करती है। यह न केवल बाह्य रूप से, बल्कि आंतरिक रूप से भी उसे सशक्त बनाती है। स्वयं के निर्णयों से अर्जित सफलता या असफलता जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। आपको अपने विषय में आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं जान सकता।

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

खत्म हो बाल विवाह कुप्रथा

सुमीता मिश्रा

हमारे समाज में बाल विवाह की कुप्रथा आज भी कायम है, जिसे रोका जाना चाहिए

बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को पर्सनल लॉ के जरिए बाधित नहीं किया सकता। बाल विवाह के कारण अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार छिन जाता है। नाबालिगों की जबरन और कम उम्र में शादी करना उनकी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन है। यह बच्चों की स्वतंत्रता, पसंद, आत्मनिर्णय और बचपन का आनंद लेने के अधिकार से वंचित करता है। इससे दोनों पक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बाल विवाह कुप्रथा को खत्म करने के लिए केंद्र, राज्यों, जिला प्रशासन, पंचायतों और न्यायपालिका को कई दिशानिर्देश भी जारी किए। साथ ही, सजा से बचने के लिए बच्चों की सगाई करने की प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत बताई। अदालत के दिशानिर्देशानुसार आम लोगों में इसको लेकर जागरूकता बढ़ाने के उपाय किए जाने चाहिए। हर समुदाय के लिए अलग तरीके अपनाए जाएं।

वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2019-2021 के पांचवें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बाल विवाह के जो आंकड़े दिए गए हैं, उनके मुताबिक 23.3 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हुई, जबकि 17.7 प्रतिशत लड़कों की शादी 21 वर्ष से कम आयु में हुई। ये आंकड़े 20 से 24 वर्ष की लड़कियों और 25 से 29 वर्ष के लड़कों पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का उद्देश्य बाल विवाह को रोकथाम, बाल विवाह में शामिल बच्चों की सुरक्षा और अपराधियों पर मुकदमा चलाना है। इस कानून में लड़कों के लिए शादी की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष तय की गई है। इसका उल्लंघन करने पर दो वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान है। बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़कियों पर, बल्कि उनके परिवार, समाज और देश पर भी पड़ता है। इससे लड़कियों की शिक्षा व स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है।

बाल विवाह कुप्रथा समाज के लिए अभिशाप है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को गरीबी की ओर धकेलता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर लिया गया फैसला न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में बाल विवाह के खिलाफ बड़ा बदलाव लाने की क्षमता भी रखता है। सरकार के सभी सर्वोच्च अधिकारों व उनकी भलाई के लिए समाज को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। इसके तहत स्वास्थ्य खतरे व सामाजिक आर्थिक परिणामों की भी जानकारी दी जाए, ताकि सभी बच्चों को सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर मिल सके।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

भारत के दोनों हाथों में लड्डू

यदि ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं तो भारत, रूस और अमेरिका की तिकड़ी बनेगी। यदि कमला हैरिस चुनाव जीत जाती हैं तो भारत, रूस और चीन की तिकड़ी बनेगी। दोनों स्थितियों में भारत को कोई समस्या नहीं होने वाली। अमेरिका की वर्तमान सरकार ने कनाडा के माध्यम से भारत में पिछले तीन साल से जो अस्थिरता फैलाने की कोशिश की है और खालिस्तानियों को प्रभावित करने का प्रयास किया है, ऐसे में चीन को निष्प्रभावी करने के लिए उसे जो साथ और विश्वास भारत का चाहिए था, वह उसने खो दिया है। अमेरिका ने अतिमहत्वाकांक्षा में अपने एक विश्वसनीय बनने जा रहे सहयोगी को अपने से दूर कर लिया, लेकिन अमेरिका के लिए मुश्किल इतनी भर ही नहीं है। यदि यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर रूस को अलग-थलग नहीं कर पा रहे हैं तो यह स्पष्ट होता जा रहा है कि दुनिया में उनकी दादागिरी के समाप्ति के दिन आ रहे हैं। अमेरिका ने बहुत प्रयास किया कि उसके उकसावे में चीन और भारत आपस में लड़ जाएं, लेकिन अंततः दोनों देशों ने इस उकसावे के आमंत्रण को पूरी बुद्धिमानी से अस्वीकार कर दिया। जहां चीन की गिरती हुई आर्थिक स्थिति भी इसके लिए जिम्मेदार है, वहीं भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत भी इसमें सहयोगी बनी। भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हम यूरोप और अमेरिका समर्थक रहना तो चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत राष्ट्र का अहित नहीं हो सकता। यदि ब्रिक्स सम्मेलन में अपनी-अपनी करेंसी में व्यापार करने पर सहमति बन जाती है तो यह डालर के प्रभाव को भी कमतर कर देगी। यदि अपना अलग पेमेंट गेटवे स्थापित करने पर बात आगे बढ़ी तो हर जगह अमेरिका की जो आंख लगी रहती है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। अब अमेरिका के पास दो विकल्प हैं- पहला कमला हैरिस जीतें और गलतियों को दोहराते रहें और दूसरा, ट्रंप जीतें और भारत के लिए कुछ बहुत बड़ा आफर करें। यदि अमेरिका और चीन में से किसी को चुनना होगा तो भारत अमेरिका को चुनेगा, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, उनमें भारत के दोनों हाथों में लड्डू है।

डा. भूपेंद्र सिंह@DrBS07

दोपारोपण की राजनीति

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हाल ही में कहा कि आनंद विहार में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उसका कारण उत्तर प्रदेश से आने वाली डीजल बसें हैं, तो बाकी पूरी दिल्ली का क्या? जब प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है, तब ये लोग पड़ोसी राज्यों को दोष देने लगते हैं। चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा। दिल्लीवासी अपनी सभी नाकामियों के लिए अपने पड़ोसी राज्यों यानी उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर दोषारोपण करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। आनंद विहार में दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च करके प्रदूषण कम करने के लिए यंत्र लगाए थे। जनता के टैक्स के पैसे को खर्च करने के बाद भी उनसे कुछ फायदा नहीं हुआ है।

विष्णु वशिष्ठ, दिल्ली

भरोसेमंद नहीं अमेरिका

भरोसे के लायक नहीं है अमेरिका- शीर्षक आलेख में राजीव सचान ने भारत के खिलाफ अमेरिका द्वारा किए जा रहे षड्यंत्रों का तथ्यपरक विश्लेषण किया है। वैश्विक स्तर पर भारत की हर जगह पर उपस्थिति अमेरिका को रास नहीं आ रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के समक्ष इसी दोस्ती का आभार जताया और कहा कि रूस हमारा सबसे भरोसेमंद मित्र है। ब्रिक्स देशों में अधिकांश अमेरिका विरोधी भी हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका खुलकर विरोध भले न करते रहे हों, लेकिन अमेरिका के पिछलग्गू तो नहीं हो हैं। दरअसल, ब्रिक्स देशों का संगठन बना ही इसलिए था, ताकि जी-7 की दादागिरी से निपटा जा सके। रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने के लिए रूस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आगे किया है। अमेरिका-भारत साझेदारी के भविष्य के बारे में व्यापक आशावाद के बावजूद रिश्ते जितने दिख रहे हैं, उससे कहीं अधिक नाजुक हैं।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रेषित किसी समाचार या विज्ञापन की सामग्री के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

नायक कभी मरा नहीं करते। वे हमेशा उन लोगों के दिल और दिमाग में जीवित रहते हैं, जो उनका अनुसरण करते हैं। -एमिली पॉटर

भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के वक्त में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दुनिया के दिग्गज नेताओं द्वारा प्रदर्शित एकजुटता के संदेश गहरे हैं। बैठक से इतर, प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच हुई वार्ता से एशिया की दो बड़ी शक्तियों के मध्य उच्च-स्तरीय कूटनीति के नए दौर की शुरुआत का संकेत भी मिलता है।

ब्रिक्स में भारत

भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के दौर में रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समूह के सोलहवें शिखर सम्मेलन में दुनिया के दिग्गज नेताओं ने जिस सहयोग व एकजुटता का प्रदर्शन किया, वह राहत देने वाला तो है ही, इसके संदेश भी महत्वपूर्ण हैं। साथ ही, सम्मेलन की शुरुआत के पहले से ही चीन और भारत के बीच रिश्तों की बर्फ जिस तरह से पिघलती दिखी है, उससे वैश्विक शक्ति संतुलन में आ रहे बदलावों के संकेत भी मिलते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने के समझौते की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बहुप्रतीक्षित वार्ता इस मायने में ऐतिहासिक है कि ये दोनों नेता करीब पांच वर्ष बाद द्विपक्षीय वार्ता के लिए आमने-सामने आए हैं। इससे एशिया की दो बड़ी शक्तियों के बीच उच्च-स्तरीय कूटनीति के नए दौर की शुरुआत का संकेत भी मिलता है। उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स देशों की संयुक्त आबादी दुनिया की कुल आबादी का 45 फीसदी और इसकी संयुक्त आर्थिक ताकत वैश्विक अर्थव्यवस्था का करीब 28 फीसदी हिस्सा है। तीस से ज्यादा देश ब्रिक्स से आधिकारिक रूप से जुड़ने की इच्छा जता रहे हैं, जिसमें तुर्किये जैसे नाटो के सदस्य देश भी शामिल हैं, जो ऐतिहासिक रूप से रूस विरोधी रहे हैं, तो यह बहुध्रुवीय होती दुनिया में ब्रिक्स की बढ़ती ताकत को ही दिखाता है। दरअसल, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने यह स्पष्ट किया है कि दुनिया का भविष्य अब केवल पश्चिमी शक्तियों द्वारा निर्धारित नहीं होगा। चीन और रूस की सक्रिय भागीदारी के साथ, इस मंच ने अमेरिका या यूरोपीय संघ के प्रभुत्व को चुनौती देने का भी संकेत दिया है। इसके बरअक्स, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे लोकतांत्रिक देशों की उपस्थिति इस समूह को एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे यह भी सुनिश्चित होता है कि ब्रिक्स केवल शक्ति संतुलन के खेल का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य एक समतामूलक व न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करना है। भारत दरअसल किसी एक गुट में बंधकर नहीं रहना चाहता। कभी गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति की बुनियाद रही, लेकिन आज वह ब्रिक्स का सदस्य है, तो क्वाड का भी। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर बैठक में शांति व संवाद में ही रूस-यूक्रेन संकट का समाधान होने की बात दोहराई, तो बैठक से इतर चीन के राष्ट्रपति से मिलकर संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बनाया। दरअसल, यह आज का भारत है, जो अपने हितों के हिसाब से किसी पक्ष में शामिल होने के फैसले करता है। कजान सम्मेलन ने साबित किया है कि ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग वैश्विक संतुलन को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है, जिसमें भारत की भूमिका और महत्वपूर्ण हुई है।

यह कैसा बांग्लादेश है

कट्टरवादी जो नया बांग्लादेश बना रहे हैं, उसे मैं जिहादिस्तान कहना ज्यादा पसंद करूंगी। उसी देश में मैं पैदा हुई थी, उसी देश में पली-बढ़ी। आज मुझे विश्वास ही नहीं होता। मेरा देश आज उग्र, असभ्य, कट्टर, हिंसक और बदला लेने पर उतारू देश बन गया है।

तस्लीमा नसरीन
चर्चित लेखिका

बांग्लादेश की 'एनजीओ' सरकार ने कुल आठ राष्ट्रीय दिवस रद्द कर दिए हैं। इनमें से छह दिवस तो शेख हसीना की मां, भाई आदि के जन्म दिवस थे, जिन्हें रद्द किया ही जाना चाहिए था। शेख हसीना ने बांग्लादेश को अपने पिता का देश मान लिया था, इसलिए सत्ता में रहते हुए अपने परिजनों की सेवा में ही वह व्यस्त थीं। वह भूल गई थीं कि बांग्लादेश में राजतंत्र या परिवारवाद वैध नहीं है। लोकतंत्र ही वैध है। हालांकि तब भी मेरा मानना है कि दो राष्ट्रीय दिवसों-सात मार्च और 15 अगस्त को रद्द किया जाना उचित नहीं। 15 अगस्त राष्ट्रीय शोक दिवस था, क्योंकि उस दिन शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के लोगों की नृशंस तरीके से हत्या की गई थी।

सात मार्च, 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने जो यादगार भाषण दिया था, उसे सुनने के बाद ही लोग मुक्तियुद्ध में भाग लेने के लिए कूद पड़े थे। इस दिन को राष्ट्रीय दिवस की मर्यादा न देने का अर्थ है बंगालियों के अस्तित्व को मर्यादा न देना। सात मार्च के भाषण, आजादी की घोषणा, मुक्तियुद्ध, विजय लाभ, पाकिस्तान के शोषण से मुक्ति, बांग्लादेश का जन्म-ये सब किन्हें सहन नहीं होता? जाहिर है, पाकिस्तान की सेना के विश्वस्त बंगाली रजाकारों को, उनके बच्चों और पोते-पोतियों को। इन लोगों का गुस्सा भारत पर भी है, क्योंकि बांग्लादेश को आजादी दिलाने में भारत ने मदद की थी। भारत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के बाद मूर्खों ने चुप्पी साध ली, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया कि भारत को नाराज करने पर लाभ के बजाय उनका नुकसान ही होने वाला है। लेकिन ये मुक्तियुद्ध के समर्थकों को चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। वे भूल गए कि सिर्फ अवामी लीग ही मुक्तियुद्ध की समर्थक नहीं है।

रजाकारों और उनके समूहों को छोड़कर बांग्लादेश के तमाम लोग मुक्तियुद्ध के समर्थक हैं। रजाकारों के बच्चे और उनके नाती-पोते यदि अब 21 फरवरी, 26 मार्च और 16 दिसंबर को रद्द घोषित करें, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। वे लोग अगर शहीद मीनार और स्मृतिसौध को ध्वस्त कर दें, तो हैरानी नहीं होगी। ये लोग अगर बांग्लादेश का नाम बदलकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान रख दें, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अगर ये लोग 14 अगस्त को आजादी का दिवस मनाएं, तो हैरानी नहीं होगी। राष्ट्रपिता के रूप में ये लोग अगर जिन्ना की फोटो लगाएं, तो आश्चर्य नहीं होगा। ये लोग अगर बांग्लादेश में शरीयत कानून लागू करें, तो हैरानी नहीं होगी। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के सहयोगी और बांग्लादेश की कथित क्रांति के सूत्रधार महफूज आलम की पहली बार फेसबुक पोस्ट देखकर मैं डर गई। उनकी पोस्ट में लिखा है कि देश की एक इंच जमीन भी अवामी लीग या मुजीब समर्थकों के लिए नहीं है। वह कहना चाहते थे कि अवामी लीग नरसंहार की दोषी है, उसके लोगों ने आंदोलनकारी छात्रों की हत्या की है। इन सबका हिसाब होगा। हिसाब तो सबका ही होना चाहिए। जुलाई-अगस्त की कथित क्रांति से जो जिहादी जुड़े थे, उन्होंने तो पुलिस के लगभग तीन हजार जवानों का गला काटकर सड़कों पर उनकी लाशें उल्टी लटका दी थीं। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की हत्या भी तो नरसंहार है, इन मामलों में भी न्याय क्यों नहीं होना चाहिए?

महफूज आलम छात्रों की हत्या को तो नरसंहार कह रहे हैं, पुलिस के जवानों की हत्या को नहीं। 15 जुलाई से आठ अगस्त तक जो खून-खराबा हुआ, उसकी जांच न होने से संबंधित जो कानून अंतरिम सरकार ने पारित किया है, मुजीब समर्थकों पर वह लागू नहीं होगा। सूत्रधार का कहना है कि बदला लेने की राजनीति वह करना नहीं चाहते, लेकिन विवश होकर करनी पड़ रही है। इसका मतलब वह मुजीब समर्थकों की हत्या करना चाहते हैं। उनका कहना है कि मुजीब समर्थकों के लिए एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ी जाएगी। यानी अवामी लीग से जुड़े लोगों को देश से फिलहाल जाएगा। लेकिन किसी को देश से भागने भी तो नहीं दिया जा रहा। यानी मुजीब समर्थकों को फांसी पर झुलाया जाएगा या उन्हें उम्रकैद की सजा मिलेगी। मुजीब के जिस समर्थक ने कभी खून नहीं किया, किसी हत्या का समर्थन नहीं किया, उसे भी सजा मिलेगी, क्योंकि उसने मुजीब के विचारों पर भरोसा किया।

इसका अर्थ क्या हुआ? यानी यह सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोगों की आजादी और विरोधी विचारधारा पर भरोसा नहीं करती। यानी यह सरकार लोकतंत्र, मानवाधिकार और धर्मनिरपेक्षता पर भरोसा नहीं करती। ऐसी सरकार तो तानाशाही, हिंसक हसीना सरकार से भी सौ गुना हिंसक और तानाशाह है।

इस बीच बंगाल की अग्निकन्या मतिया चौधुरी का निधन हो गया। वहां की मिट्टी में उन्हें जगह नहीं मिली। वैसे में उन्हें उनके दिवंगत पति पत्रकार बजलूर रहमान की कब्र में दफन किया गया। 1960 के दशक में तानाशाह पाक सैन्य जनरल अयूब खान के विरोध में जो छात्र आंदोलन हुआ था, उसमें मतिया चौधुरी ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। उस दौर में उन्हें चार बार जेल में रहना पड़ा था। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए बांग्ला अकादमी ने 2021 में उन्हें फेलोशिप दी थी। लेकिन इस वर्ष मुक्तियोद्धा को निधन के बाद राष्ट्र ने सम्मान नहीं दिया। 25 मार्च, 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ढाका समेत दूसरे इलाकों में बंगाली बुद्धिजीवियों का सामूहिक संहार किया था। वही काला दौर अब लौट रहा है। कई प्रसिद्ध पत्रकारों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लेखक-बुद्धिजीवी मोहम्मद जफर इकबाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। उन पर नरसंहार में लिप्त रहने का आरोप है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि इसी रास्ते से बांग्लादेश नई शुरुआत की ओर बढ़ेगा।

यूनुस सरकार जफर इकबाल की विरोधी है, क्योंकि वह रजाकार विरोधी हैं। वह बांग्लादेश के मुक्तियुद्ध के समर्थक हैं। इसी कारण उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। कट्टरवादी जो नया बांग्लादेश बना रहे हैं, उसे मैं जिहादिस्तान कहना ज्यादा पसंद करूंगी। उसी देश में मैं पैदा हुई थी, उसी देश में पली-बढ़ी। आज मुझे विश्वास ही नहीं होता। मेरा देश आज उग्र, असभ्य, कट्टर, हिंसक और बदला लेने पर उतारू देश बन गया है। मुझे नहीं लगता कि लाल कालीन बिछा देने पर भी कभी मैं वहां लौटना चाहूंगी।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

जे. कृष्णमूर्ति

सही अर्थों में हमारे जीवन में एकांत तभी होता है, जब हम हर समस्या पर अपना पूरा ध्यान देते हैं और उसे तत्काल हल कर लेते हैं, उसे अगले दिन या अगले मिनट तक ढोते नहीं चलते।

बीते हुए कल के बोझ को ढोने से बचें

सामान्यतः जिस ढंग का जीवन हम बिताते हैं, उसमें शायद ही कभी एकांत मिलता है। अगर कभी हम एकांत में होते भी हैं, तो अनेक तरह के प्रभाव, अनुभव, ज्ञान, स्मृतियां, चिंताएं, संघर्ष और दुख हमें चारों ओर से घेरे रहते हैं। इन्हीं चीजों के कारण हमारा मन ज्यादातर मंद, मूढ़ और असंवेदनशील हो जाता है। यह हर रोज एक ही ढर्रे के बंधे-बंधाए जीवन को जिए चला जाता है, तो क्या हम सही अर्थों में कभी एकांकी हो पाते हैं? या हम सदा अपने साथ बीते हुए कल के बोझ को ही ढोते चल रहे हैं? एक बार दो संन्यासी एक गांव से दूसरे गांव को चले जा रहे थे। रास्ते में अचानक उनकी नजर एक युवा लड़की पर पड़ी, जो नदी के किनारे बैठी रो रही थी। उनमें से एक संन्यासी उस लड़की के पास जाकर बोला, 'बहन, तुम क्यों रो रही हो?' उस लड़की ने कहा, 'नदी के उस पार जो घर तुम देख रहे हो, वहीं मैं रहती हूं। आज सवेरे जब मैं इस पार आई तो बिना किसी कठिनाई के मैं पैदल चलकर नदी पार कर गई, लेकिन अचानक नदी में पानी बढ़ गया है, इसलिए मैं अब घर नहीं लौट सकती। कोई नाव भी नहीं है।' उस संन्यासी ने कहा कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। और यह कहकर उसने लड़की को अपने कंधे पर उठा लिया और उस पार छोड़ आया। लौटकर वह पुनः अपने संन्यासी मित्र के साथ यात्रा पर चल पड़ा। कोई दो घंटे बाद दूसरा संन्यासी पहले संन्यासी से बोला, भाई, हम लोगों ने व्रत लिया था कि कभी किसी औरत को नहीं छूएंगे। इसलिए तुमने आज जो कुछ किया है वह एक घोर पाप है। क्या तुम्हें उस औरत को छूने पर सुख, रोमांच और एक गहरी उत्तेजना की अनुभूति नहीं हुई? दूसरे संन्यासी ने उत्तर दिया, मैं तो उस औरत को दो घंटे पीछे छोड़ आया, क्या तुम उसे अभी तक ढो रहे हो?

हम सब भी वही कर रहे हैं। जो बीत गया उसके बोझ को हम ढोते चल रहे हैं। उसके प्रति हम कभी नहीं मरते। उसे हम अपने से कभी अलग नहीं करते। सही अर्थों में हमारे जीवन में एकांत तभी होता है, जब हम हर समस्या पर अपना पूरा ध्यान देते हैं और उसे तत्काल हल कर लेते हैं, उसे अगले दिन या अगले मिनट तक ढोते नहीं चलते। तब हम भले ही लोगों से भरे हुए एक घर में रह रहे हों या खचाखच भरी बस में सफर कर रहे हों-हम सदा एकांत में ही होते हैं। और इस एकांत का अर्थ है-एक निष्कलुष और ताजा मन। आंतरिक रूप से एकांत और अवकाश (विस्तार और फैलाव) को पाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे ऐसा बोध होता है कि आप कुछ करने के लिए, होने-जाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं-मानो आप उन्मुक्त आकाश में उड़ान भर रहे हों। हमारे पास राजनीतिक स्वातंत्र्य भले ही हो, लेकिन हम आंतरिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं और इसीलिए हमारे भीतर विस्तार और फैलाव नहीं है। अपने भीतर इस विराट विस्तार और फैलाव के बिना कोई भी सार्थक सहयोग न विकसित हो सकता है और न कार्य कर सकता है।

अतीत से सीखें, चिपके नहीं

सूत्र

अतीत संदर्भ का स्थान है, निवास का स्थान नहीं, अतीत सीखने का स्थान है, रहने का स्थान नहीं। हमारी पिछली गलतियां हमें मार्गदर्शन करने के लिए हैं, न कि हमें परिभाषित करने के लिए हैं। यदि आप अभी भी अतीत से चिपके हुए हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखें हर नई शुरुआत किसी दूसरी शुरुआत के अंत से आती है।

दूसरा पहलू

रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध के लिए यूक्रेन की सेना में युवाओं को पकड़कर जबरन भर्ती कराया जा रहा है।

सैन्य भर्ती के डर से छिपते यूक्रेन के युवा

ओक्यान एलजी यूक्रेन के टॉप म्यूजिक ब्रांड्स में से एक है। उसका अपना स्टेडियम है और देशभक्ति वाले गीतों की भी उसके पास भरमार है। इस कारण दशकों से यह रूस-विरोध का मंच भी है। इसके कन्सर्ट के टिकट मिलना बहुत कठिन होता है। लेकिन राजधानी कीव में अचानक इसके कन्सर्ट के टिकट सुलभ हो गए। इसका कारण भी अजीब था। पुलिस और सरकारी अधिकारी कन्सर्ट हॉल के बाहर छिपकर खड़े हो गए। वे कन्सर्ट सुनने आए तमाम युवाओं से उनके कागजात देख रहे थे। दरअसल ये उन युवाओं की खोज में आए थे, जिन्होंने सेना में भर्ती के सरकार के आवश्यक निर्देश की अनदेखी की थी। वैसे युवाओं के पकड़ में आते ही वे उन्हें सीधे सैन्य भर्ती के लिए ले गए। पकड़कर ले जा रहे एक ऐसे यूक्रेनी युवा का वीडियो वायरल हुआ है, जो लोगों से मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था।

मारिया वरन्निकोवा

सेना में भर्ती होने के डर से लोगों, विशेषकर युवाओं ने किसी कन्सर्ट या कार्यक्रमों के साथ ही खुले में जाना लगभग बंद कर दिया है।

यूक्रेन के कानून के मुताबिक, युवाओं को हर साल सरकारी इंटर ऑफिसर्स के सामने अपने दस्तावेजों का नवीकरण कराना जरूरी है, ताकि उनमें से युवाओं को जबरन पहले पर सेना में लिया जा सके।

ऐसे लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए पकड़कर ले गए। खारकीव, निप्रो और देश के दूसरे बड़े शहरों में भी सैन्य भर्ती अभियान चल रहा है। खारकीव में तो पुलिस और सरकारी अधिकारियों के एक कन्सर्ट हॉल के बाहर खड़े होने पर आयोजकों ने कार्यक्रम ही रद्द कर दिया।

रूस के खिलाफ युद्ध में भारी संख्या में सैनिकों को खोने के बाद यूक्रेन का रुख अब कमोबेश रक्षात्मक है। यूक्रेन के कानून के मुताबिक, युवाओं को हर साल सरकारी इंटर ऑफिसर्स के सामने अपने दस्तावेजों का नवीकरण कराना जरूरी है, ताकि उनमें से युवाओं को जबरन पहले पर सेना में लिया जा सके। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस साल साढ़ लाख युवाओं ने, जो यूक्रेन की आबादी का 16 प्रतिशत हैं, अपने दस्तावेजों का नवीकरण नहीं करवाया है। ऐसे में, सरकार को मजबूरन युवाओं को पकड़कर ले जाना पड़ रहा है। इसका नतीजा यह है कि लंबे समय तक रूस-विरोधी माहौल रहने के बाद यूक्रेन में अब युद्ध के खिलाफ वातावरण बनता जा रहा है।

©The New York Times 2024

आंकड़े

मोबाइल निर्यात

भारत मोबाइल फोन निर्यात में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। भारत ने बीते आठ वर्षों में 15 अरब डॉलर से ज्यादा के मोबाइल फोन निर्यात किए हैं।

2016	0.22
2019	1.60
2022	5.80
2023	11.10
2024	15.58

आंकड़े वित्त वर्षों में मोबाइल फोन निर्यात के, अरब डॉलर में | स्रोत : ICEA, McCAI

रानी ने सुदर्शन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। राजा ने सुदर्शन के वध की आज्ञा दी। जल्लाद ने गर्दन काटने के लिए हाथ उठाया, तो वह उठा ही रह गया।

भक्त सुदर्शन

अंतर्यात्रा
संकलित

सेठ सुदर्शन बहुत ही सुंदर युवा पुरुष थे और अपना गृहस्थ जीवन बड़ी सच्चरित्रता के साथ बिताते थे। वह अक्सर भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। प्रत्येक चतुर्दशी को उपवास करते और रात्रि के समय श्मशानभूमि में जाकर ध्यान लगाया करते थे। एक बार नगर की रानी उनके रूप पर मोहित हो गई और अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर उन्हें डिगाने की चेष्टा करने लगी। लेकिन सच्चरित्र सुदर्शन उसके प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए।

एक बार जब वह चतुर्दशी की रात्रि को श्मशानभूमि में ध्यान लगा रहे थे। तब रानी ने एक चाल चली और उसने अपनी दूती को श्मशानभूमि भेजा। दूती सुदर्शन को कंधे पर उठा लाई और रानी की शय्या पर लिटा दिया। सुदर्शन को ध्यान में देखकर रानी अनेक प्रकार की कुचेष्टाओं द्वारा उनकी समाधि भंग करने की कोशिश करने लगी। अंत में दिन निकल आया, लेकिन रानी की वासना पूर्ण न हो सकी। सुदर्शन समाधि में ही लीन थे। इसके बाद रानी ने साजिश रची और अपने शरीर को नोच-खसोटकर गैने-चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर राजा आए। उनसे कहा कि सुदर्शन ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और अब भेद खुल जाने के भय से ध्यान का ढोंग रच रहा है। राजा ने यह सुनते ही सुदर्शन के वध की आज्ञा दी। सुदर्शन को पुनः श्मशानभूमि ले जाया गया और वहां जल्लाद ने उनकी गर्दन काटने के लिए हाथ उठाया कि उसका हाथ उठा ही रह गया। इसके बाद रानी की साजिश का खुलासा हो गया।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 06 मार्च, 1961

दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति का विरोध

दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति पर पुनः कड़े प्रहार

राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री सम्मेलन में नाइजीरिया, लंका, मलाया व न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों ने दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद व जाति भेद नीति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जनता जाति भेद नीति की सख्त विरोधी है।

सिर्फ किसानों पर ही दोष न मढ़ें

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए अकेले किसानों को दोष देने से काम नहीं चलेगा, शहरवासी भी पूरी लापरवाही बरत रहे हैं।

रोहित कौशिक

मुद्दा

दिल्ली-एनसीआर में दिवाली से पहले फिर वायु की गुणवत्ता खराब हो गई है। हर साल अक्तूबर-नवंबर में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा पराली जलाने के कारण भी प्रदूषण बढ़ता है। इस प्रदूषण के लिए किसानों द्वारा पराली जलाने को एक बड़ा कारण माना जाता है, लेकिन पराली जलाना यह इस समस्या का एक कारण है। कुछ लोग और बुद्धिजीवी किसानों द्वारा पराली जलाने की प्रक्रिया को ऐसे प्रचारित करते हैं, जैसे इस प्रदूषण का केवल यही एक कारण है।

केवल पराली जलाने की प्रक्रिया को ही इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। ऐसे अनेक कारण हैं, जो इन दिनों प्रदूषण बढ़ाकर हवा को गुणवत्ता खराब करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा की सरकारों को फटकार लगाई है। पराली न जलाने को लेकर बड़ी-बड़ी बातें तो की जाती हैं, लेकिन किसानों के सामने इस समस्या का कोई व्यावहरिक समाधान पेश नहीं किया जाता है। वहीं, किसानों की लापरवाही प्रदूषण की समस्या को बढ़ा देती है। इस मामले में किसानों को ही दोष क्यों दिया जाए, शहरी लोग भी अपनी जिम्मेदारी कहां समझते हैं। करवा चौथ पर कई शहरों में जिस तरह से पटाखे छोड़े गए, वह यह दर्शाता है कि पर्यावरण और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर हम कितने लापरवाह हैं। दिवाली पर भी हम अपनी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का परिचय न दें, यह कैसे हो सकता है। कुल मिलाकर आने वाला समय प्रदूषण के लिहाज से दिल्ली-एनसीआर और देश के कई शहरों के लिए अच्छा नहीं है।

वायु प्रदूषण बढ़ने से सांस के रोगियों की समस्या बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण बढ़ने पर सरकारें जरूर सक्रिय होती हैं, लेकिन जैसे ही प्रदूषण कम होता है, सरकारें पुनः सो जाती हैं, जबकि वायु प्रदूषण कम करने वाले उपायों पर पूरे साल सक्रियता के साथ काम होते रहना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि कोई भी तकनीक प्रदूषण को कम करने में सहायता तो कर सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती। कई बार मौसम में परिवर्तन भी इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। रही-सही कसर हमारी नासमझी और मानवीय गतिविधियां पूरी कर देती हैं। यही कारण है कि हर साल अक्तूबर-नवंबर में होने वाले इस प्रदूषण को कम करने के लिए नीतियां तो बनती हैं, लेकिन उनका सही ढंग से क्रियान्वयन न होने के कारण नतीजा ढाक के तीन पात रहता है। सरकारी नीतियों के सही ढंग से क्रियान्वयन के साथ जब तक जनता पूर्ण रूप से जागरूक नहीं होगी, वायु प्रदूषण को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता।

धूल, धुएं और कुहासे से बना स्मॉग हमारे लिए कई समस्याएं पैदा करता है। जब ईंधन जलता है, वायुमंडलीय प्रदूषण या गैसें हवा में मौजूद सूरज की रोशनी और वातावरण में इसकी गर्मी के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, तब स्मॉग बनता है। इस मौसम में हर साल स्मॉग के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। निर्माण कार्य और वाहनों का धुआं भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। वाहनों के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जैसे खतरनाक तत्व एवं गैसें होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। कार्बनमोनोऑक्साइड जब सांस के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंचती है, तो वह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक तत्व बनाती है। इस तत्व के कारण शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन सुचारु रूप से नहीं हो पाता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब सांस के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंचती हैं, तो वह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक तत्व बनाती है। इस तत्व के कारण शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन सुचारु रूप से नहीं हो पाता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कम खतरनाक नहीं हैं। नाइट्रोजन मानोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा घटाते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फेफड़ों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसकी अधिकता से दमा और ब्रोंकाइटिस जैसे रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। वातावरण में हाइड्रोकार्बन की अधिकता कैंसर जैसे रोगों के लिए जिम्मेदार है। वाहनों से निकलने वाला एथिलीन जैसा हाइड्रोकार्बन थोड़ी मात्रा में भी पौधों के लिए हानिकारक है।

वास्तविकता यह है कि आज पर्यावरण के अनुकूल तकनीक के बारे में सोचने की फुर्सत किसी को नहीं है। पुराने जमाने में पर्यावरण के हर अवयव को भगवान का दर्जा दिया जाता था। इसीलिए हम पर्यावरण के हर अवयव की इज्जत करना जानते थे। नए जमाने में पर्यावरण के अवयव वस्तु के तौर पर देखे जाने लगे और हम इन्हें मात्र भोग की वस्तु मानने लगे। उदाहरकण की आंधी ने तो हमारे समस्त ताने-बाने को ही नष्ट कर दिया। सवाल यह है कि क्या खोखले आदर्शवाद से वायु प्रदूषण का मुद्दा हल हो सकता है? इसलिए अब समय आ गया है कि हमें हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए गंभीरता के साथ काम करना होगा।

सम्पादकीय

चीन सीमा पर हुआ समझौता

भारतीय सेना अब कर सकेगी निगरानी, 2020 में किया था अतिक्रमण

जब भी दो देशों के बीच सीमा पर तनाव बना रहता है, तो स्वाभाविक रूप से उनका आर्थिक विकास प्रभावित होता है। इसलिए दुनिया भर में प्रयास किए जाते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ तनाव का रिश्ता न रहे। मगर अक्सर वर्चस्ववादी नीतियों के चलते कुछ देशों में परस्पर टकराव बना रहता है। भारत और चीन के बीच भी लंबे समय से रिश्ते इसीलिए मधुर नहीं हो पाते कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी की मर्यादा का पालन नहीं करता। वह अपनी विस्तारवादी नीति पर कायम है। 15 जून, 2020 को चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी के भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण किया था। दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव हुआ। उसके बाद चीन ने भारत के हिस्से वाले छह क्षेत्रों में अतिक्रमण कर लिया था। तबसे लगातार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। अच्छी बात है कि दोनों देशों के बीच अब अपने सैनिकों को वापस बुलाने और एलएसी पर 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने पर सहमति बन गई है। सोमवार को भारत ने इसकी सूचना जारी की थी, अब चीन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। चीन ने कहा है कि वह भारत के साथ मिल कर सीमा संबंधी विवाद का हल निकालने का प्रयास करेगा। यह अच्छी बात है कि गलवान में हुए सैन्य संघर्ष के बाद भी चीन बिना किसी हील-हुज्जत के हमेशा बातचीत की मेज पर बैठता रहा। तब से सैन्य अधिकारी स्तर की बीस से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रियों के स्तर पर भी बातचीत के कई दौर हो चुके हैं। इन्हीं बैठकों और बातचीत का नतीजा है कि चीन ने भारत के छह में से चार क्षेत्रों देपसांग, गलवान, हाटस्प्रिंग और पैंगोंग से अपनी सेना हटा ली थी। मगर अभी भी दौलतबेग ओल्डी और डेमचोक में उसका कब्जा बना हुआ था। भारतीय सैनिक उन क्षेत्रों में गश्त करने नहीं जा सकते थे। ताजा समझौते के अनुसार उन दोनों क्षेत्रों को भी खोल दिया गया है। अब भारतीय सेना अपने तय क्षेत्रों में गश्त कर सकेगी। भारत ने इसे चीन का सकारात्मक रुख बताया है। दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के लिए उनकी सेनाओं का परस्पर मेलजोल बढ़ना जरूरी है।

हालांकि चीन के किसी भी रुख पर दावे के साथ कुछ कहना मुश्किल होता है। पूर्वी लद्दाख में उसके ताजा सकारात्मक रुख से निस्संदेह भारतीय सेना का तनाव काफी कम होगा, मगर चीन कब अपना रुख बदल ले, कहना मुश्किल है। भारत के पड़ोसी देशों, पाकिस्तान और श्रीलंका में विकास परियोजनाओं के जरिए उसने अपनी मौजूदगी बढ़ाने में काफी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। समय-समय पर वह भारतीय हिस्से वाली जगहों को अपना बता कर उनका नाम बदलता और उन्हें अपने नक्शे में दिखाता रहा है। हिंद महासागर में वह अपनी मौजूदगी बनाए रखने और बढ़ाने का लगातार प्रयास करता देखा जाता है। इसलिए उचित ही भारत कोई बड़ा दावा करने से बच रहा है। मगर यह भारत की बड़ी कामयाबी कही जाएगी कि उसने बहुत सावधानी और संयम के साथ चीन की अतिक्रमण वाली जगहों से वापस लौटने को राजी कर लिया।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग 4 वर्षों के बाद भारत चीन व राष्ट्रअध्यक्षों की द्विपक्षीय वार्ता परिणामों पर दुनियाँ की नज़रें

हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन केज़ान रूस 22-24 अक्टूबर 2024 की करें तो, यह अंग्रेजी अक्षरों बीआरआईसीएस से बना है। ब्रिक्स दुनियाँ की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। जैसा कि नाम से अनुमान लगाया जा सकता है, ये देश हैं - ब्राजील, रुस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स के विचार की परिकल्पना वर्ष 2001 में की गई थी, जो 2006 में ब्रिक के रूप में सामने आई और 2010 में जब इस समूह में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, तो यह ब्रिक्स बन गया। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुए 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार अब समूह में 10 देश शामिल हैं। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं।

कर विशेषज्ञ स्तंभकार एडवोकेट
किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर करीब करीब सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जिसमें भारत उस मंच का सदस्य है या नहीं, उसकी उपस्थिति कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता! जिसका सदस्य है,वहां तो अपनी बौद्धिक क्षमता का आगाज़ करता ही है,परंतु जिसमें सदस्य नहीं है उसमें भी बतौर अतिथि आमंत्रित किया जाता है। अभी हाल ही में इस्लामाबाद पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन में भारत ने उनके घर में ही यानें मेजबानी में पारदर्शिता से खरी-खरी सुनाई। आज हम इस विषय पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कज़ान रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22-24 अक्टूबर 2024 शुरू है,भारतीय पीएम 22 अक्टूबर 2024 को कैज़ान पहुंचे जहां उनका जोरदार ढंग से स्वागत किया गया।परंतु इस 16 वें शिखर सम्मेलन के बीच जहां एक और रूस-यूक्रेन व इजरायल-हमास -ईरान युद्ध अपने चरम स्तरपर है वहीं भारतीय पीएम के ब्रिक्स से अलग एक द्विपक्षीय बातचीत रूस ईरान तथा विशेष रूप से 23 अगस्त 2024 को चीन के साथ करना इसकी अद्भुत विशेषता को रेखांकित करता है, क्योंकि दुनियाँ जानती है भारत शांति कायम रखने में विश्वास रखता रखता है व उसे इसमें महारत हासिल है, ऐसे वक्त में इन तीनों देशों से अलग-अलग बातचीत करना विशेष बात है, क्योंकि स्वाभाविक ही है युद्ध को रोकने संबंधी बातचीत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जो कि प्रेस रिलीज में नहीं आई है, परंतु इतना हम समझ सकते हैं कि अब वैश्विक शांति की उम्मीद बढ़ गई है।यानें 16 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सकारात्मक आगाज़ होगा व विशेष रूप से 4 वर्षों के बाद चीनी राष्ट्रपति से भारतीय पीएम के द्विपक्षीय वार्ता का सकारात्मक परिणाम का अंजाम मील का पत्थर साबित होगा इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,16 वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन व भारत की ईरान रूस व चीन से द्विपक्षीय वार्ता का ऐतिहासिक नतीज़े का आगाज़। ब्रिक्स आज दुनिया की 43 प्रतिशत आबादी, दुनिया के 32 प्रतिशत भूमि क्षेत्र, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 35 प्रतिशत और विश्व निर्यात का 20 प्रतिशत कवर करता है। समूह के अनुसार, यह पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग विकसित करने के अवसर प्रदान करता है जो देशों के सतत विकास और वृद्धि में योगदान देता है। साथियों बात अगर हम दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को भारतीय पीएम और रूसी राष्ट्रपति की द्विपक्षीय वार्ता की करें तो,बता दें कि इससे पहले भारतीयपीएम ने मंगलवार को कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर पहले रूसी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान पीएम ने रूसी राष्ट्रपति के साथ बातचीत में कहा

कि रूस-यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए और भारत इसके लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है।पीएम ने टेलीविजन पर प्रसारित अपनी शुरुआती टिप्पणी में पुतिन से कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहालीका पूर्ण समर्थन करता है। आगे कहा कि पिछले तीन महीनों में रूस की उनकी दूसरी यात्रा दोनों देशों के बीच भनिष्ठ तालमेल और गहरे विश्वास को दर्शाती है।पीएम ने कहा,हम रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के मुद्दे पर लगातार संपर्क में हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारा मानना ??है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। इसके बाद पीएम ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मुलाकात की। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच पेजेशकियन ने पश्चिम एशिया में शांति की आवश्यकता पर बल दिया तथा सभी पक्षों के साथ अपने अच्छे संबंधों के कारण संघर्ष को कम करने में भारत की भूमिका पर जोर दिया। साथियों बात अगर हम 22 सितंबर 2024 को ईरान व भारत की द्विपक्षीय वार्ता की करें तो, पीएम ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस साल जुलाई में वें के ईरान के राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात थी उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। उन्होंने चाबहार बंदरगाह, लोगों के बीच संपर्क, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, गाजा की स्थिति, अफगानिस्तान में स्थिरता और सुरक्षा और यूक्रेन संघर्ष सहित कई विषयों पर चर्चा की।भारत और ईरान महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारभारत और ईरान के बीच लंबे समय से सभ्यतागत संबंध हैं। ईरान भारत के विस्तारित पड़ोस में स्थित है और दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण समानताएं हैं। भारत और ईरान महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हैं।भारतीय विदेश मंत्री ने जनवरी 2024 में ईरान का दौरा किया। सितंबर 2023 में ब्रिक्स में शामिल होने के बाद यह उनकी पहली ईरान यात्रा थी।इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता पर गंभीर रूप से चिंतित भारत ने इस महीने की शुरुआत में पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति के बढ़ने पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान दोहराया था। इस साल अप्रैल में एक बयान में भारत ने कहा था कि वह इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता पर गंभीर रूप से चिंतित है, जो क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है।इससे तत्काल तनाव कम करने, संयम बरतने,हिंसा से पीछे हटने औरकूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया। बैठक में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पेजेश्कियान के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई और दोनों पक्षों ने इसे सार्थक चर्चा कहा है। साथियों बात अगर हम विशेष रूप से भारतीय पीएम और चीन के राष्ट्रपति की द्विपक्षीय वार्ता की करें तोपीएम बुधवार को रूस के कज़ान में ब्रिक्स समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की,यह दोनों नेताओं के बीच पांच वर्षों में पहली औपचारिक मुलाकात थीकज़ान में मंगलवार शाम को एक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव ने पुष्टि की कि यह बैठक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई, इस बैठक को लेकर यह उम्मीद की जा रही है कि यह दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुदृढ़ करने और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगी।दोनों शीर्ष नेताओं की मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जबकि भारत ने सोमवार को घोषणा की कि दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में अपने गतिरोध को सुलझाने के लिए एक समझौता किया है। विदेश सचिव ने कहा,पिछले कुछ हफ्तों में, भारतीय और चीनी कूटनीतिक तथा सैन्य वार्ताकार विभिन्न मंचों पर आपस में निकट संपर्क में रहे हैं।इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पेट्रोलिंग व्यवस्थाओं के लिए एक समझौता किया गया है, जिससे सैनिकों की वापसी और 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न समस्याओं का समाधान होगायह समझौता पीएम के कज़ान जाने से पहले की गई घोषणा है, और इसे दोनों देशों के संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चीन ने भी पूर्वी लद्दाख में उसकी और भारत की सेनाओं के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए नई दिल्ली के साथ समझौता होने की मंगलवार को पुष्टि की,चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा भारत और चीन दोनों देशों की सीमा से संबंधित मुद्दों पर राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए निकट संपर्क में रहे हैं,उन्होंने कहा,अब दोनों पक्ष प्रासंगिक मामलों पर एक समाधान पर पहुंच गए हैं जिसकी चीन बहुत सराहना करता है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार अब कई विशिष्ट लक्षणों को पूत करेगे। एक अब एक अवसर पाएगे है कि अपने लोगन के प्रेमे पौसरते बोल है, जहा अपको विशेष कुछ रहेगे और दूसरी तरफ, अपको दिन बाकी से सावधान रहना पड़ेगा। हम न किसी तरह से और और अंदर हुई को सुलझाने तथा व्यवसायक जेनर की समस्या वार्तो, सीमा पराजयित तरीको से हो, जहा एक व्यवसायक तरी तरह और आपसी से लक्ष प्रदान करेगा

मेष
आज इगो के कारण किसी से बातचीत में मनमुटाव हो सकता है। मित्रों के साथ किसी बात विवाद हो सकता है। स्वभाव में आवेश और क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी। धार्मिक कामों में धन का खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृष
आप में आज आत्मविश्वास कूट-कूटकर भरा रहेगा। किसी भी काम को करने के लिए आप जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं। पिता तथा बड़ों की ओर से लाभ होगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। वाणी में उग्रता ना रखें।

मिथुन
आपको उग्र स्वभाव पर संयम रखने की सलाह दी जाती है। आज आप मानसिकरूप से थकान का अनुभव करेंगे। अधिक परिश्रम की तुलना में कम फल की प्राप्ति होगी। संतान के विषय में आपको चिंता हो सकती है।

कर्क
आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। व्यापार स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा। उच्च अधिकारी आप पर प्रसन्न रहेंगे। आप का हर काम आज सफलता से पूरा होगा। आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी में पदोन्नति भी हो सकती है। वाहन सुख मिलेगा।

सिंह
आज आपका स्वास्थ्य नरम-गरम रह सकता है। शारीरिक रूप से आलस्य और अशांक का अनुभव करेंगे। मन में चिंता रह सकती है। गलत कामों से दूरी बनाए रखें। किसी भी योजना को सावधानीपूर्वक करें।

कन्या
आज अचानक धन खर्च होने का योग है। यह खर्च स्वास्थ्य के कारण भी हो सकता है। व्यावहारिक या सामाजिक काम के लिए बाहर जाना हो सकता है। खान-पान में ध्यान रखें। क्रोध तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहें। व्यापार में बाधाएं उपस्थित होंगी।

तुला
विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। सरकारी कामों में आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है। संतान के लिए पूंजी निवेश करेंगे। नई योजना का आरंभ करने के लिए आज अनुकूल दिन है। सरकारी काम में लाभ होगा।

वृश्चिक
रोमांस के लिए आज अनुकूल दिन है। आज का हर कार्य आप दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास से पूरा करेंगे। प्रवास-पर्यटन की संभावनाएं है। अच्छा भोजन और नए वस्त्र मिलने का अवसर मिल सकता है। भागीदारी से लाभ होगा।

धनु
अधिकारियों से काम का उचित फल भी मिल सकता है। भाई-बंधुओं के साथ कोई झगड़ा दूर होगा। विचार लगातार परिवर्तन होते रहेंगे। आर्थिक विषय में सावधानी बरतनी आवश्यक है। नेगेटिव विचारों से मन परेशान रह सकता है।

मकर
मानसिक रूप से स्वस्थता का अनुभव नहीं करेंगे। भावना से काम में मन नहीं लगेगा। कुटुंबजनों के साथ किसी विषय पर वाद-विवाद हो सकता है। विद्यार्थियों को अभ्यास का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा।

कुंभ
आपका आज का दिन शुभफलदायी है। कई क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। मित्रों से लाभ होगा और उनके पीछे धन खर्च भी हो सकता है। पर्यटन स्थल की सैर आपको मोहित करेगी। परिवनों से मुलाकात आनंददायी हो सकती है।

मीन
सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। पेट दर्द से परेशानी हो सकती है। आज आप किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ करेंगे। उसमें सफलता भी प्राप्त भी करेंगे। पिता की ओर से आपको लाभ हो सकता है। संतान के लिए पूंजी निवेश करेंगे।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी चूना राम जाट। इनका जन्म बीकानेर में 24 नवम्बर सन 1984 को हुआ। आज इन्हें सरकार ने पाली जिले की कमान दी हुई है। एक अच्छे आईपीएस ऑफिसर के रूप में इन्हें पूरे राजस्थान में जाना जाता रहा है। अजमेर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया गया अभियान पूरे राज्य में मिसाल बना। अपराधियों पर गाज बनकर टूटी इनकी टीम का इन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाया है। ऐसे में टीम भी इनके एक इशारे पर अपराधियों के दांत खट्टे करने का मादा रखती है। इनकी विभिन्न जिलों में एसपी शिप लगातार जारी है। अपनी फॉस के लिए हमेशा अच्छा सोचने वाले पुलिस अधिकारी हैं चूना राम जाट। ये हाल में पुलिस अधीक्षक पाली लगे हुए हैं इससे पहले ये पुलिस अधीक्षक, अजमेर। पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा (जांच) जयपुर। पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़। पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।पुलिस अधीक्षक, टोंक। पुलिस अधीक्षक, दौसा। कमांडेंट, राज्य आपदा मोचन बल, राजस्थान,जयपुर। सहायक पुलिस अधीक्षक वृत्ताधिकारी.चतुर्थ, कोटा शहर। वृत्ताधिकारी, अजमेर दक्षिण। प्रशिक्षणाधीन एसयूएनपीए, हैदराबाद में भी रह चुके हैं। हमेशा अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास वाले पुलिस के स्लोगन के साथ खड़े नजर आए हैं।

अजमेर एसपी शिप के दौरान चूनाराम जाट ने एक अनूठी पहल करते हुए बिना सुरक्षा के साइकिल पर सवार होकर शहर में गश्त की। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों को चेक किया और यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने करीब 15 किलोमीटर तक साइकिल चला कर शहर की कानून व्यवस्था की जानकारी ली थी। वहीं गश्त के दौरान पटाखे जैसी

श्री चूनाराम जाट (आरआर-13) आई पी एस

आवाज करने वाले बाइकर्स पर भी बड़े स्तर की कार्रवाई की ताकि बाइकर्स शहर में दहशत ना फैला सके। आईपीएस जाट राजस्थान में एक युवा और ऊर्जावान अधिकारी हैं। वह हमेशा कानून व्यवस्था और बेहतर पुलिसिंग के लिए नए तरीके अपनाते हैं। एक जांबाज पुलिस अधिकारी के रूप में पूरे राजस्थान में इन्हे जाना जाता है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

24 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

- चौथे सिख गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना 1577 में की, शहर का नाम तालाब अमृत सरोवर के नाम पर रखा गया।
- जेसुइट पादरी एस.जे थामस भारत आने वाले पहले अंग्रेज थे, वह पुर्तगाली नौका से 1579 को गोवा पहुंचे।
- मुगल शासक जहाँगीर ने 1605 को आगरा में गद्दी संभाली थी।
- फ्रांस-ऑस्ट्रिया स्वीडन और फ्रांस के मध्य वेस्टफाली समझौते पर 1648 में हस्ताक्षर हुए थे। जिससे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ईसाइयों की रक्तरंजित लड़ाइयों पर विराम लग गया।
- पोलैंड को 1795 में ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रूस के बीच विभाजित किया गया।
- कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन 1851 में शुरु हुई।
- कैलिफोर्निया के जस्टिस स्टीफन जे फील्ड ने 1861 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन को पहला अंतरमहाद्वीपीय टेलीग्राफ संदेश भेजा।
- अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में 25 हजार महिलाओं ने 1915 में मतदान के अधिकार के लिए प्रदर्शन किया।
- ब्रिटिश विदेश कार्यालय ने 1924 में ज़िनोवी का पत्र प्रकाशित किया।
- द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के एक महीने बाद ही विश्व में शांति कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) की स्थापना 1945 में की गई।
- रॉकेट द्वारा पहली बार 1946 में धरती का अंतरिक्ष से चित्र लिया गया।
- जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी कबाइलियों ने 1947 में हमला किया।
- बर्नार्ड बारूक ने 1948 में सीनेट युद्ध की जांच समिति के समक्ष एक भाषण में पहली बार 'शीत युद्ध' शब्द का इस्तेमाल किया।
- न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की आधारशिला 1949 में रखी गई।
- उत्री रोडेशिया जांबिया गणतंत्र बना कैनेथ कौंडा वहाँ के पहले राष्ट्रपति 1964 में बने थे।
- बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए 1975 में एक अध्यादेश लाया गया और अगले दिन से यह प्रभाव में आ गया।
- सुधा माधवन मैराथन में 1982 को दौड़ने वाली पहली महिला एथलीट बनी।
- कोलकाता में एस्प्लेनेड और भवानीपुर के बीच पहली मेट्रो ट्रेन (भूमिगत ट्रेन) 1984 में शुरु।
- दक्षिण कोरिया द्वारा लम्बी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण न करने की घोषणा 2000 में की।
- नासा के 2001 मार्स ओडिसी अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के चारों ओर कक्षा में प्रवेश किया।
- लंदन में 2003 को आखिरी वाणिज्यिक सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड विमान उतरा।
- ब्राजील ने 2004 को अंतरिक्ष में पहला सफल राकेट परीक्षण किया।
- न्यूजीलैंड-भारत 2005 में नया हवाई सेवा समझौता करने पर सहमत।

विशेष आलेख

राजस्थान की शान दुर्गों का गौरवशाली इतिहास

अनिल माथुर, जोधपुर

राजस्थान, जिसे 'राजाओं का स्थान' कहा जाता है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के दुर्ग न केवल राज्य की सुरक्षा और सामरिक महत्व के प्रतीक हैं, बल्कि ये वीरता, साहस, और राजपूत शौर्य के अद्वितीय उदाहरण हैं। इन दुर्गों का इतिहास सदियों पुराना है, और ये आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आइए राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की विशेषताओं पर नजर डालते हैं-

आमेर का किला (जयपुर)

आमेर का किला अपनी भव्यता और अद्वितीय शिल्पकला के लिए जाना जाता है। यह किला राजा मान सिंह प्रथम द्वारा 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। किले के भीतर शीश महल और दीवान-ए-आम जैसी संरचनाएँ हैं, जो इसकी सुंदरता और वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण हैं।

मेहरानगढ़ किला (जोधपुर)

जोधपुर का मेहरानगढ़ किला राजस्थान के सबसे बड़े और मजबूत किलों में से एक है। यह किला राव जोधा द्वारा 1459 में बनवाया गया था। इसकी ऊँचाई से पूरे जोधपुर शहर का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। किले के भीतर संग्रहालय में राजपूत योद्धाओं के शस्त्र, वस्त्र और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएँ प्रदर्शित हैं।

चित्तौड़गढ़ का किला (चित्तौड़)

चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन किला है, जो 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह किला वीरता और बलिदान की कहानियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ रानी पद्मिनी और रानी कर्णावती जैसी वीरांगनाओं की गाथाएँ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने जौहर का मार्ग अपनाया था। यह किला राजपूत शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक है।

कुंभलगढ़ किला (राजसमंद)

कुंभलगढ़ किला अपनी विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में किया था। यह किला महाराणा प्रताप की जन्मभूमि भी है, जो मेवाड़ के सबसे प्रतिष्ठित राजाओं में से एक थे। किले के आसपास का परिदृश्य और जंगल इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं।

रणथंभौर का किला (सवाई माधोपुर)

रणथंभौर का किला 10वीं शताब्दी में बनवाया गया था और यह अपने वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। यह किला विभिन्न युद्धों का साक्षी रहा है और यहाँ के जंगल में बाघों की उपस्थिति इसे अनूठा बनाती है। पर्यटक किले के साथ-साथ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों को देखने का आनंद भी ले सकते हैं।

जैसलमेर का किला (जैसलमेर)

यह किला अपने सुनहरे रंग के पत्थरों से निर्मित है, जिसके कारण इसे सोनार किला भी कहा जाता है। जैसलमेर का किला थार मरुस्थल के बीच स्थित है और यहाँ की अद्वितीय स्थापत्य शैली इसे विशेष बनाती है। यह किला जैसलमेर के भाटी राजाओं की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है।

राजस्थान के दुर्ग : गौरव और पहचान

इन दुर्गों के निर्माण के पीछे राजपूतों की सुरक्षा व्यवस्था, उनकी साहसिकता और कला प्रेम का विशेष योगदान है। ये दुर्ग न केवल स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण हैं, बल्कि राजस्थान की शान, गौरव और उसकी ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा भी हैं। आज भी ये दुर्ग विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं और लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। राजस्थान के ये दुर्ग न केवल स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि राज्य के गौरवशाली अतीत और संस्कृति को भी जीवंत रखते हैं। ये किले उस समय की वीरता और बलिदान की कहानियों को संजोए हुए हैं, जो हमें राजस्थान के राजाओं और योद्धाओं की अनमोल विरासत की याद दिलाते हैं।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,झुनझुनवा,जिलाई रोक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राम विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन न.0141-2796794,795 रोक कार्यालय-बाईपास जिलाई, रोक फोन न.01432-244881 जिलाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-घोड़ाला सिंह का जोहड़,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल- badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

प्रदूषण पर चिंता

राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, उनके गहरे निहितार्थ हैं। अदालत ने पराली जलाने के मामले में पंजाब और हरियाणा सरकार की आधी-अधूरी कार्रवाइयों पर न केवल गहरी नाराजगी जताई, बल्कि केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण कानून को 'दंतहीन' तक करार दिया। गहराते वायु प्रदूषण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की गंभीरता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि उसने पंजाब और हरियाणा सरकार के जवाबी हलफनामों की विसंगतियों को उजागर करते हुए पंजाब के मुख्य सचिव को गलतबयानी के लिए अवमानना की कार्रवाई तक की चेतावनी दे डाली। अदालत की नाराजगी बिल्कुल जायज है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों की सांसों पर वायु प्रदूषण पिछले कई दिनों से कहर ढा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि बुधवार को राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच गया, जो घातक श्रेणी में आता है। ऐसे में, क्या आश्चर्य कि यहां सांस संबंधी रोगों में 15 फीसदी तक उछाल की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी हैं?

निस्संदेह, राजधानी दिल्ली की आबोहवा की इस हालत के लिए किसी एक सूबे या सरकार को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि पराली दहन के साथ-साथ कई अन्य कारकों का इस प्रदूषण में योगदान है। मगर एक संघ के तौर राज्य सरकारों का रवैया यह सोचने को मजबूर करता है कि काफी हद तक भी देश के किसी इलाके की जान पर भारी साबित होती समस्या को लेकर भी उनका रुख इतना असंवेदनशील क्यों है? इस समस्या को तो कार्यपालिका को आपसी तालमेल और मानवीय आधार पर सुलझाना चाहिए था, जिसमें किसानों के हितों की भी अनदेखी न होती और राजधानी के लोगों को भी राहत मिल पाती, मगर न सिर्फ आला अदालत को इसके लिए हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, बल्कि वहां भी सभी पक्ष कानूनी दांवपेच अपना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उचित ही फटकार लगाई है कि आप जवाब पर जवाब दाखिल करते रहेंगे और यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कोर्ट ने केंद्र से भी पूछा है कि यदि राज्य आपके नोटिस को गंभीरता से नहीं ले रहे, तो आप उनके खिलाफ मुकदमे कायम क्यों नहीं करते? स्पष्ट है, अदालत पराली दहन मामले में सभी पक्षों से असरकारी पहल चाहता है।

अदालत की नाराजगी बिल्कुल जायज है, क्योंकि राजधानी के लोगों की सांसों पर वायु प्रदूषण कहर ढा रहा है और कुछ सूबे कानूनी तिकड़म में उलझे हुए हैं।

प्रदूषण की समस्या से निपटने में शहरी जन-भागीदारी के पहलू को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। राजधानी के लोग इस तथ्य से वाकिफ हैं कि हर वर्ष इन्हीं दिनों में यह समस्या अधिक गंभीर रूप अख्तियार करती है। ऐसे में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों से क्या यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वे इन दिनों में निजी गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें? एनडीएमसी ने मंगलवार को पार्किंग शुल्क दोगुना करने की घोषणा की है, ताकि राजधानी के लोगों की कम दूरी के लिए गाड़ी लेकर निकलने की आदत को हतोत्साहित किया जा सके। यहां के बाशिंदों को समझना होगा कि शहरों को साफ-सुथरा रखने की जितनी जिम्मेदारी सरकारों व स्थानीय निकायों की है, उससे कम दायित्व नागरिकों का नहीं होता। एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान ही यही है कि उसमें सत्ता प्रतिष्ठानों को न्यूनतम बल प्रयोग करना पड़ता है। मगर बढ़ते प्रदूषण सरीखे संकट और पराली दहन जैसे मामले हमें बताते हैं कि सार्वजनिक हितों की कीमत पर निजी लाभ की संस्कृति से छुटकारा पाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की अभी कितनी जरूरत है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 24 अक्तूबर, 1949

राजनीतिक चलचित्र

न्यूयार्क में नेहरूजी का अभूतपूर्व तथा हृदयस्पर्शी स्वागत, भारत के प्रधानमन्त्री का युद्ध की आशंका से त्रस्त मानवता को निर्भयता तथा शांति का अमर संदेश, अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दी के सम्बन्ध में भारत की तटस्थता का पुनः प्रतिपादन, किंतु साथ ही यह स्पष्टीकरण कि स्वतन्त्रता पर आक्रमण होने की स्थिति में भारत चुप न रहेगा, ...संयुक्त राष्ट्र संघ में दृढ़ विश्वास, भारत व अमरीका के सहयोग पर नेहरूजी का जोर, भारत का सुरक्षा-परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया जाना, चीन की साम्यवादी सरकार की स्वीकृति के प्रश्न पर भारत तथा ब्रिटेन द्वारा विचार गत सप्ताह की प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय हलचलें हैं। जहां तक भारतीय राजनीतिक चलचित्र का सम्बन्ध है निष्कान संपत्ति के लिए भारत सरकार का नया आर्डिनेंस, पूर्वी पंजाब में भार्गव मन्त्रिमंडल का गठन तथा भारत की फ्रांसीसी बस्तियों के सम्बन्ध में भारत सरकार के वैदेशिक कार्यालय के प्रवक्ता द्वारा स्वायत्त शासन का स्पष्टीकरण प्रमुख घटनाएं हैं।

वाशिंगटन में नेहरूजी अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़कर न्यूयार्क पहुंचे और वहां से ओटावा चले गये। संयुक्त राज्य अमरीका की राजधानी में नेहरूजी के आगमन को ''पूर्व तथा पश्चिम का ऐतिहासिक मिलन'' बताया गया। न्यूयार्क में अमरीकी जनता, विविध संस्थाओं तथा सरकारी अधिकारियों ने स्वागत समारोहों में भारत के नेता के प्रति जो प्रेम प्रदर्शित किया वह समाचारपत्रों के मुख पृष्ठों पर बड़े-बड़े शीर्षकों व विस्तार से प्रकाशित होकर विलीन नहीं हो गया है।...नेहरूजी ने अमरीका के लोगों को एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया है। न्यूयार्क के सिटी हाल में नेहरूजी का जो भव्य स्वागत हुआ, उस अवसर पर श्री ओडायर ने अपने भाषण में कहा : ''महात्मा गांधी के अनुयायी के रूप में भारत के निवासी इनकी बुलन्द आवाज सुनते आये हैं। आज वह महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी हैं।'' न्यूयार्क में वाल्डर्फ एस्टोरिया में एक बड़े प्रीति-भोज के अवसर पर आमंत्रित महानुभावों को नेहरूजी का परिचय देते हुए श्रीमती रूजवेल्ट ने कहा: ''आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई भय नहीं और जो जीवन को उसके वास्तविक रूप में शांति तथा गम्भीरता से स्वीकार करता है।'' नेहरूजी में व्यावहारिकता तथा आध्यात्मिकता दोनों का सामंजस्य दिखाई दे सकता है।

महाराष्ट्र में वाकई महा मुकाबला

यहां स्कैन करें

जीतेंद्र दीक्षित | वरिष्ठ पत्रकार

यह चुनाव महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी है। कई महारथियों का करियर दांव पर लगा है, उनके लिए चुनावी नतीजे एक अंत भी होंगे और एक नई शुरुआत भी।

महाराष्ट्र में बिसात सज चुकी है। गठबंधनों में सीटों का बंटवारा हो चुका है। कई पार्टियों ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और कई उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस बार के विधानसभा चुनाव पिछले चुनावों से बेहद अलग और दिलचस्प होने जा रहे हैं। कई महारथियों का करियर दांव पर लगा है, उनके लिए चुनावी नतीजे एक अंत भी होंगे और एक नई शुरुआत भी।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दो गठबंधनों के बीच टकराव होने जा रहा है। एक तरफ, सत्ताधारी महायुति है, तो दूसरी तरफ, विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी है। दोनों ही गठबंधनों में एक-एक राष्ट्रीय पार्टी है और दो-दो क्षेत्रीय पार्टियां। इनके अलावा कुछ छोटे दल भी दोनों गठबंधनों के साथ मैदान में हैं। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान महायुति को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। यह गठबंधन राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 19 सीटों पर जीत हासिल कर सका था। लोकसभा चुनाव में चपत लगने के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा थी कि विधानसभा चुनाव के बाद महायुति की सत्ता में वापसी मुश्किल हो सकती है और महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी था, लेकिन बीते चंद दिनों में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए, जिनसे अब टक्कर कांटे की नजर आ रही है।

महाविकास आघाड़ी में फिलहाल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिव सेना और शरद पवार की एनसीपी ने 85-85 सीटों पर लड़ने का एलान किया है। 18 सीटें छोटी पार्टियों के लिए छोड़ने और शेष 15 पर आगे बात जारी रखने की घोषणा की गई है। सत्ताधारी महायुति में भाजपा 155, शिव सेना 80 और एनसीपी 53 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। समस्या यह है कि हर पार्टी से बगावत की आवाज आ रही है।

महाराष्ट्र में मुद्दों की चर्चा करें, तो मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर नतीजों को प्रभावित कर सकता है। लोकसभा चुनाव में महायुति को मराठा समुदाय के गुस्से का खमियाजा भुगतना पड़ा था। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ, उसका मुख्य निशाना भाजपा ही थी। इस बार जरांगे पाटिल के इस एलान ने महायुति के नेताओं की नींद उड़ा दी है कि वे कई सीटों पर मराठा उम्मीदवार उतारेंगे और जहां नहीं उतार सकते, वहां दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। मराठा वोटों के नुकसान से बचने के लिए ओबीसी जातियों को अपने साथ करने का पुरजोर प्रयास महायुति के घटक दल कर रहे हैं।

वैसे तो हरियाणा और महाराष्ट्र की सियासी जटिलताएं अलग-अलग हैं, पर हरियाणा चुनाव के नतीजों का असर महाराष्ट्र में भी नजर आ रहा है। जिस तरह तमाम एग्जिट पोल व अनुमानों में हार की भविष्यवाणी के बावजूद भाजपा हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब रही, उसने महाराष्ट्र में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकी है। जब हरियाणा में वर्चस्व रखने वाली जाट जाति का झुकाव कांग्रेस की तरफ नजर आया, तो भाजपा ने अपना ध्यान बाकी जातियों पर केंद्रित कर दिया, उसी तरह से महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जाति मराठा के विमुख होने पर भाजपा अन्य जातियों का समर्थन पाने की कोशिश कर रही है।

इस चुनाव में लोकलुभावन घोषणाओं का भी बड़ा जोर है। मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की तर्ज पर इसी साल अगस्त में महाराष्ट्र में भी शिंदे सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाली 21 से 65 उम्र की महिलाओं को हर महीने सरकार की तरफ से 1,500 रुपये दिए जाते हैं। अब तक योजना की पात्र महिलाओं को तीन किस्तें मिल भी गई हैं। इसके अलावा महिलाओं को साल में तीन बार मुफ्त गैस सिलेंडर देने का भी एलान है।

चुनाव से ठीक पहले शिंदे सरकार ने मुंबई में प्रवेश पर लिए जाने वाले टोल टैक्स को भी खत्म कर दिया है। सिर्फ भारी वाहनों को टोल टैक्स भरना होगा। सरकार ने गौसेवकों को प्रतिदिन 50 रुपये का भत्ता देने और मदरसा शिक्षकों की वेतन-वृद्धि का भी एलान किया है। गौर करने की बात है कि आम चुनाव में महायुति की हार के पीछे एक बड़ा कारण किसानों का आक्रोश था। चुनाव से ठीक पहले शिंदे सरकार ने 2023 के नुकसान के लिए राहत के तौर पर 4,111 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में इस साल के शुरुआती छह महीनों में 1,267 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हर पार्टी किसानों को लुभाने में लगी है।

महाराष्ट्र में एक खास पहलू यह है कि लोकसभा चुनाव में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति दिखी थी। शरद पवार की पार्टी ने अजीत पवार से दोगुनी सीटें जीती थीं। लोगों को अजित पवार की अपने चाचा शरद पवार से बगावत पसंद नहीं आई। यह देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में शरद पवार के प्रति कैसी सहानुभूति रहती है?

उद्धव ठाकरे का मामला भी शरद पवार की तरह ही है। एनसीपी से एक साल पहले जून 2022 में शिवसेना में बगावत हुई। पार्टी का आधिकारिक नाम और चुनाव चिह्न धनुष-बाण एकनाथ शिंदे को मिल गया। 56 में से 42 विधायक और 12 सांसद शिंदे के साथ चले गए। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने शिंदे वाली शिव सेना से ज्यादा सीटें जीतीं। चुनाव प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे खुद को गद्दारी का शिकार बताकर सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा है, इस चुनाव में तय हो जाएगा कि असली शिवसेना और असली एनसीपी किसकी है।

बड़ी पार्टियों के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी करीब दर्जनभर सीटों पर जोर आजमा रही है। बाबा साहेब आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी भी मैदान में है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे भी 200 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने को तैयार हैं। उनके निशाने पर उद्धव की शिवसेना के उम्मीदवार होंगे।

इस बार महाराष्ट्र में परिवारवाद का विस्तार भी रोचक होगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने वर्ली से चुनाव जीतकर चुनावी राजनीति में कदम रखा था। इस बार राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पदार्पण कर रहे हैं। अजीत पवार के दूसरे बेटे जय पवार और शरद पवार के पोते युगेंद्र पवार मैदान में उतर सकते हैं। तय है, महाराष्ट्र के महा मुकाबले से देश की निगाह नहीं हटेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

उद्योगों से निकलकर अब घरों की शोभा बढ़ाएंगे रोबोट

यहां स्कैन करें

प्रांजल शर्मा | डिजिटल नीति विशेषज्ञ

रेस्तरां में कॉफी बनाते और ड्रिंक डालते रोबोट अब जगह-जगह दिखने लगे हैं। स्वचालित व प्रतिक्रिया देने वाले रोबोट को हवाईअड्डों और मॉल में भी काम करते देखा जा सकता है। कुछ रेस्तरां तो ऐसे भी हैं, जहां रोबोट इस्तेमाल की गई प्लेटों को एकत्र करते हैं और उनको स्साेई में ले जाते हैं। साफ है, तमाम आकार-प्रकार के रोबोट अब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। बावजूद इसके चलते-फिरते इंसानी रोबोट हमारे बीच आज भी आश्चर्य, उत्साह व विस्मयं पैदा करते हैं।

'टेस्ला ऑप्टिमस' ऐसा ही एक रोबोट है, जिसे टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने पिछले दिनों जारी किया है। इसने इंसानी रोबोट के प्रभाव व उपयोगिता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मस्क ने रोजमर्रे के कामों के लिए भी रोबोट बनाने की घोषणा की है। साथ-साथ उन्होंने पूरी तरह से स्वचालित कैब और वैन का भी प्रदर्शन किया, जो बिना स्टीयरिंग के चलेंगी। ये तीनों उत्पाद वैश्विक बाजार में व्यापक खपत को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। वास्तव में, रोबोटिक उत्पादों का बाजार बीते कुछ वर्षों में काफी बढ़ा है। इसमें इंसानी रोबोट की मांग अधिक है। गोल्डमैन सैक्स की 'ह्यूमनॉइड रोबोट : द एआई एक्सेलेरेंट' रिपोर्ट तो यह भी बताती है कि यदि डिजाइन, उपयोग, प्रौद्योगिकी, सामर्थ्य और आम लोगों में स्वीकृति जैसी चुनौतियों से पार पा लिया जाए, तो 2035 तक यह बाजार 154 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।

इंसानी रोबोट के आने के बाद भारत और चीन जैसे युवा आबादी वाले देशों को अपनी श्रम नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है।

इंसान जैसे रोबोट अब कई वजहों से अधिक स्मार्ट, सस्ते व मानवीय बन गए हैं। सबसे बड़ा कारण तो इनमें लगने वाली मशीनों का दाम घटना है। फिर, लगातार सुधरती कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने कहीं अधिक प्रयोग करने की सुविधा दे दी है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल एक इंसानी रोबोट को बनाने में 50 हजार डॉलर से 2.5 लाख डॉलर के बीच खर्च आता था, जो अब घटकर 30 हजार डॉलर से 1.5 लाख डॉलर के बीच हो गया है। लिहाजा आश्चर्य की बात नहीं कि मस्क ने ऑप्टिमस के जल्द ही 20 हजार डॉलर में उपलब्ध होने की घोषणा की है। ये रोबोट घर के कामों में मदद करेंगे, पौधों को पानी देंगे, खाना परोसेंगे और कई दूसरे काम करेंगे। रोबोट अब तक दुकानों और गोदामों तक ही सिमटे रहे हैं। लेकिन घरों में उनका यूं प्रवेश मानव समाज और अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला साबित होगा।

भारत में औद्योगिक रोबोट के इस्तेमाल में 59 फीसदी की वृद्धि हुई है। साल 2023 में 8,510 रोबोट काम कर रहे थे, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के मुताबिक, एक नई ऊंचाई थी। कार-निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं, दोनों ने इसके विकास में योगदान दिया है। स्टैटिस्टा के मुताबिक, भारत में रोबोटिक्स बाजार का राजस्व साल 2024 में 44.67 करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। सबसे ज्यादा जोर सर्विस देने वाले रोबोट पर है, जिससे इस साल 28.15 करोड़ डॉलर का राजस्व आ सकता है। इसकी आमदनी में 8.26 फीसदी की सालाना वृद्धि का अनुमान है, जिसके कारण 2029 तक यह बाजार 66.44 करोड़ डॉलर का हो सकता है। औद्योगिक रोबोट के बाद घरेलू रोबोट भी भारत में लोकप्रिय हो सकता है। ऐसे रोबोट की आमद बढ़ने से भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं और युवा आबादी वाले इन देशों को अपनी श्रम एवं रोजगार नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है।

ये रोबोट खतरनाक व गंदे कामों में फायदेमंद होंगे, हालांकि रचनात्मक लोगों के सामने इनसे चुनौतियां पैदा नहीं होंगी। कुल मिलाकर, इंसानी रोबोट हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से हमारे घरों में प्रवेश कर सकते हैं। भारत और अन्य देशों को इसके लिए तैयार रहना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सुपात्र बनने की साधना

जीवन में आपको समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है कि आप घटनाओं को अत्यधिक महत्व देते हैं। आप छोटे रह जाते हैं और घटनाएं आपसे बड़ी हो जाती हैं। मान लीजिए, आप किसी व्यस्त सड़क पर मोटर साइकिल चला रहे हैं और आपके सामने एक गाड़ी है, जो बहुत धुआं छोड़ रही है। ऐसे में, आपके पास तीन उपाय हैं। एक, आप शिकायत करके, किसी तरह बर्दाश्त करते हुए गाड़ी के पीछे-पीछे चलते रहें। दूसरा, थोड़ी देर रुककर या अपनी गति को धीमी करके उस गाड़ी को दूर आगे निकल जाने दें और तीसरा, कुशलतापूर्वक उस गाड़ी से आगे निकल जाएं और उस घटना को भूल जाएं।

पहले विकल्प की भांति प्रायः हर व्यक्ति घटनाओं में फंसा रहता है और दुखी होता है। दूसरे विकल्प में भी आपको पूर्ण राहत नहीं मिलती, क्योंकि कोई दूसरी बड़ी गाड़ी आपके सामने आ सकती है। इसलिए, ज्ञानी लोग अपनी कुशलता के प्रयोग से घटनाओं से आगे निकल जाते हैं। जब वाहन की अवस्था उत्तम हो, तब आपकी कुशलता प्रभावशाली होती है। साधना और अभ्यास वाहन को सुचारू रूप से चलाते हैं और गुरु-कृपा से कुशलता आती है।

जितने अधिक आप जागृत होते हैं, उसी के अनुसार अपने चारों ओर की घटनाओं या वातावरण से ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। यदि आप जागृत नहीं, तो सबसे कीमती ज्ञान भी अर्थहीन है। जागरूकता, सजगता पर निर्भर करती है। अपनी खिड़कियों को खोलने और बंद करने की आपकी कुशलता पर। जब तूफान हो, तब अपनी खिड़कियों को बंद करने की जरूरत पड़ती है और जब भीतर गर्मी और घुटन हो, तब आपको अपनी खिड़कियों को खोलने की आवश्यकता है।

आपकी इंद्रियां खिड़कियों के समान हैं। जब आप जागृत हैं और इच्छानुसार अपनी खिड़कियों को खोलने और बंद करने की योग्यता रखते हैं, तब आप स्वतंत्र हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप बंधन में हैं। इस पर ध्यान देना ही साधना है, आध्यात्मिक अभ्यास। याद रखिए, यदि आप मिट्टी के कच्चे बर्तन में जल डालते हैं, तो वह पात्र टूट जाता है और जल भी बेकार हो जाता है। यदि पात्र मजबूत है, उसे अच्छे से पकाया गया है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जल को बर्तन में डालो या बर्तन को जल में। साधना आपके पास हुआ पात्र बनाती है।

यदि आप मिट्टी के कच्चे बर्तन में जल डालते हैं, तो पात्र टूट जाता है, जल बेकार हो जाता है। यदि पात्र पकाया गया है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जल को बर्तन में डालो या बर्तन को जल में।

आप ध्यान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि आपका मन चंचल है, तब महसूस कीजिए कि आप थोड़े से बेवकूफ हैं। तब आप गहन ध्यान में डूब सकेंगे। बुद्धि आपकी चेतना का एक छोटा सा अंश है। जब आप खुद को मूर्ख मानते हैं, तब बुद्धि से परे हो जाते हैं।

श्री श्री रविशंकर

निर्मला सीतारमण | केंद्रीय वित्त मंत्री

साल 2047 में जब भारत अपनी आजादी का सौवां साल मनाएगा, तब हमारे पास न सिर्फ अपने नागरिकों, बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए भी समृद्धि के एक नए युग को परिभाषित करने का मौका होगा।

प्रस्तावना के शब्दों से अब कैसा विरोध

देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर हमला करते हुए सन् 1976 के 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है। दरअसल, संविधान की मूल प्रस्तावना में भारत को एक 'संप्रभु' व 'लोकतांत्रिक' गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया था। इन दोनों शब्दों के साथ 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन के माध्यम से 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द भी जोड़े गए थे। अब आपत्ति इसी संशोधन को लेकर की गई है। याचिकाकर्ताओं को शायद अदालत का दरवाजा इसलिए खटखटाना पड़ा है, क्योंकि मौजूदा सरकार के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह संविधान में संशोधन करके 42वें संशोधन को रद्द कर सके। इन्हीं याचिकाकर्ताओं ने जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उस प्रावधान को भी चुनौती दी है, जिसके तहत राजनीतिक दलों को पंजीकृत होने के लिए 'धर्मनिरपेक्षता' को बनाए रखने का वचन देना होता है। इसका मतलब यह है कि याचिकाकर्ता इस देश को एक धर्मी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भारत में सिर्फ एक समुदाय के ही लोग रहें और बाकियों को इसी समुदाय के रहमो-करम पर रहना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने उचित ही सोमवार को कहा कि 'धर्मनिरपेक्षता' और 'समाजवाद' संविधान की मूल विशेषताएं हैं। उसने मौखिक रूप से यह आश्चर्य भी जताया कि क्या प्रस्तावना से इन दो शब्दों को हटाने के लिए कोई न्यायिक निर्देश दिया जाना चाहिए, जैसा कि जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं ने मांग की है। वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के साथ-साथ संविधान की 'बुनियादी विशेषताओं' के रूप में 'धर्मनिरपेक्षता' और 'समाजवाद' को बरकरार रखते हुए पूर्व में कई फैसले दिए हैं। यदि कोई संविधान में प्रयुक्त 'समानता' और 'बंधुत्व' शब्द के साथ भाग तीन (मौलिक अधिकार) के तहत अधिकारों को देखता है, तो स्पष्ट संकेत मिलता है कि धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मुख्य विशेषता माना गया है। लिहाजा आशा करनी चाहिए कि इस याचिका को सर्वोच्च अदालत जल्द खारिज कर देगी।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

खारिज हो मांग

समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना से हटाने संबंधी जो याचिका शीर्ष अदालत में लगाई गई है, उसका मकसद राजनीतिक है। ऐसी याचिका तो पहली नजर में ही खारिज कर दी जानी चाहिए। अलबत्ता, इस पर यदि चर्चा हो रही है, तो याचिकाकर्ताओं को अदालत से फटकार ही मिलेगी।

स्वीकृति, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
प्रस्तावना में संशोधन

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतन्त्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त करने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता

और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए,

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

बाद में जोड़े गए शब्द हटने ही चाहिए

यह सही है कि प्रस्तावना सिर्फ संविधान की आवश्यक विशेषताओं को परिभाषित नहीं करती, बल्कि उन मूलभूत शर्तों की तरफ भी हमारा ध्यान खींचती है, जिनके आधार पर एकीकृत समुदाय बनाने के लिए इसे अपनाया गया था। मगर दिक्कत तब पेश आती है, जब इसमें तथ्यात्मक गलती नजर आती है। मौजूदा विवाद का मूल कारण यही है। प्रस्तावना में जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द अंकित है, उसे साल 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के तहत शामिल किया गया था, लेकिन प्रस्तावना की आखिरी पंक्ति कहती है- अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ईस्वी (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब बताइए जरा, क्या समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1949 में प्रस्तावना का हिस्सा थे, जिसकी गवाही प्रस्तावना की आखिरी पंक्ति दे रही है? कदापि नहीं, यह दर्शाना गलत है कि भारतवासी 26 नवंबर, 1949 को भारत को एक सामाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए सहमत हुए थे। वास्तविकता तो यह है कि इन शब्दों को इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल के दौरान जोड़ा। ऐसे में, अगर इन शब्दों को मूल प्रस्तावना से हटाने की मांग हो रही है, तो इसमें क्या गलत है?

जाहिर है, जिन लोगों को इस याचिका से पेट में दर्द हो रहा है, उसकी वजह यह नहीं है कि वे प्रस्तावना में कथित छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हैं, बल्कि ऐसा विरोध न करने से एक खास राजनीतिक परिवार के प्रति उनके भरोसे को कमतर मान लिया जाएगा और ऐसा वे शायद ही चाहते हैं। यही कारण है कि तथ्यों को जानते हुए भी वे विरोध का राग अलाप रहे हैं, ताकि सामाजिक माहौल को खराब किया जा सके और सत्ताधारी दल पर यह झूठा आरोप लगाया जा सके कि वह धर्मनिरपेक्ष भारत के खिलाफ है। इससे दुनिया भर में भारत की छवि खराब होगी और आलोचकों का पेटदर्द भी ठीक हो जाएगा। ऐसे में, गुनी जनों का यह दायित्व है कि वे सच को सामने लाएं व आंदोलनजीवियों को बेपरदा करें। वास्तव में, प्रस्तावना में संशोधन की याचिका इसलिए भी जरूरी है, ताकि लोगों को सच का पता चल सके। रही बात धर्मनिरपेक्षता या समाजवाद की, तो भारत शुरू से एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसे साबित करने के लिए इसको किसी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। यहां धर्म, जाति, नस्ल आदि के मद्देनजर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, फिर चाहे प्रस्तावना में इसकी चर्चा हो या न हो।

दिवाकर, टिप्पणीकार